खण्ड-131, अंक-5
शुक्रवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(12 मार्च, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 131 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

शुक्रवार, १२ मार्च, १९५४

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इर्तजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवपाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनंदन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाभसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकरशुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशनखन्ना, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त , श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री

रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खाँ, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विश्वनाथ जी के मन्दिर, बनारस में हरिजन प्रवेश में रुकावट

*१—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि तारीख १७ फरवरी, १९५४ को विश्वनाथ मन्दिर में हरिजनों को जाने में जिन लोगों ने रोका उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—१७ फरवरी, १९५४ को बनारस के विश्वनाथ मंदिर में हरिजनों को जाने से रोकने के सम्बन्ध में २७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इन व्यक्तियों के विरुद्ध ताजीरात हिन्द की धारा ३४१, १४३ तथा रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट, १९४७ (Removal of Social Disabilities Act, 1947) की धारा ३ के अन्तर्गत अदालती कार्यवाही की जा रही है। इस समय मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या गृह मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि हरिजनों को विश्वनाथ जी के मन्दिर में प्रवेश करने के सम्बन्ध में वह कौन से विशेष व्यक्ति थे जिन्होंने रोका था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन लोगों के नेता तो थे श्री करपात्री जी।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या सरकार इसके आगे और सोच रही है कि मंदिर प्रवेश, जो हो रहा है और उस मन्दिर का इन्तजाम अपने हाथ में लेने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किसी एक मन्दिर या प्रदेश के जितने मन्दिर हैं उन को सरकार किसी प्रकार से अपने इन्तजाम में ले, यह बिल्कुल निराला प्रश्न है और हरिजनों या किसी और मंदिर प्रवेश से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवमूर्ति शर्मा (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन २७ आदमियों की गिरफ्तारी के बाद जिन लोगों ने आंगन में लेट कर के हरिजनों को मन्दिर में आने से रोका उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिन लोगों ने हरिजनों को रोकने की कोशिश की वह उन २७ के अतिरिक्त भी कोई ऐसे लोग थे, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वनाथ जी के मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी ने भी कोई समाचार-पत्रों में अपना बयान निकलवाया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जब इस क़िस्म का सवाल उठा था तो मैंने कहा था कि इसको हल करना चाहिये और खूबसूरती के साथ हल करना चाहिये।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ़्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री बेचनराम जी एम० एल० ए० को भी मन्दिर में प्रवेश करने से रोका गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो लोग मन्दिर प्रवेश करना चाहते थे, उस दल के नेता श्री बेचन राम जी थे?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस मन्दिर की गत वर्ष की आमदनी क्या थी और क्या सरकार भी उसमें कुछ रुपया देती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—क्या आमदनी है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार तो एक पैसा भी नहीं देती।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि इन २७ आदमियों में कितने लोग अभी जेल में हैं, कितने छूट गये और किस क्लास में हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरा ख्याल है अब सब लोग बाहर जमानत पर छूटे हुये हैं।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—क्या सरकार हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के विषय में कोई अगला कदम उठाने के लिये विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस वक्त हरिजन भाई मन्दिर में प्रवेश करने के लिये गये थे, उस वक्त सरकारी कर्मचारियों ने उनके मन्दिर प्रवेश के मामले में उन्हें पूरी सुविधा दी थी और खुद उनके नेता बेचनराम जी ने कहा है कि वह अधिकारियों के व्यवहार से बहुत संतुष्ट हैं। इसके अलावा भी अगर वह जाना चाहेंगे तो उन्हें मदद दी जायगी।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब क्या परिस्थिति है, अब तो कोई सत्याग्रह या रोक नहीं की जा रही है और अब क्या हरिजनों के जाने में कोई असुविधा नहीं होती?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मैं जानता हूं, उस तारीख के बाद किसी ने जाने की कोशिश नहीं की।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि १८ फरवरी को भी कुछ लोग वहां प्रवेश करने के लिये गये और कुछ लोगों को वहां जमीन पर लेटा हुआ देख कर लौट आये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१८ फरवरी की बाबत कोई मुझे सूचना नहीं मिली है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या जिन लोगों ने हरिजन भाइयों को मन्दिर में जाने से रोका उन्होंने कुछ लिखित आवेदन भेजा है, अगर भेजा है तो वह आवेदन क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरी जानकारी में तो शायद कोई आवेदन उनकी तरफ से सरकार के पास नहीं आया है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो हरिजन भाई मन्दिर के अन्दर जाना चाहते थे, उनमें से कितने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर अन्दर जाना चाहते थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरा ऐसा विश्वास है कि वह सभी लोग धार्मिक भावना से प्रेरित हो कर गये होंगे ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गिरफ्तारी के बाद जो हरिजन मन्दिर में जाना चाहते थे वह जा पाये या नहीं? अगर नहीं तो अधिकारियों ने क्यों उनकी सहायता नहीं की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गिरफ्तारी के बाद किसी ने भी जाने की कोशिश नहीं की और जहां तक मुझे मालूम है, जो लोग उस वक्त मन्दिर में प्रवेश करने के लिये गये थे उनके नेता बेचनराम जी ने जब लोगों को रोकते हुये देखा तो कहा कि जब लोग हमको रोकते हैं तो ठीक है, हम नहीं जायेंगे। हम भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वह इनको सद्बुद्धि दें और जब उनके अन्दर सद्बुद्धि आ जायगी तभी हम प्रवेश करेंगे।

श्री जयपालसिंह (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि विश्वनाथ मन्दिर प्रवेश के लिये मुख्य मंत्री पंत जी तथा कमला पति त्रिपाठी सहित कोई कमेटी बनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे तो कोई पता नहीं है कि कोई कमेटी बनी है।

अलीगढ़ में मुस्लिम जमात का जन्म तथा कन्वेन्शन

*२---श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि गत तीन माह पूर्व अलीगढ़ में पुराने मुस्लिम लीग की संगठन की तरह मुस्लिम जमात नाम की संस्था को जन्म दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को उसके उद्देश्यों की जानकारी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

*३---श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार बतायेगी कि उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुस्लिम कन्वेन्शन के अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल के श्री बद्रूदुजा तथा हमारे प्रदेश के श्री इसहाक़ इल्मी ने साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले भाषण दिये, श्री बद्रूदुजा के लिखित भाषण को बंगाल सरकार ने जब्त कर लिया है और यह भी पता चला है कि बंगाल सरकार ने उनको नजरबन्द कर लिया है। राज्य की सरकार ने श्री इसहाक इल्मी के भाषण को जब्त कर लिया है तथा उनके विरुद्ध १२४ ए तथा १५३ ए आई० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। यह मुकदमा न्यायालय में इस समय विचाराधीन है। सरकार इस संस्था की कार्यवाहियों पर दृष्टि रख रही है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि लीगी मनोवृत्ति के लोग आज भी प्रान्त के अन्दर उसी तरह के संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मुस्लिम लीग करती थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जमाना बदल गया। मुस्लिम लीग जिस परिस्थिति में काम करती थी वह परिस्थिति तो आज है नहीं। इसलिये आज ठीक मुस्लिम लीग के तरीके पर तो काम करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस कंवेंशन में अन्य प्रदेशों के कौन-कौन डेलीगेट्स आये थे और इस प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में कितने आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, न यह सूचना है कि अन्य प्रदेशों में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो कन्वेंशन अलीगढ़ में हुआ था उसमें कांग्रेस के कुछ प्रतिष्ठित लोग भी थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का पता है कि मुसलिम जमात में कुछ गैर मुसलिम लोग भी शामिल हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस कंवेंशन के मौके पर जरूर कुछ गैरमुसलिम बुलाये गये थे। लेकिन मुसलिम जमात में शामिल हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री को इस बात की सूचना है कि प्रादेशिक मंत्रि मंडल के कुछ लोग भी उसमें निमंत्रित किये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई गया नहीं यह मैं जानता हूं। निमंत्रण पाना व्यक्तिगत बात है इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस कंवेंशन में जो नानमुसलिम शरीक हुये थे उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गयी है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—महज किसी जलसे में शरीक होने की वजह से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मुसलिम जमात की कितनी शाखायें प्रान्त में खुली हुई पायी गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तो दो ही तीन महीने हुये इसे चले हुये। शाखाएं कायम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिये पूरी सूचना अभी मेरे पास है भी नहीं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि सी० आई० डी० वालों ने सरकार को जब यह कन्वेंशन हो गया उसके बाद इसकी सूचना दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कन्वेंशन खत्म होने के बाद ही कन्वेंशन के अन्दर जो कार्यवाही हुई उसकी सूचना दी जा सकती थी ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लीगी मनोवृत्ति के हिन्दू लोग दाढ़ी रखाने लगे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने तो अपने किसी उत्तर में "लीगी मनोवृत्ति" शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इसलिये मैं जानता नहीं कि लीगी मनोवृत्ति के कैसे लोग कहे जाते हैं। हां, दाढ़ी रखाये हिन्दू भी देख पड़ते हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसका वहां कोई दफ्तर खुला हुआ है और श्री एम० एन० छोड़ दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, उसका दफ्तर है और बशीर साहब शायद जमानत पर छूटे हैं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग गिरफ्तार हुये हैं उनमें पाकिस्तानी आन्दोलन के जमाने में कितने लोग शामिल रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का पाकिस्तानी आन्दोलन से क्या तात्पर्य है। इसलिये मैं इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे नहीं सकता।

श्री केशव पांडेय---ब्रिटिश राज्य में जिन लोगों ने पाकिस्तान का नारा लगाया था उसमें से कितने आदमी गिरफ्तारशुदा इन व्यक्तियों में सम्मिलित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि जब यह सवाल बार-बार आया कि कुछ लोगों का मुस्लिम लीग से सम्बन्ध था तो ऐसा मानना चाहिये कि जो दो सज्जन गिरफ्तार हुये हैं उन दोनों ने ही किसी न किसी हद तक उस किस्म के आन्दोलन में उस समय हिस्सा लिया होगा।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान से जो लोग परमिट ले कर आये हैं वे लोग इस मीटिंग में सम्मिलित हो कर ऐसे संगठन को कायम करने के लिये प्रेरित करते हैं ? और इस संगठन का नाम क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इन लोगों की प्रेरणा से यह संगठन कायम हुआ यह कहना बड़ा मुश्किल है, इसका कोई खास प्रमाण हमारे पास नहीं है। यह संभव है कि जो लोग वहां से आये हैं वे इस किस्म की संस्था में दिलचस्पी लेते हों।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संगठन किस नाम से पुकारा जाता है और इसके क्या उद्देश्य हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्नों के उत्तर में बताया गया है कि मुस्लिम जमात के नाम से संस्था कायम की गई है और उद्देश्य में यह कहा गया है कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक हक़ों की रक्षा करना।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (जिला झांसी)---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन कन्वेंशन हुआ उसी दिन पाकिस्तान रेडियो ने यह समाचार विस्तृत रूप से प्रसारित किया था और अगर यह सही है तो वह समाचार पाकिस्तान को उसी रोज कैसे भेजा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, पाकिस्तान रेडियो में समाचार आया था और उसमें कोई दिक्कत नहीं है और दुनिया के समाचार छप सकते हैं। कंवेंशन खुले तौर से हुआ था कोई गुप्त रूप से नहीं हुआ था। सभी अखबारों के करेसपांडेंट्स और प्रेस ट्रस्ट इस देश के अन्दर मौजूद हैं और वे आसानी से खबर दे सकते हैं।

हरिजन सहायक विभाग की रिपोर्ट अंग्रेजी में

*४---**श्री बद्रीनारायण मिश्र**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या कारण है जो हरिजन सहायक विभाग की रिपोर्ट अंग्रेजी में छपवाकर विधान सभा के फरवरी, १९५४ के अधिवेशन में बाँटी गयी जब कि राज्य भाषा हिन्दी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)---हरिजन विभाग द्वारा समय समय पर जो भी रिपोर्ट इत्यादि प्रचारित की जाती है उनमें से बहुधा सभी हिंदी में होती हैं परन्तु कभी कभी अंग्रेजी में भी इन रिपोर्टों को छापना पड़ता है क्योंकि बहुधा अन्य प्रान्तों से इस विभाग में ऐसे पत्र प्राप्त होते हैं जिनसे इस प्रान्त में हरिजनों को दी जाने वाली सुविधायें इत्यादि पर सूचनायें मांगी जाती हैं। अन्य प्रान्तों में अभी हिन्दी का इतना प्रचार न होने से अंग्रेजी ही भाषा

में उनकी सूचना दी जा सकती है। अतएव रिपोर्ट को अंग्रेजी में छापने की आवश्यकता हुई। विभाग द्वारा जितनी भी रिपोर्ट इत्यादि प्रचारित होती हैं इन सब की प्रतिलिपियाँ माननीय सदस्यों की सेवा में सदा भेजी जाती हैं। चूंकि एक प्रति अंग्रेजी में छपी थी वह भी वितरण कर दी गयी। हरिजन सहायक विभाग की १९५३-५४ साल की कार्य प्रगति हिन्दी में भी (हरिजन कल्याण) पत्र गणतंत्र अंक में छपी थी जिसकी प्रतियां भी माननीय सदस्यों को बांट दी गईं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या दूसरे प्रान्त के लिये जरूरी है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी में छापा जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह—हाँ, यदि उनका समझना जरूरी है तो अंग्रेजी में छापना भी जरूरी हो जाता है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसका हिन्दी में भी अनुवाद छपा था?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हाँ, यह तो जवाब में दे दिया गया है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या अन्य प्रान्त वाले भी हमारी आवश्यकता को ध्यान में रख कर हिन्दी में रिपोर्टस छपवाते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह प्रश्न तो उन्हीं से पूछा जा सकता है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह रिपोर्ट पुरानी देवनागरी लिपि में थी या नयी देवनागरी लिपि में छपी थी?

श्री हरगोविन्द सिंह—हाँ, पुरानी देवनागरी लिपि में छपी थी।

प्रदेश में छोटे ग्रामों का विलय

*५—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार ४ मार्च के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न ३ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि इस समय इस प्रान्त में गाँवों की कुल संख्या कितनी है और विलीनीकरण के बाद कुल संख्या कितनी रह जायगी?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—इस राज्य में गाँवों की कुल संख्या १,१२,००० के लगभग है। जिस भाग में जमींदारी उन्मूलन हो गया है उसमें लगभग ६७,००० गाँव हैं और विलीनीकरण के बाद इस क्षेत्र में गाँवों की संख्या ६१,००० के लगभग हो जायेगी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी आबादी के गाँव तोड़े जा रहे हैं?

श्री चरण सिंह—२५० से कम आबादी वाले गाँव आगे को नहीं रहेंगे। मानलीजिये कि कोई २४० की आबादी का गाँव है तो उसको पड़ोस के किसी गाँव से मिला दिया जायगा चाहे उसकी आबादी २५० से कम हो या ज्यादा हो। हमारे पास चार जिलों का औसत आ चुका है। उस हिसाब से लगभग ३७॥ प्रतिशत गाँवों का औसत घट जायगा।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय मंत्री महोदय ने पहाड़ी गाँव की बतलाया और मैदानी गाँव की बाबत बतलाया किन्तु बीच के गाँवों को नहीं बतलाया कि उनका क्या होगा?

श्री चरण सिंह—हम मैदानी और पहाड़ी इलाकों के बीच का भेद नहीं मानते हैं इसलिये कोई अन्तर है ही नहीं।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री महोदय, बतलायेंगे कि जो २५० से कम आबादी वाले गाँवों का विलीनीकरण होगा तो उनके नाम का क्या होगा। उनके नाम खत्म कर दिये जायेंगे या नाम अलग ही रहेगा ?

श्री चरण सिंह--मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं। कि उसका नाम उन लोगों की मरजी के अनुसार होगा।

श्री देवमूर्ति राम--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो गाँव दूसरे गाँव में मिलाये जायेंगे वह गाँव वालों की सम्मति से मिलाये जायेंगे या कोई अधिकारी अपनी राय से उनको मिलायेगा।

श्री चरण सिंह--उसको मिलायेगा अधिकारी यह देख कर कि किस गाँव की जमीन का मेल किस गाँव की जमीन का किस गाँव की जमीन से मेल खाता है और किन गाँव वालों का अधिक मेलजोल है क्योंकि आमतौर पर छोटे गाँव वाले और बड़े गाँव वालों के खानदान पुराने एक ही हुआ करते थे। मैं आप की इजाजत से यह बात भी कहना चाहता हूं कि गाँव के मिलाने की बात इसलिये हुई कि नगले पुर्वे हमारे यहाँ बहुत हैं। उनमें ११२ हजार गाँव हैं और २५७ हजार नगले पहले से मौजूद हैं तो अब उन २५७ हजार नगलों की बजाय ३१ हजार गाँव को मिला कर २८८ नगले हो जायंगे और बाकी फर्क नहीं पड़ता।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)--क्या इन गाँवों के मिला देने के लिये फासले पर ख्याल रखा जायगा क्योंकि मकान तो उनके अलग-अलग ही रहेंगे तो अगर वह मिल जायंगे तो फासले का ख्याल रखना होगा ?

श्री चरण सिंह--इन गाँव की जमीन एक दूसरे से मिली हुई होगी बीच में ऐसा नहीं होगा कि एक गाँव घाटमपुर तहसील का और दूसरा बिल्लौर तहसील का।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री पर्वतीय प्रदेश का भी यही खयाल करेंगे ?

श्री चरण सिंह--वहाँ के गाँवों को मिलाने का कोई विचार नहीं है। वहाँ मिलाने में व्यवहारिक रूप से बहुत कठिनाई होगी और न जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट वहाँ है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या गाँवों को मिलाने के सम्बन्ध में फ़ैसला होने के पहले जिले की प्लानिंग कमेटियों से भी विचार विनिमय करने का मौका देंगे ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं, मैं आप की इजाजत से यह भी अर्ज कर दूं कि जो प्रस्ताव गाँवों को मिलाने के अफसरों ने किये हैं उनमें बहुत कम एतराजात हुये हैं। शायद कहीं एक या दो हुये हों। जहाँ जहाँ मैं गया मैंने पूछा तो मुश्किल से १ या २ सुझाव दिये जिसके लिये मैंने कहा कि कलेक्टर साहब से कहो, वह मुनासिब अदला बदली कर देंगे।

श्री गेंदा सिंह--जहाँ के लोगों को एतराज हो वहाँ के लिये अपील का भी बन्दोबस्त माननीय मंत्री जी कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--अपील कलेक्टर को ही हो सकती है।

श्री गेंदा सिंह--क्या वह अपने यहाँ अपील करने का मौक़ा नहीं दे सकते हैं ?

श्री चरण सिंह--जहाँ अपील नहीं होती वहाँ माननीय सदस्य कब चूकते हैं कहने से ? कौन रोकता है ?

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--जो गाँव विलीन किये जावेंगे क्या उनकी आबादी भी हटा दी जयगी ?

श्री चरण सिंह--आबादी तो वहीं रहेगी।

तारांकित प्रश्न

परीक्षा पत्रों तथा उनके उत्तरों का माध्यम

*१--श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहाँपुर)--क्या यह सही है कि इंटरमीडिएट बोर्ड यू० पी० ने कोई सर्कुलर इस आशय का दिया है कि अब को कोई भी परीक्षार्थी इंग्लिश में उत्तर नहीं दे सकता है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जी नहीं।

श्री भगवान सहाय--क्या सेंटर के इम्तिहानों में कामयाब छात्रों की सूची को देखते हुये और उत्तर प्रदेश के लड़कों की संख्या को घटती हुई देखते हुये माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से कोई हाई लेविल पर बातचीत करने का विचार रखते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

श्री भगवान सहाय--उत्तर प्रदेशके लड़कों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी अब इस पर विचार करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, अगर जरूरत समझी जायगी तो जरूर विचार किया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा--उत्तर प्रदेश की हिन्दी राज भाषा होने के कारण क्या माननीय मंत्री जी परीक्षा पत्रों को केवल हिन्दी में ही छापने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, लेकिन अंग्रेजी का पत्र तो हिन्दी में शायद छप नहीं सकता है।

*२--श्री भगवान सहाय--[४ मार्च, १९५४ को प्र० सं० २४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

राजकीय डिग्री कालेजों में प्रिंसपल तथा अध्यापकों के वेतन क्रम

*३--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के राजकीय डिग्री कालेजों में क्या-क्या वेतन क्रम प्रिंसपल्स तथा अन्य स्टाफ के हैं ?

डाक्टर सीताराम--इन डिग्री कालेजों में वेतनक्रम इस प्रकार है:--

डिग्री कालेज कानपुर तथा नैनीताल

प्रिन्सपल ५००-५०-१००० प्र० रो० ५०-१,२०० जोड़, १०० रु० प्रति मास विशेष वेतन।

प्रोफेसर-५००-५०-१,००० प्र० रो० ५०-१,२०० रु०

सहायक प्रोफेसर-२५०-२५-४०० प्र० रो० ३०-७०० प्र० रो० ५०-८५० रु०

रजा डिग्री कालेज, रामपुर

प्रिन्सिपल-२५०-२५-४०० प्र० रो० ३०-७०० प्र० रो० ५०-८५० रु०

सीनियर लेक्चरार-२५०-२५-३७५ प्र० रो० २५-५००।

जूनियर लेक्चरार-२००-१०-२५० प्र० रो० १०-३१० प्र० रो० १४-४५० रु०

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर राज्य के तथा दूसरे डिग्री कालेजों के वेतन क्रम में क्यों फर्क है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--रामपुर स्टेट का जब मर्जर हुआ था तो जो वेतनक्रम उस समय वहाँ लागू थे उनको ही जारी रक्खा गया।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी रामपुर कालेज के प्रोफेसरों और प्रिन्सिपल के वेतनक्रमों को राज्य के दूसरे कालेजों के वेतनक्रम के अनुसार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हाँ इस पर विचार हुआ था लेकिन यही ठीक समझा गया कि फिलहाल वही वेतनक्रम जारी रक्खे जायं जो वहाँ हैं।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल कालेज के प्रिन्सिपल का एप्वाइंटमेंट किस तनख्वाह पर किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--नैनीताल के प्रिन्सिपल को लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो तनख्वाह मिलती थी उसके अलावा डेप्यूटेशन अलाउन्स दिया जाता है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल के प्रिन्सिपल पद के लिये कोई एडवरटिजमेंट किया गया था या यूं ही नियुक्ति कर दी गयी थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--पहले कोई ऐडवर्टिजमेंट नहीं हुआ था, उनको डैप्युटेशन पर बुला लिया गया था, अब पब्लिक सर्विस कमीशन को एडवर्टिजमेंट भेजा गया है।

जौनपुर के थाना केराकत स्थान कटका में डाके से क्षति

*४--**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थान कटका थाना केराकत जिला जौनपुर के अन्तर्गत माह जुलाई सन १९५३ को जो डाका पड़ा उसमें कितने की क्षति हुई और कितने व्यक्ति जान से मारे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--४,०९९ रुपये की क्षति हुई और १ व्यक्ति मारा गया।

*५--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाका उसी समय पड़ा जब कि पुलिस वहाँ गश्त में गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक पुलिस द्वारा इस डाके के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चन्द्र बली, महाबली, रामनारायण सिंह और राम सरन इस संबंध में गिरफ्तार हुये हैं। पाँचवाँ आदमी विश्राम अभी फरार है।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति मारे गये हैं वे किस हथियार से मारे गये हैं और कितने लोग घायल हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चन्द्रबली के छुरे से ठाकुर दास शाह, जिनके घर डाका पड़ा था, मारे गये। ८ आदमी और घायल हुये जिनके छुरे के निशान थे।

श्री बाबू नन्दन--डाका किस समय पड़ा था और कितने आदमियों ने डाकुओं का मुकाबला किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--६ और ७ के बीच में डाका पड़ा था। मुकाबला करने वालों में एक ठाकुरदास शाह खुद थे तथा गाँव के कुछ लोग और आ गये थे, उनके नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में डाकुओं का एक गिरोह है जो समय-समय पर उत्पात मचाया करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य उनके नाम बता देंगे तो मैं उनका आभारी हूंगा ।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनमें से कुछ हरिजन भी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है ।

शिक्षा की किण्डर गार्टन प्रणाली को प्रोत्साहन

*६—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या म्युनिसिपल अथवा देहाती क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों में किन्डरगार्टन शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

*७—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह किंडरगार्टन फैक्टरी, महरागाँव, जिला नैनीताल को कितनी सहायता प्रदान करती है ?

डाक्टर सीताराम—कुछ नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार किंडरगार्टन प्रणाली को भविष्य में तरक्की देने के लिये विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—इस प्रणाली से प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उससे नीची अवस्था के बच्चे पढ़ाये जाते हैं । इसलिये सरकार उससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन फिर भी सरकार उसकी महत्ता को समझती है और उसके प्रोत्साहन के लिये रुपया भी दिया जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने किंडरगार्टन फैक्टरी, महरागाँव को कभी कोई सहायता दी ?

डाक्टर सीताराम—जी हाँ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—यह सहायता कब और कितनी दी गयी ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९४६-४७ में २५० रुपये और सन् १९४७-४८ में ५०० रुपये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस संस्था को भी भविष्य में सहायता देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इस पर विचार किया जायगा ।

राजकीय देवसिंह विष्ट डिग्री कालेज नैनीतालके कर्मचारियों के हिल एलाउन्स की दर

*८—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को मालूम है कि राजकीय देव सिंह विष्ट डिगरी कालेज नैनीताल में सन् १९५१, के जी० ओ० निकलने के पहले से नियुक्त व तदुपरान्त स्थानान्तरित कर्मचारियों को हिल एलाउन्स नहीं दिया जाता है ? अगर हाँ, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—(क) दिया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस हिल एलाउन्स की दर क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—निर्धारित दर जो और विभागों में दी जाती है।

गोरखपुर के थाने और पुलिस चौकियों में रोशनी पर व्यय

*९—**श्री केशव पाण्डेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर पुलिस विभाग को थाने या चौकियों में रोशनी के निमित्त आठ आना माहवारी खर्च दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गोरखपुर जिले में केवल बेलघाट थाना आठ आना प्रति माह रोशनी के निमित्त पाता है । अन्य थाने केवल कोतवाली को छोड़ कर जहाँ बिजली है, बारह आना प्रतिमाह पाते हैं।

*१०—**श्री केशव पाण्डेय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील खजानों पर पुलिस को रोशनी का खर्च दो पैसा प्रति मास दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*११—**श्री केशव पाण्डेय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त रकम की कमी को पूरा करने के लिये विभागीय माँग आयी थी ? यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री केशव पाण्डेय—जिस थाने में बिजली नहीं है उसमें कितनी लालटेनें हैं और कितनी देर तक जलाई जाती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ?

श्री केशव पाण्डेय—बेलवाट थाने में कितनी लालटेनें हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो माननीय सदस्य ने पूछा नहीं था। अगर पूछा होता तो मैं सूचना एकत्रित कर रखता । इस वक्त इसकी सूचना नहीं है।

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी आठ आना प्रति मास थाने में लालटेनों के जलाने के लिये कम धन समझते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसको बहुत कम समझता हूं । लेकिन जब मैंने इस सवाल को देखा तभी से इस मामले को पूछ ताँछ की है कि इस मामले में आवश्यक सुधार होना चाहिये।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी गोरखपुर शहर में जो केन्टूनमेंट के थाने हैं और जहाँ बिजली पर्याप्त है उनमें बिजली का प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो मैं नहीं कह सकता कि किन थानों में बिजली का प्रबन्ध हो सकता है, लेकिन इन प्रश्नों के जरिये से और बजट डिस्कशन के समय माननीय भगवान सहाय ने जिक्र किया था कि कुछ थानों में बिजली की रोशनी नहीं है और रोशनी के लिये कम पैसा मिलता है उसकी वजह से मेरा ध्यान इस ओर गया है कि सारे प्रदेश के सभी थानों में रोशनी का प्रबन्ध किया जाय ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या इसी हिसाब से दूसरे जिलों के थानों को रोशनी के लिये दिया जाता है या अधिक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सवाल तो केवल एक थाने का था और मुझे इस समय तो सारे सूबे की इत्तिला इस सम्बन्ध में तो है नहीं लेकिन मैंने अभी निवेदन किया है कि सारे सूबे के लिये इस प्रश्न पर देखा जा रहा है, कि प्रबन्ध हो जाय।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील खजाने में पुलिस को रोशनी के लिये कितना मासिक खर्चा दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस में दो पैसा प्रति माह लिखा है, लेकिन दिया जाता है दो पैसा प्रति दिन ।

देवरिया जिले में चोरी डकैती, कत्ल व बलवे

*१२—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिला में पिछले तीन महीनों में कितनी चोरी, कितनी डकैती, कितने कत्ल और कितने बलवे हुये हैं उनमें से कितने मुकदमें अदालत में चल रहे हैं और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है ? गत वर्ष इसी अवधि में उपरोक्त अपराधों की क्या संख्या थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२५ पर)

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी ने इस नकशे में जो आंकड़े दिये गये हैं उन्हें देख लिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, अपनी समझ में देख जरूर लिया है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १-१२-५३ से २८-२-५४ की १४४ चोरियों में ७४ चोरियों का पता नहीं है, उन पर फाइनल रिपोर्ट भी नहीं लगी, क्या इसी तरह से दूसरे अपराधों की भी हालत है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य ने जिस रूप में प्रश्न पूछा था, उसी रूप में मजबूर हो कर उत्तर देना पड़ा । यह प्रश्न पहले साल की बाबत पैदा हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कई मुकदमे पहले साल के जो थे वह २८ फरवरी तक खत्म नहीं हुये, उनका ब्योरा मेरे पास है। चूंकि पूछा नहीं गया इसलिये मैं जबाब नहीं दे सका। इसी तरह से जो मुकदमें २८ फरवरी तक नहीं हुये या फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी उनपर २८ फरवरी के बाद या तो फाइनल रिपोर्ट लगी, मुकदमा चलाया गया या जांच हुई ।

श्री गेंदा सिंह—माननीय गृह मन्त्री जी चोरियों के संबंध में अपनी राय दे रहे हैं वही राय क्या सभी संख्याओं के लिये है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हां, चोरी के अलावा डकैती में भी ऐसी ही है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या इस अवधि में देवरिया शहर में जो दो डकैतियां हुई थीं, एक शान्ति प्रसाद दुबे और एक आंख वाले डाक्टर के घर पर वह भी इसमें शामिल हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गेंदा सिंह—जो सूचना हमें दी गई है, उसमें देवरिया शहर की कोई डकैती शामिल है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी बाबत मैं ठीक नहीं कह सकता क्योंकि देवरिया जिले का सवाल था उसमें शहर भी शामिल है ऐसा मैं ठीक नहीं कह सकता ।

गोरखपुर निचलौल थाना के दरोगा का स्थानान्तरण

*१३--श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि निचलौल थाना तहसील महाराजगंज जिला गोरखपुर के दरोगा एवं नायब दरोगा का स्थानान्तरण एक ही साथ किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, इन्तिजामी कारणों से ।

शाहगंज जिला जौनपुर चीनी मिल के गन्दे पानी को सिंचाई के उपयोग में लाने की व्यवस्था

*१४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शाहगंज जिला जौनपुर, चीनी मिल का गन्दा पानी चारों तरफ फैलकर बदबू पैदा करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां,। इस प्रकार की शिकायत है ।

*१५--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या श्रम मन्त्री मिल मालिक से गन्दे पानी को एक गड्ढे में रोकवाकर सिंचाई या खाद बनाने के काम में लाने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रदेश की अन्य मिलों के साथ-साथ इस मिल के गन्दे पानी के खाद-गुणों की जांच करने तथा उसको सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था पर (Factory Effeuents Enquiry Commitee) की सिफारिशों के अनुसार विचार हो रहा है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यह योजना कब तक विचाराधीन रहेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस महीने में लेबर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गवर्नमेंट की जो कुछ राय है वह पेश की जायगी इसलिये मैं समझता हूं कि लेबर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद ही और कोई कदम उठेगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार तब तक इन मिलों के पानी को बढ़ाव से रोकने और इकट्ठा करवाने का प्रबन्ध करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, ३१ दिन का महीना है और आज १२ तारीख हो गई है इस लिये १९ दिन के अन्दर क्या प्रबन्ध किया जा सकता है ? लेबर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग तक तो रुकना ही पड़ेगा ।

गौहरपुर सत्याग्रह में गिरफ्तार लोगों को जेल की श्रेणी का विभाजन

*१६--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि गौहरपुर (आजमगढ़) के सत्याग्रह के सिलसिले में जो लोग गिरफ्तार हैं उनको जेल में किस श्रेणी में रक्खा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गौहरपुर सत्याग्रह में भाग लेने के फलस्वरूप गिरफ्तार किए गए लोगों में से दो आदमियों को सुपीरियर क्लास में और शेष को आर्डिनरी क्लास में रखा गया है ।

श्री उमाशंकर--क्या गृह मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस गांव से कितने सत्याग्रही जेल भेजे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--४७ ।

श्री उमाशंकर--क्या सत्याग्रहियों पर मौके पर मार भी पड़ी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें तो उनके लिये जेल में सुपीरियर क्लास की बात थी। मार की बाबत दरियाफ्त करना हो, तो उसकी बाबत अलग प्रश्न पूछना चाहिये तब ही मैं जवाब दे सकूंगा।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गौहरपुर सत्याग्रह में कुल कितने आदमी गिरफ्तार किये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने अभी बतलाया कि सत्याग्रह में ४७ आदमी गिरफ्तार हुये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि सत्याग्रह के अलावा और भी ११५, और १५१ आदि दफाओं में कुछ आदमी गिरफ्तार हुये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सत्याग्रह के अलावा दूसरी दफाओं में उस जगह मेरी सूचना के अनुसार ५ आदमी और गिरफ्तार हुये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दो सज्जनों को उच्च श्रेणी में रखा गया था वे कौन-कौन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री गोपाल नारायण सक्सेना और राम कुंवर सिंह।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री जी उन लोगों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जिन्होंने सत्याग्रह किया और गिरफ्तार नहीं किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त तो उनकी सूचना मेरे पास है नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गौहरपुर सत्याग्रह में जिन लोगों को सजायें हुईं क्या वे सब लोग रिहा कर दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न के सम्बन्ध में तो मैंने यह सूचना मंगाई नहीं। कोई और प्रश्न पूछा जाय तो मैं सूचना मंगवा सकता हूं।

महाराजगंज जिला आजमगढ़ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर शांति भंग के मुकदमें

*१७—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं पर शान्ति भंग करने के मुकदमें चल रहे हैं और कहां-कहां शान्ति भंग हुई है जिसमें उक्त कार्यकर्ताओं का हाथ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानून तोड़ने के अपराध में जो व्यक्ति पकड़े जाते हैं या जिन पर मुकदमा चलाया जाता है उनके बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं रखी जाती, जिससे कि यह पता चले सके कि वे व्यक्ति किस राजनैतिक दल से सम्बन्धित हैं।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कुल कितने लोगों पर शांति भंग करने का मुकदमा चलाया गया या चल रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अलग-अलग मामलों पर मुकदमा चला था। मिश्रालग एक मामला हुआ था जिसमें १०७ की कार्यवाही २१ आदमियों पर की गयी थी। इसका तो कुछ

ब्योरा मेरे पास है । उसके अलावा एक और मामला था जिसमें १४ आदमियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था । एक और तीसरा मामला था जिसमें १० आदमियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था । इस तरह से जोड़कर ४५ आदमियों की सूचना मेरे पास है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि उमाशंकर जी ने अपने प्रश्न संख्या १७ में निश्चितरूप से यह सूचना मांगी थी कि उन लोगों में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं जिन पर शांति भंग करने का मुकदमा चलाया गया था, तो माननीय मंत्री जी ने यह आंकड़ें क्यों नहीं इकट्ठा किये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि सरकार के लिये यह उचित नहीं होगा कि जेल में जा करके प्रत्येक आदमी से यह पूछा जाय कि तम्हारा किस राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध है ।

श्री उमाशंकर---क्या १०७/११७ के अनुसार चलने वाले मुकदमों में अक्सर दो पार्टियां रहती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, प्रायः रहती तो हैं ।

श्री राजनारायण---माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बताया कि जेल में जा करके यह पूछना कि आपका किस राजनीतिक दल से सम्बन्ध है, उचित नहीं है. तो क्या सरकारी कर्मचारी यदि जेल में किसी से पूछें कि आपका किस राजनीतिक दल से सम्बन्ध है, तो उनको कोई दंड सरकार देगी ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो शर्तिया सवाल आप पूछ रहे हैं । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बग़ैर कानून को भंग किये भी लोगों के ऊपर मुकदमा चलता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, कभी कभी इस बात की आशंका होती है कि फ़लां साहब क़ानून भंग करेंगे तो भी मुकदमा चलने की नौबत आ जाती है ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शान्ति भंग करने के अपराध में जो आदमी जेल गये थे उनमें से कितने आदमियों ने माफ़ी मांग ली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त तो इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि सरकार के पास इस तरह की तालिकायें जिलों में या प्रदेश में रखी जाती हैं कि कौन-कौन लोग किस राजनीतिक दल से सम्बन्धित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार के पास बहुत सी किस्म की सूचनायें रहा करती हैं लेकिन उन सब की ब्योरेवार यहां चर्चा करना शायद मुनासिब नहीं होगा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ में जो सत्याग्रह चला था उसमें उत्तर प्रदेश की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन, श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने अगुवाई की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री गोपाल नारायण सक्सेना को सुपीरियर क्लास दिया गया था, इसका मैंने ज़िक्र तो किया ।

श्री उमाशंकर---क्या यह सही है कि १०७/११७ के अनुसार चलने वाले मुक़दमे में बहुत से पुलिस द्वारा घोषित अपराधियों को दोनों पार्टियों ने अदालत से कहा कि हम इनको नहीं जानते ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उपाध्यक्ष महोदय, अब इस बात का निर्णय तो आप ही कर सकते हैं कि यह सवाल इससे उठता है या नहीं । बहरहाल इस सवाल के सम्बन्ध में इस क़िस्म की सूचना तो मैंने मंगवाई नहीं ।

आजमगढ़ के थाना मधुबन में बन्द सत्याग्रहियों पर मार

*१८---श्री उमाशंकर---क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ थाना मधुबन में बन्द करके सत्याग्रहियों के मारने की कोई सूचना उन्हें मिली थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । परगना हाकिम, घोसी ने इस सम्बन्ध में जांच की ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परगना हाकिम घोसी ने इन दरख्वास्तों की जांच कब की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उन्होंने १४ अक्तूबर से लेकर १६ अक्तूबर तक जांच की ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मंत्री जी को पता है कि इन दरख्वास्तों की जांच जिलाधीश आजमगढ़ ने २४ अगस्त को की थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सम्भव है किया हो । इसकी मुझे इत्तिला नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि दोनों अधिकारियों की जांच में किस अधिकारी की जांच को वह सत्य मानते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो घोसी के परगना हाकिम ने जांच की उस रिपोर्ट को जिला मैजिस्ट्रेट ने हमारे पास भेजा है यह कह कर कि असली वाक्या यह है । इसलिये ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि दोनों अफ़सरों ने जो जांच की उसमें दो अलग-अलग बातें हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि जिन किसानों ने दरख्वास्त दी थी उन से इन दरख्वास्तों के सम्बन्ध में कोई जांच परगना हाकिम ने नहीं की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---परगना हाकिम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मैं पांच दिन तक बराबर उन जगहों में रहा और सब से बात चीत की और लोगों से पूछा । इसके अलावा वह यह भी लिखते हैं कि जिस दिन घटना हुई उस दिन वह खुद २ बजे से लेकर शाम को ७ बजे तक थाने में मौजूद थे और उसी मौके पर मौजूद थे जहां सत्याग्रह हो रहा था । इसलिये सत्याग्रह में जो कुछ हुआ उसमें से बहुत सी बातें उन्होंने अपनी आंखों देखी । यह उन्होंने जिक्र किया है ।

गोंडा के थाना वजीरगंज ग्राम मझगंवा के निवासियों द्वारा जिलाधीश के पास शराबी गुन्डों के उत्पात के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*१९---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा थाना वजीरगंज ग्राम मझगंवा बाजार के निवासी तथा पास-पड़ोस के निवासियों ने श्री मान् जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि उपर्युक्त

बाजार से शराब की दूकान हटा दी जाय जो रात दिन खुली रहती है और जिससे बाजार में शराबी गुन्डों का उत्पात दिन-प्रति दिन बढ़ता जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को प्राप्त हुआ था । जांच करने से शराब की दूकान के ठेकादार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली । इस कारण दूकान को बन्द करना उचित नहीं समझा गया ।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस अधिकारी द्वारा जांच हुई और किस तारीख को हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस में जो जिला मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट भेजी है उसमें यह नहीं लिखा है कि किस तारीख को और किस के जरिये जांच की गई । उन्होंने रिपोर्ट को ठीक मानकर यहां भेजा है ।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि ठेकेदार का लड़का चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ और उसकी दुकान पर उन लोगों का अड्डा बना हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सही है कि ठेकेदार का लड़का चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ, लेकिन वहां पर गुंडों का जमघट होता है यह साबित नहीं होता है । लेकिन दो चार आदमी जो थे वे उनके मित्र होंगे, उनके ऊपर दूकानदार के पैसे बकाया थे उसके संबंध में झगड़ा हुआ था ।

श्री गंगाप्रसाद--क्या यह सत्य है कि पुलिस कप्तान ने गारद भेजकर गुंडों के उत्पात को रोकने की कोशिश की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, जब झगड़ा हुआ तो पुलिस की ड्यूटी थी कि झगड़े को रोकने की कोशिश करती ।

पिछड़ी हुई जातियों को सुविधाएं

*२०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछड़ी हुई जातियों के लिये क्या-क्या सुविधायें सरकार की तरफ़ से दी जाती हैं ?

डाक्टर सीताराम--पिछड़ी जातियों को जो सुविधायें दी जाती है उनका विवरण संलग्न पत्र में दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२६ पर ।)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी के लिये ध्यान रखा जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सभी नौकरियों के लिये जो प्रांतीय सरकार के अन्तर्गत हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उनका ध्यान रखा जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी जो सुविधायें दी जाती हैं और जो सूची में संलग्न है उनका सारांश बता देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मेरा ख्याल है कि अगर माननीय सदस्य इसको पढ़ेंगे तो उनकी समझ में आ जायगा ।

श्री गेंदासिंह---जो संलग्न सूची दी गई है वह सभी सदस्यों के पास है भी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---यदि छोटा विवरण हो तो पढ़ दें ।

(विवरण नहीं पढ़ा गया ।)

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी हुई जातियों को सरकारी नौकरियों के देने के संबंध में क्या नीति निर्धारित है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बैकवर्ड क्लासेज के लिये कुछ भी नहीं ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को पिछड़े हुए वर्ग की सूची भी नहीं मालूम है कि कौन-कौन से उसमें शामिल हैं ।

डाक्टर सीताराम---सब को मालूम है । सबके पास जी० ओ० भेज दिया गया है ।

गांवों में ग्राम रक्षक दल की स्थापना

*२१---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार यह बतायेगी कि ग्राम रक्षा के लिये यू० पी० में कोई नवीन योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस प्रदेश के प्रत्येक बड़े गांव में पुलिस की देख-रेख में ग्राम रक्षक दल (Village defence Societies) स्थापित की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त और कोई नवीन योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय बिल

*२२---श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर विश्व-विद्यालय बिल यह कब तक विधान सभा में विचार करने के लिये ला रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की है जिसकी आख्या की प्रतीक्षा की जा रही है । आख्या प्राप्त होने पर इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा ।

थाना लार जिला देवरिया में डकैतियों की संख्या

*२३---श्री बद्रीनारायण मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लार थाना (जिला देवरिया) में जुलाई माह से अभी तक कितनी डकैतियां हुईं और उनमें से कितनों की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जुलाई, १९५३ से फरवरी, १९५४ तक कोई डकैती नहीं हुई । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों की आमदनी व व्यय

*२४--श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह यह जानने का विचार कर रही है कि किस सरकारी कर्मचारी की कितनी आमदनी है और वह कितना खर्चा कर रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की आमदनी और उसके खर्च की जांच कराने का सरकार का इस समय कोई विचार नहीं है ।

उत्तर प्रदेश किसान सभा का स्मृति पत्र

*२५--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर-प्रदेश किसान सभा की ओर से जो प्रतिनिधि मंडल गत १९ और २० जुलाई को गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री से मिला था और उसने जो स्मृति-पत्र दिया था उस पर क्या कार्यवाही सरकार की ओर से की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--स्मृति-पत्र में दिये गये आरोपों पर सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा जांच कराई गई और वे निराधार पाये गये ।

आगरा जेल में नजरबन्द कम्युनिस्टों के परिवारों को सहायता

*२६--श्री झारखंडे राय--क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि आगरा जेल में नजरबन्द कम्युनिस्ट बन्दियों के परिवारों को कितनी सहायता दी जाती है ? क्या उस सहायता को बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय आगरा जेल में कोई कम्युनिस्ट नजरबन्द नहीं है इसलिये सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बन्दी कामरेड भगवान सिंह (जिला गाजीपुर) का प्रार्थना-पत्र

*२७--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि जिला बरेली सेन्ट्रल जेल से कम्युनिस्ट बन्दी कामरेड भगवान सिंह (जिला गाजीपुर) ने जो प्रार्थना पत्र मुख्य मन्त्री जी की सेवा में २७-९-५२, २७-११-५२ और ६-१-५३ को भेजे हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बरेली सेन्ट्रल जेल के कैदी भगवान सिंह तथा दो और कैदियों ने दिनांक २७ दिसम्बर, १९५२ को एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र सुपरिन्टेंडेंट जेल द्वारा मुख्य मन्त्री के नाम भेजा था और वह सरकार को प्राप्त हुआ था । उस पत्र में की गयी शिकायतें जांच करने पर गलत पायी गयीं । भगवान सिंह ने तारीख २७ नवम्बर, १९५२ और ६ जनवरी, १९५३ को कोई प्रार्थना पत्र सुपरिन्टेंडेंट जेल को नहीं दिये, और न इन तारीखों के प्रार्थना-पत्र सरकार को ही मिले ।

*२८-३०--श्री नेकराम शर्मा--[२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध विद्यार्थियों की शिकायत

*३१--श्री लक्ष्मण राव क़दम (जिला झांसी)--क्या सरकार के पास इस प्रकार के विद्यार्थियों की शिकायतें आयी हैं जो समय पर प्रार्थना-पत्र व फीस आदि दाखिल करने पर भी

हाई स्कूल की परीक्षा में केवल इस लिए शामिल नहीं हो सके कि उनके प्रार्थना-पत्र स्थानीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षा बोर्ड के पास भेजने से रह गये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां। ऐसी कुछ शिकायतें बोर्ड के कार्यालय में आयी हैं।

गन्ना आन्दोलन के सिलसिले में देवरिया जिले में गिरफ्तार लोगों पर मुकदमे

३२—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला में श्री गेंदा सिंह, सदस्य विधान सभा, राजबंशी राय, सदस्य विधान सभा, पारस नाथ श्रीवास्तव, श्री आनन्देश्वर सिंह प्रभृति अन्य लोग, जो गन्ना आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए, जेल में बन्द हैं, उन जेल बन्दियों पर कब तक मुकदमा प्रारम्भ हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—७ फरवरी, सन् १९५४ को गिरफ्तार किये गये कुल १७ व्यक्ति, जिनमें कि सर्वश्री गेंदा सिंह व राजवंशी राय भी शामिल हैं, २७ तारीख को अदालत से जमानत मुचलका पर छोड़ दिये गये हैं ? अभी इन लोगों के मामले में जाँच हो रही है, और आशा है कि मामला शीघ्र अदालत भेज दिया जावेगा।

उत्तर प्रदेश में सैन्य शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या

*३३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी सैन्य शिक्षा N. C. C. Training पा रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों में सीनियर डिवीजन एन० सी० सी० है जिस के कैडेटों की संख्या ३,२६४ है।

*३४—श्री व्रजभूषण मिश्र—प्रत्येक विद्यालय में कितने N. C. C. आफिसर ट्रेनिंग के निरीक्षण के लिए नियुक्त किये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कुल संख्या विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत ९२ तथा अन्य विद्यालयों में १२२ है।

*३५—श्री व्रजभूषण मिश्र—N. C. C. Act द्वारा निर्धारित अलाउन्स कितने अफसरों को मिल रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सभी को।

*३६—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[९ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]।

*३७—श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)—[२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*३८-४०—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२ अप्रैल, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

प्रदेश में असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासिक्यूटर्स का चुनाव

*४१—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या गृह मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे असिस्टेंट पब्लिक प्रासिक्युटर्स हैं जिनको सेलेक्शन बोर्ड ने ट्रेनिंग के लिए नहीं चुना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—६

बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट कमेटी के नाम निर्देशित सदस्यों की सूची

*४२—श्री रामनारायण त्रिपाटी—क्या गृह मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ ट्रस्ट कमेटी के लिए किन-किन सदस्यों को इस वर्ष नामजद किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी के लिए जो श्री केदारनाथ मन्दिर की भी देख रेख करती है, निम्नाँकित व्यक्ति नामजद किये गये हैं :—

(१) श्री सत्य सिंह राणा । (२) श्री बी० डी० उनियाल ।	टेहरी गढ़वाल के महाराजा द्वारा ।
(३) श्री श्रीनिवास जोशी, रिटायर्ड हेडमास्टर, बागेश्वर, अल्मोड़ा । (४) श्री गोपाल शास्त्री, दर्शन केसरी, काशी विद्यापीठ, बनारस ।	राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा ।
(५) श्री तिरमल सिंह, भूतपूर्व एम० एल० ए०, टेहरी गढ़वाल । (६) श्री उमानन्द दंगवाल, एम० ए०, एल० एल० बी० टेहरी गढ़वाल ।	उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा, टेहरी गढ़वाल के दो सदस्यों के रिक्त स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ मन्दिर ऐक्ट, की उपधारा ५ (१) (अ) के द्वारा भरे जाने चाहिए ।

मथुरा जिले के करसारा गांव में गिरजाघर तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार लोग

*४३—श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—क्या यह सही है कि मथुरा जिले के करसारा गाँव में इसाइयों के गिरजाघर को तोड़-फोड़ के कथित आरोप में हाल ही मे पुलिस ने कई सज्जनों को गिरफ्तार किया है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ ।

जिला मैनपुरी में विद्यालयों को भवन निर्माणार्थ सहायता

*४४—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मैनपुरी में भवन निर्माण के लिए सहायता पाये हुए सभी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन बन चुके हैं ?

*४५—क्या सरकार बतायेगी कि गत ५ सालों में सरकार ने उपर्युक्त किन-किन विद्यालयों को भवन निर्माणार्थ कितनी-कितनी सहायता दी है ?

डाक्टर सीताराम—जी हाँ ।

विद्यालय का नाम	वर्ष	स्वीकृत धन
		रु०
१—ए० के० हायर सेकेन्डरी स्कूल, शिकोहाबाद, मैनपुरी, ..	४७–४८	
	४८–४९	
	४९–५०	
	५०–५१	
	५१–५२	१,०००
	५२–५३	
	५३–५४	
२—लोधी राजपूत हायर सेकेन्डरी स्कूल, जसराना, मैनपुरी । ..	४७–४८	
	४८–४९	
	४९–५०	
	५०–५१	
	५१–५२	१,०००
	५३–५४	
३—तिवारी ज्वाला कन्या पाठशाला, मैनपुरी ..	४७–४८	
	४८–४९	
	४९–५०	
	५०–५१	
	५१–५२	१,०००
	५२–५३	
	५३–५४	

मधुबन थाना, जिला आजमगढ़ में जनवरी, १९५४ में डकैतियों और चोरियों की संख्या

*४३—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन थाना, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत गत जनवरी मास में कितनी डकैतियां और चोरियां हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डकैती कोई नहीं हुई। चोरी की ७ घटनायें हुईं।

अतारांकित प्रश्न

विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद और शिक्षा उप-संचालक बरेली द्वारा गवर्नमेंट हाई स्कूल में इण्टर साइन्स खोलने की सिफारिश

१—**श्री मुहम्मद तकी हादी** (जिला मुरादाबाद)—क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद और उप-शिक्षा संचालक बरेली ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में साइन्स खोलने के लिए सिफारिश की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

अमरोहा में साइन्स स्कूलों की कमी

२—**श्री मुहम्मद तकी हादी**—क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि अमरोहा, जिसकी जन-संख्या ६५,००० है के किसी एक स्कूल में भी प्योर साइन्स नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

माडल उद्योगशाला हायर सेकण्डरी स्कूल कानपुर के रिफ्यूजी व अछूत विद्यार्थियों से सम्बद्ध रिपोर्ट

३—**श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या सरकार माडल उद्योगशाला हायर सेकेन्डरी स्कूल, कानपुर के रिफ्यूजी व अछूत (शेडयूल्ड कास्ट) विद्यार्थियों से सम्बन्धित शिकायतों पर जिला शिक्षा निरीक्षक कानपुर ने अक्तूबर १०, सन् ५३ की जो रिपोर्ट सरकार को दी है, उसे कृपया मेज पर रखेंगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस दिनांक की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई ।

चरना डाकू तथा उसके साथियों के मृत शरीरों को आगरे में लाने का कारण

४—**श्री महाराज सिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चरना डाकू तथा उसके अन्य साथियों को मैनपुरी जिले के पुलिस दल ने मारा और उन डाकुओं की लाशों को आगरा ले जाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णनन्द—जी हां । लाशों की फोटो लेना जरूरी था जिससे उनकी पहिचान के बारे में बाद को झगड़ा न उठे । इसके लिए उचित सुविधा आगरे में प्राप्त थी ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर न मिलने पर आपत्ति

***श्री राज नारायण** (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि २४ तारीख को हमने एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दिया था और वह बहुत महत्वपूर्ण था और अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि एडजर्नमेंट मोशन लाने से पहले माननीय सदस्य अल्प सूचित तारांकित प्रश्न पूछा करें। उसके अनुसार हमने अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दिया था। वह केन सेस के सम्बन्ध में था आज तक नहीं बतलाया गया है कि वह अल्प सूचित तारांकित प्रश्न माना गया है या नहीं। जब कि इसका उत्तर तीन दिन में मिलना चाहिये था। इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पुरानी प्रोसीडिंग्स को पढ़ा तो मुझे कई अकेजन्स ऐसे मिले दूसरी जगहों पर जिसमें अध्यक्ष महोदय ने मंत्रियों को सख्त चेतावनी दी है कि "Ministers should come prepared" मंत्रियों की ओर से वेग आन्सर के मिलने से एक नियम का प्रश्न उठता है। मैं इस पर कोई विशेष जोर नहीं देना चाहता। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री लोग जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं कि उसके लिये किसी समय की भी आवश्यकता नहीं। 'यदि ऐसा है तो विचार किया जायगा' सब सवाल का यही जवाब दिया जा सकता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आइन्दा मंत्री महोदयों से कहा जाय कि वह तैयार हो कर जायं और जो उनसे सवाल पूछा जाय उसको कस के साथ तैयार करें और सदन में समुचित उत्तर दें। वेग उत्तर से हमारा भी नुक्सान होता है और उनका भी नुक्सान होता है।

श्री उपाध्यक्ष—इस विषय में मैं दफ्तर से दरयाफ्त करूंगा और उसके पश्चात् कुछ कह सकूंगा ।

देवरिया जिले के खड्डा इलाके में अनेक गांवों में एक साथ आग लगने तथा अधिकारियों के व्यवहार के सम्बन्ध मे कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—आज एक ऐडजर्नमेंट मोशन की एक सूचना मिली है जो कि तारीख २ मार्च की एक घटना के आधार पर है। आज १२ तारीख हो गयी, इसलिये शायद

---

*यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

[श्री उपाध्यक्ष]

यह इतने महत्व का प्रश्न नहीं रह गया कि इस पर कोई ऐडजर्नमेंट मोशन पेश किया जाय। इसके अलावा इसमें वाद-विवाद भी है। यह बिलकुल स्पष्ट भी नहीं है।

एक सदस्य---इसका विषय क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---इसका विषय है देवरिया जिले के खड्डा इलाके में एक ही साथ कई गांव में आग लग जाना और यह भी कहा जाता है कि वहां के अधिकारी जिस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं वे ऐसी हैं जिन से वहां शांति कायम नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में मैं इसको पेश करने की अनुमति नहीं देता हूं।

विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष के निर्णय के सम्बन्ध में पूछताछ

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल कहा था कि जो कोच आफ प्रिविलेजेज के विषय हैं उन पर वह अपना निर्णय आज देंगे। तो उस सम्बन्ध में यदि आप कुछ बतला दें तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं सदन को यह बतला दूं कि माननीय स्पीकर महोदय आज कुछ अस्वस्थ हैं और इससे आज वह नहीं आ सकेंगे। कल वह स्वयं आकर इसका समाधान कर सकेंगे।

१९५४--५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय-विभाजन

श्री उपाध्यक्ष---ये दोनों अनुदान यदि आप एक साथ ही उपस्थित कर दें तो अच्छा होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं दोनों ही उपस्थित कर रहा हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मेरा यह सुझाव है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री के चार अनुदान हैं। आज केवल अनुदान संख्या १९ और २० ली जायं और कल ४० और ४९ ली जायं। दूसरा सुझाव यह है कि १९ और २० नम्बर का अनुदान एक साथ ले लिया जाय।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक ३९---जन-स्वास्थ्य

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९-चिकित्सा (लेखा शीर्षकः ३८-चिकित्सा) के अन्तर्गत २,६५,२३,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०-जन स्वास्थ्य (लेखा शीर्षकः ३९-जन स्वास्थ्य) के अन्तर्गत १,३०,२०,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन आकड़ों को मैंने सदन की स्वीकृति के लिए स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में उपस्थित किया है यदि इन आंकड़ों में ५० लाख रुपये और भी जो स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट और

फारेस्ट डिपार्टमेंट में व्यय किये जाते हैं, जोड़ लिये जायं तो वे आंकड़े इस प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के लिए उस अनुपात में जिस अनुपात में प्रदेश की जनसंख्या है, बहुत रोचक प्रतीत नहीं होते हैं। मैं स्वयं उन आंकड़ों से बहुत न तो प्रभावित हूं और न मैं उन आंकड़ों को देखकर ऐसा समझता हूं कि इन आंकड़ों की बुनियाद पर प्रदेश की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हल की जा सकती है। सदन के सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं कि ये आंकड़े किन कारणों से इतने कम हैं, यदि इन आंकड़ों का मुकाबिला इस देश के और प्रदेशों से किया जाय तो यह आंकड़े बहुत कम प्रतीत होते हैं और इस प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात और समस्या के अनुपात में ये ऐसे प्रतीत होते हैं कि इनसे प्रदेश की इतनी बड़ी समस्या हल नहीं की जा सकती परन्तु हम यह तो जानते ही हैं कि हमने और केंद्रीय सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है और उसके अन्तर्गत हम इस देश के और और प्रदेश के विभिन्न प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हमने उस योजना का अध्ययन किया है तो हमें यह भलीभांति मालूम है कि इस योजना में, स्वास्थ्य की योजना के सम्बन्ध में जो प्राथमिकता प्रदान की है वह बहुत कम है। यही कारण है कि हम अपने प्रदेश में अधिक धन स्वास्थ्य की समस्या के हल के लिए प्रत्येक वर्ष नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन इस बात में भी सत्यता है हर सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि पहले उन चीजों का इन्तजाम करे बीमारियां जिन कारणों से हमारे बीच में पैदा होती है। और हम में से हर एक यह अच्छी तरह से जानता है कि यदि लोगों को अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा रहने को मिले तो बीमारियां हमारे बीच में कम पैदा होंगी। अगर हम इस वास्तविकता को अपनी नजर के सामने रखे तो हमें यह मानकर चलना पड़ता है कि हमें अन्न उत्पादन और और चीजों के सम्बन्ध में और उन समस्याओं के हल करने में अपने प्रदेश का रुपया अधिक व्यय करना चाहिए और इसके बाद स्वास्थ्य समस्या को हल करने का प्रश्न हमारे सामने आये। इसलिये हमारा प्रदेश और हमारी केंद्रीय सरकार आज अन्न के उत्पादन इर्रीगेशन, ऐग्रीकल्चर और ऐसे तमाम विभागों में, जिनके द्वारा लोगों का स्तर ऊंचा किया जा सकता है, अधिक धन व्यय कर रही है।

इसके यह मानी नहीं हैं कि प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विमुख है यद्यपि प्रदेश की सरकार इतनी बड़ी रकम नहीं खर्च कर रही है जितनी बड़ी रकम उसे खर्च करनी चाहिये।, ताहम इस रकम में वह जितने कार्य कर रही है यदि उनको उन आंकड़ों पर जांचने की चेष्टा करें जो हमें देखने को मिलते हैं तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इन चार पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों से इस प्रदेश के व्यक्तियों की संख्या में जो प्रत्येक वर्ष मरते हैं बहुत कमी हुयी है। जहां तक मृतकों की संख्या का सम्बन्ध है मैं यदि आपके सामने थोड़े बहुत आंकड़े रखूं जो और प्रदेशों से सम्बन्ध रखते हैं तो उससे आपको परिचय मिल सकेगा कि हमारा प्रदेश यद्यपि धन कम व्यय कर पा रहा है, तब भी यहां के जन स्वास्थ्य की हालत अच्छी है। मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं। हमारे प्रदेश में बकि सन् १९४४ में हजार आदमियों के पीछे १८.७४ व्यक्ति मरा करते थेसन् १९५२ में, १०.७० फीसदी मरे और यदि हम मध्य प्रदेश, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल के ऐवरेज से जोकि १९४६ से १९५० तक ५ वर्षों में मृतकों का रहा, यू०पी० के आंकड़ों से मुकबिला करें तो पता चलेगा कि हमारे प्रदेश में मृतकों की संख्या हजार पीछे बहुत कम है। मध्य प्रदेश में हजार में ३०.७४ व्यक्ति प्रतिवर्ष मरते हैं, मद्रास में १८.७५ व्यक्ति मरते हैं। बम्बई में २०.०१ व्यक्ति मरते हैं और पश्चिमी बंगाल में लगभग १७ व्यक्ति मरते हैं और यू०पी० का ऐवरेज सन् ४६ से सन् ५० तक का केवल १३.५३ प्रति हजार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह ऐवरेज आबादी से है या बीमारों से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आबादी से है।

[श्री चन्दभानु गुप्त]

मृत्यु संख्या की कमी हमारे प्रदेश में यद्यपि महज इसलिए नहीं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई कार्य हुआ है कोई और वजहें भी हैं जिनकी वजह से हमारे प्रदेशमें मृतकों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। उसमें शिक्षा का प्रसार और ऐसे कार्य जिनके द्वारा लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा किया जा सकता है वे बातें भी उसमें शामिल हैं। अतः यह सरासर धृष्टता होगी यदि मैं यह कहूं कि सारी कमी जो मृतकों में प्रतिवर्ष होती जा रही है वह महज स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के ही कारण है, परन्तु मैं इस बात का श्रेय अवश्य लेने को तैयार हूं कि पिछले ६-७ वर्षों में मलेरिया, हैजा और अन्य संक्रामक रोगों की वजहसे जो मृत्युएं हुआ करती थीं उनमें उत्तरोत्तर कमी हुई है। माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्रदेश में संक्रामक रोगों का घर बना हुआ है। क्या मलेरिया, क्या हैजा और क्या प्लेग यह तमाम रोग हमारे प्रदेश में ऐसे रहे हैं जो प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोगों को ग्रसित करते रहे हैं। और लोगों को दुनियां से फना करते रहे हैं, लेकिन हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि ४-५ वर्ष मलेरिया से लड़ने के बाद हमने इस प्रदेश में मलेरिया से मरने वालों की संख्या में घटोत्तरी की है। जहां पहले ७ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष मलेरिया से मर जाते थे वहां अब प्रदेश की सरकार ने यह संभव कर दिया है कि वह संख्या १ लाख ५० हजार के निकट आ गये है।

इसी तरह से हैजे से जहां पहले ५० हजार आदमी प्रति वर्ष मर जाया करते थे वहां आज जो आंकड़े हमारे सामने हैं वह बतलाते हैं कि आज प्रतिवर्ष हैजे से मरने वाले लोगों की संख्या १० हजार के नजदीक पहुंच गयी है। क्या यह इस बात को सिद्ध नहीं करता है प्रदेश की सरकार ने मेलों में जो कम्पलसरी इनआकुलेशन की प्रथा जारी की उससे बहुत से लोग जो पहले हैजे से मर जाया करते थे उनकी संख्या अब घट गयी है। अभी कुम्भ का मेला हुआ। उसमें भी हमने कम्पलसरी इनआकुलेशन की स्कीम को जारी किया। यद्यपि बाद को मेले के दो दिन पहले उसे बन्द कर दिया लेकिन उससे जो कुछ फायदा मेले में सम्मिलित होने वालों को हुआ वह इस बात का प्रमाण है कि कम्पलसरी इनआकुलेशन से कालरा रुक जाता है और कालरा ग्रसित व्यक्तियों से दूसरों को बचाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि हमने हर साल बजट में ज्यादा रुपया खर्च नहीं किया लेकिन जितने कार्य किये उनसे मृतकों की संख्या घटती गई है। उससे यह बात सिद्ध होती है कि जन स्वास्थ्य प्रदेश में ऊंचा उठता जा रहा है।

इसी तरह से हमने मलेरिया की स्कीम १८ जिलों में, और खास कर तराई भाबर में जारी की। उसका नतीजा यह हुआ कि हजारों घर वहां जा कर बस गये और रोजगार व खेती-बाड़ी करने लगे। ऐसे क्षेत्रों जहां लोग जाते नहीं थे, जहां जा कर लोग बीमार पड़ जाते थे, और अपने रोजगार से वंचित हो जाते थे वहां आज मलेरिया निरोधक डी० डी० टी० और उन एप्लायसेंज का उद्योग कर रहे हैं जो आधुनिक विज्ञान ने प्रदान किये हैं, उनको इस्तेमाल करके मलेरिया की रोकथाम हुई है। उन यूनिट्स के मातहत जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने हमको दिया है हम मलेरिया से लड़ने का कार्य प्रदेश में कर रहे हैं और उनके द्वारा उत्तरोत्तर इस बात की चेष्टा में लगे हुए हैं कि मलेरिया हमारे प्रदेश से समाप्त हो जाय ताकि देहात के रहने वाले जो हजारों की संख्या में इस रोग से पीड़ित होकर फना हो जाते थे उनको हम मरने से रोक सकें।

इसी तरह से हमने टी०बी० की बीमारी पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया। बी०सी०जी० टीका लगाने की ९ टीम्स जो हमारे प्रदेश में थीं उन्होंने, ३०,४० लाख व्यक्तियों के टीके लगाये हैं और उत्तरोत्तर वे अपना कार्य बढ़ाती जा रही हैं। इससे टी०बी० के रोगियों की संख्या घटती जा रही है। यद्यपि सारे प्रदेश में हम इन टीम्स को प्रसारित नहीं कर पाये हैं लेकिन उत्तरोत्तर यह प्रयत्न है कि हम टी०बी० टीम्स की संख्या को बढ़ावें। अगले वर्ष भी हम दो टीम्स को बढ़ा रहे हैं। यद्यपि ११ टीमें हमारे प्रदेश में कार्य करने लगेंगी लेकिन जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा

हमारे प्रदेश की समस्यायें बड़ी हैं। और उन्हें हल करने के लिये हमें अधिक धन की आवश्यकता है।

हमने देहाती क्षेत्रों में शिशुपालन केन्द्रों में भी पिछले वर्ष-इस वर्ष और अगले वर्ष में काफी संख्या में वृद्धि करने की नीति को अपनाया है। प्रदेश के सभी सदस्यगण को यह भली भांति मालूम है कि पिछले वर्ष जब हमने ६७ शिशुपालन केन्द्र बढ़ाने की घोषणा इस सदन में की थी उस समय सदन को यह सूचित किया था कि हमने विश्व स्वास्थ्य संघ के अन्तर्गत रह कर यह निर्णय किया है कि हम इन तीन वर्षों के अन्दर २०० शिशु पालन केन्द्रों की स्थापना करेंगे और उन स्थानों में जहां हमारी माताओं के लिये कोई इन्तजाम मैटरनिटी का नहीं है वहां पर कुछ इन्तजाम करें। पिछले वर्ष और इस वर्ष में हमने करीब-करीब ६७ और मैटरनिटी सेन्टर बनाये हैं। अगले वर्ष भी जैसा कि बजट के आंकड़ों से मालूम होगा कि हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ६७ मैटरनिटी सेन्टर खोलेंगे और उनके द्वारा देहाती जनता की, देहात के रहने वालों की, किसान भाइयों की सेवा करेंगे। यद्यपि यह ६७ मैटरनिटी सेन्टर भी बहुत कम है परन्तु मैटरनिटी सेन्टर का खोलना कोई आसान चीज नहीं है। इस मायने में कि धन भी हमारे पास हो तब भी हमको हेल्थ विजिटर और मिडवाइफ जो शिक्षित हो और जो अपनी जिम्मेदारी से काम को देख सके, मिलने मे दिक्कत होती है। हमें अपने प्रदेश में शिक्षित स्त्रियों के मिलने में काफी दिक्कत रही है क्योंकि हमारी बहनें इस कार्य के लिये आगे बढ़ती नहीं हैं। मिडवाइफ या नर्सों का काम या हैल्थ विजीटर का काम सीखने के लिये आगे नहीं निकलती हैं। इधर २-३ वर्षों में कुछ तरक्की इस ओर हुई है और कुछ संख्या में हमारी बहनें आयी हैं परन्तु अभी तक उस मात्रा में मिडवाइफ बनने के लिये या नर्सेज बनने के लिये या हैल्थ विजीटर का काम करने के लिये अभी स्त्रियां बाहर नहीं निकलती हैं। इस प्रकार से उनकी संख्या को हम बढ़ा नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में काफी संख्या में नर्स और मिडवाइफ और हैल्थ विजीटर पैदा हो जायं लेकिन ऐसा करने के लिये कुछ शिक्षा तो उनको देनी ही पड़ेगी और उनको कुछ टैक्नीकल बातों का ज्ञान भी कराना पड़ेगा जिनकी जानकारी के ऊपर वह अपना कार्य कर सकेंगी और हम उत्तरोत्तर उन्नति भी करेंगे परन्तु उचित संख्या में हमको स्त्रियां और बहनें नहीं मिल रही हैं। इस कारण से हम बहुत तेजी से मैटरनिटी सेन्टर इस प्रदेश में हर स्थान पर नहीं खोल सके हैं यद्यपि हमारी नीति यह है कि हम ५ मील के दायरे में अपने प्रदेश में मैटरनिटी सेन्टर स्थापित कर दें। जहां हम अस्पताल खोलने का आदर्श अपने सामने रखते हैं। वहां हमारी यह इच्छा भी है और हमारा यह भरोसा है कि इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ५ मील के दायरे में प्रदेश के हर हिस्से में एक मैटरनिटी सेन्टर स्थापित कर दें। इन तीन वर्षों के अन्दर हम २०० की संख्या पूरी कर लेंगे ऐसी हमें आशा है इन तीन वर्षों में अधिक संख्या में हमारी बहनें शिक्षा प्राप्त कर लेंगी। तथा मिडवाइफ का और नर्स का कार्य करने के लिये शिक्षित बन जायंगी। यह ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े प्रदेश में हमारे यहां ७००, ८०० नर्सें हैं। अधिक संख्या में नर्स की शिक्षा प्राप्त करने के लिये बहनों को उत्साहित करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सदन के सहयोग से अधिक संख्या में बहनें इस कार्य में हमारी सहायता करने के लिये आगे निकलेंगी और इस जिम्मेदारी को निबाहने का प्रयत्न करेंगी।

जहां हमने मलेरिया, कालरा और मैटरनिटी सेन्टर ऐसे कार्य कर के जनता की सेवा करने की चेष्टा की है वहां हमने डिस्पेंसरी चाहे वह आयुर्वेदिक हों या एलोपैथिक उनको खोलने का प्रयत्न किया है। इस सदन के सदस्यों ने इस बात को देखा होगा कि प्रत्येक वर्ष २०, २५ डिस्पेंसरी की स्थापना करते रहे हैं। कहीं पर डिस्पेंसरी को इमारत को बनाया गया है और कहीं पर हमने किराये के मकान में डिस्पेंसरी स्थापित की है,

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

परन्तु २०, २५ की संख्या इस प्रदेश में बहुत बड़ी नहीं है ताहम उन दिक्कतों के रहते हुये और अपने सीमित कोष को सामने रखते हुये हमने उत्तरोत्तर इस बात का प्रयत्न किया कि औषधालयों की संख्या बढ़े। जब हमने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग का बजट बनाया था तो उस समय उतनी प्राथमिकता हमें प्रदान नहीं की गई थी और ३-४ करोड़ से कुछ अधिक रकम स्वास्थ्य में और २ करोड़ के करीब जन स्वास्थ्य में रखी गयी थी। इसमें से करीब २ करोड़ की रकम स्वास्थ्य में और १ करोड़ के लगभग जनस्वास्थ्य में व्यय हो चुकी है और अगले २ वर्षों में बाकी रकम खर्च होगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ धन व्यय हुआ है जो पंचवर्षीय योजना में नहीं था। अगले वर्ष भी हम ४८ लाख रुपया योजना के बाहर खर्चा करने जा रहे हैं। हमारा उत्तरोत्तर यह प्रयत्न है कि हम स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ावें और इस प्रदेश की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करें। यह सम्भव नहीं है कि सभी बाधायें एकदम समाप्त हो जावें।

अकसर इस बात की शिकायत रहती है, और यह शिकायत थोड़ी जो भी है, कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अस्पताल या औषधालय होने चाहियें, वे नहीं खोले गये हैं। मैं वहाँ की आवश्यकताओं को समझता हूं ताहम उन दिक्कतों के कारण जिनका विवरण मैंने अभी थोड़े में दिया हमारे लिये यह सम्भव नहीं है। जब हमारे पास माँग आती है तो हम उस स्थान के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं और जब अस्पताल के स्टाफ के लिये स्थान मिलता है तो हम निर्णय करते हैं कि अस्पताल खोल दिया जाय। आज जब कि हम मकानों को जल्दी से तैयार नहीं करा सकते हैं तो हम यह चाहते हैं कि जनता हमसे सहयोग करे और यदि ऐसे मकान जहाँ अस्पताल रखे जा सकते हैं वे दिये जावें तो हम फौरन ही निर्णय उस स्थान पर अस्पताल खोलने के लिये कर देते हैं। पिछले वर्ष हमें कई स्थानों के लिये मालूम हुआ कि वहाँ डाक्टर, कम्पाउन्डर आदि के लिये स्थान नहीं है तो हमें अपना निर्णय बदल कर दूसरे स्थान पर अस्पताल ले जाने पड़े। बहुत से साथियों ने कन्सेशन्स दे रखे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी माँग और सुझाव उनके क्षेत्रों में अस्पताल खोलने की होगी। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने अस्पताल हमने खोलने का इस वर्ष टार्गेट रखा है वे हम उन्हीं स्थानों पर खोलेंगे जहाँ हमें इस प्रकार के स्थान मिलेंगे जिनका मैंने अभी जिक्र किया।

सन् ४६ से तो काफी अस्पताल हमारे प्रदेश में बढ़ गये हैं। करीब ३४७ अस्पताल अभी तक देहाती क्षेत्रों में हैं एलोपैथी के, अलावा उनके जो शहरी क्षेत्रों में हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद की डिसपेंसरियाँ भी सन् ४६ से ५३७ हो गई हैं। हमारा बजट भी ४, ५ साल में दुगुने से ज्यादा हो गया है। लेकिन यदि इस रकम को हम अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आय के अनुपात से देखने की चेष्टा करेंगे तो बहुत कम प्रतीत होती है और वास्तविकता यह है कि वह बहुत कम है भी। हमने प्रदेश में आयुर्वेदिक डिसपेंसरीज की संख्या बढ़ाई है और उसके साथ ही साथ हमने यह भी प्रयत्न किया है कि आयुर्वेदिक दवायें जो भेजी जायं वे भी सरकारी फारमेसी से भेजी जायं ताकि असली दवाइयाँ भेजी जा सकें। इस प्रकार हमने फारमेसी का निर्माण करके हर साल जो दवाइयों के ऊपर खर्चा करते थे उसमें भी लगभग डेढ़ लाख रुपया बचत की है। हमारा यह प्रयत्न है कि इस फारमेसी को हम एक ऐसी फारमेसी बनायें कि अलावा सरकारी अस्पतालों के जनता की दवाओं की माँग को भी वह पूरा कर सके। लेकिन अभी हमारी फारमेसी केवल सरकारी अस्पतालों के लिये ही दवाइयाँ तैयार कर रही है क्योंकि अभी फारमेसी के पास न तो सब प्रकार की दवाइयाँ तैयार करने के साधन हैं और न उचित संख्या में हम उन व्यक्तियों को ही रख सके हैं जो कि दवाइयों के निर्माण में निपुण होते हैं। हमें प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से हमारे नगर में एकड्रग रिसर्च इंस्टीटयूट कायम किया गया है और कदाचित उनके आविष्कार और अनुसंधानों से इस फारमेसी को भी फायदा होगा और उस समय ड्रग इंस्टीटयूट के द्वारा तैयार की गयी दवाइयाँ भी इस फारमेसी के द्वारा मैन्यूफैक्चर की जा सकेंगी।

अतः भविष्य में यह न केवल हमारे ही अस्पतालों के लिये दवाइयाँ तैयार करेगी बल्कि आम जनता और गैर सरकारी अस्पतालों के लिये दवा दे सकने में समर्थ हो सकेगी। इस साल बजट में फारमेसी के लिये ज्यादा रुपया रक्खा गया है। इससे उसकी इमारत भी तैयार की जायगी और आधुनिक ढंग की दवाइयाँ बनाने के साधन इकट्ठे किये जायंगे। हमें आशा है कि इससे तैयार की हुई दवाइयां थोड़े समय के बाद सारे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी।

अलवा इन देशी दवाइयों के तैयार कराने के हमने प्रतिवर्ष यह भी चेष्टा की है कि सरकारी अस्पताल जिनमें उचित प्रकार की सज्जा और सामग्री नहीं है उनको उचित प्रकार की सज्जा और सामग्री मुहैया की जाय। और इस बजट में उसके लिये रुपया रक्खा गया है। इस वर्ष के बजट में साढ़े पाँच लाख रुपया रक्खा गया है सज्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पिछले वर्ष ५–६ लाख रुपया और इस वर्ष १० लाख रुपया अधिक सज्जा और सामग्री को पूरा करने के लिये रक्खा गया है। इससे उन अस्पतालों में जो शहरी क्षेत्र में हैं आधुनिक ढंग की सज्जा और सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायगा। इन अस्पतालों में एक्स–रे की मशीने तथा उसके साथ नये तरीके के इलाज की एक्स–रे की मशीनें मुहैया करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

आयन्दा साल हम यह भी आशा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उन अस्पतालों की मदद करेंगे जो जीर्णावस्था में है। उनके लिये इस बजट में ५०,००० रुपया बढ़ाया गया है। हमारे प्रदेश में ऐसी भी समाज सेवी संस्थायें हैं जो इस प्रकार के औषधालय आदि को चला रही हैं। उन संस्थाओं में रामकृष्ण मिशन एक प्रमुख संस्था है जो प्रदेश की जनता की वर्षों से सेवा कर रही है और जिसका कार्य सदैव सराहनीय रहा है। मैं प्रतिवर्ष जब बजट तैयार करता हूं, तो उस संस्था के लिये कुछ न कुछ रुपया अधिक रखने का प्रयत्न करता हूं। इस वर्ष भी उस संस्था के अन्तर्गत जो संस्थायें चल रही हैं उनके लिये बजट में रुपया रक्खा गया है। करीब ४४ हजार रुपया इस प्रकार के गैर-सरकारी औषधालयों के लिये बटाया गया है।

हमने, अस्पतालों की इमारतें के सुधार के लिये भी करीब ५० ४४ लाख रुपये की रकम रखी है। इस पर हम प्रति वर्ष रखते जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को अनुभव होगा कि लड़ाई के जमाने में मरम्मत न होने के कारण हमारे अस्पतालों की काफी दुर्दशा हो गई थी। उस जमाने में रुपया उस मात्रा में उनके सुधार के लिये नहीं मिल सका और उत्तरोत्तर हालत बिगड़ती गई। लड़ाई के खत्म होने के बाद भी उस दिशा में काफी रुपया हम नहीं दे पाये थे जिस मात्रा में उनके सुधार के लिए आवश्यकता थी। पर अब हमें उत्तरोत्तर इसके लिए धन प्रतिवर्ष बढ़ाते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष लगभग ६ लाख रुपये उन अस्पतालों की इमारतों की मरम्मत के लिये रखे जा रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा कि चार पाँच वर्षों में अस्पतालों की मरम्मत काफी हुई है। पहले कुछ ऐसे अस्पताल थे जहाँ आदमी घुसना नहीं चाहता था, अब उनके रूप बदल गये हैं। यद्यपि और भी बहुत रुपये की आवश्यकता है ताहम यह छोटी रकम जो प्रतिवर्ष इन अस्पतालों की मरम्मत के लिये हम रखते हैं, उन अस्पतालों के सुधार की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद पहुंचाती है।

साथ ही कुछ ऐसी दवायें जो आधुनिक ढंग से रोज निकलती हैं और अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिये हमें जिनकी जरूरत होती है उनको

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हम यहाँ खरीद कर स्टोर में रखते हैं और जब जब उनकी आवश्यकता किसी स्थान में पड़ती है उनमें भेजने की चेष्टा करते हैं। उसके लिये करीब ५ लाख रुपये की रकम इस बजट के अन्दर रखी गई है।

हमारे प्रदेश में दो बड़े मेडिकल कालेज हैं, जहाँ से हमारे डाक्टर पढ़कर निकलते हैं जो हमारे देहाती अस्पतालों में और शहरी अस्पतालों में जाकर जनता की सेवा करते हैं। इन कालिजों को हम इन चार-पाँच वर्षों से काफी अनुदान दे रहे हैं। मेडिकल कालेजों को जो अनुदान हम देते हैं वह कुछ उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिये देते हैं जो इतने बड़े अस्पताल के लिये और इतने बड़े कालेज के लिये बहुत जरूरी है। हमारा मेडिकल कालेज, लखनऊ हमारे प्रदेश के उन प्रमुख संस्थाओं में से है जहां के डाक्टर योग्य हैं और जहाँ से वे लोग जनता की सेवा करने के लिये निकलते हैं और जो कि अपने अपने कार्यों में विशेषज्ञ हैं, और जिनका साइंस की दुनिया में स्थान है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि लखनऊ और आगरे के मेडिकल कालेजों को जहाँ इस प्रकार के डाक्टर हैं उनके लिये आधुनिक साधन सब मुहैया रहें। इसलिये उत्तरोत्तर उनपर किये जानेवाले व्यय को हम बढ़ाते जाते हैं। हमने इन कालेजों के विद्यार्थियों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि की है और इन विद्यार्थियों की जो शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते हैं आज लखनऊ मेडिकल कालेज में १५० विद्यार्थी प्रतिवर्ष दाखिल होते हैं और ७५ विद्यार्थी आगरा मेडिकल कालेज में हैं। यह १५० और ७५ की संख्या भी हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए नाकाफी सी है परन्तु हम अपने सीमित धन को देखते हुये उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमने बराबर इन संस्थाओं के लिये रुपया अपने बजट में रखने का प्रयत्न किया है और हम समझते हैं कि अगले वर्ष लखनऊ मेडिकल कालेज की एक बड़ी आवश्यकता जो है चिल्ड्रेन अस्पताल की वह पूरी हो जायगी और वहाँ पर जो सर्जिकल थियेटर्स हैं जिनकी आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही थी वह पूरी हो जायगी। मेडिकल कालेज में लड़कियों की संख्या चूंकि बढ़ गई है इसलिये लड़कियों के कालेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। उसको भी इस वर्ष के बजट में पूरा करने की चेष्टा की है। उसके आउटडोर विभाग में परिवर्तन करने के उद्देश्य से कुछ बैठने की सुविधायें लोगों को प्रदान करने के उद्देश्य से इमारत में परिवर्तन करने के लिये इस साल के बजट में हम रुपया रख रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि यह लखनऊ का कालेज और आगरा का कालेज उत्तरोत्तर प्रगति करता जायगा और प्रगति करते हुये अपने देश में उस स्थान को प्राप्त करेगा जिस स्थान को इसे प्राप्त करना चाहिये। उससे अनुपात में इस कालेज के डाक्टरों की योग्यता भी बढ़ेगी। मुझे दुःख है इस बात का कि बराबर शिकायतें आती हैं और वे शिकायतें पूरे तौर से रफा भी नहीं हो पा रही हैं कि मेडिकल कालेज के डाक्टर और हमारे विभाग के भी डाक्टर बहुत अधिक समय प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यय करते हैं। जहाँ तक इस विषय का संबन्ध है यह एक विवादग्रस्त विषय हो गया है कि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस शीघ्र ही बन्द की जाय या न बन्द की जाय। आज के समय में डाक्टरों की संख्या को सामने रखते हुये यह जरूर समझा जाता है कि मेडिकल कालेज के ऊपर जनता का जितना धन व्यय हो उसी अनुपात में मेडिकल कालेज अपने देश में और प्रदेश में अपना उच्च स्थान प्राप्त करे जिससे विज्ञान की दुनिया में उस विद्यालय में शिक्षा लेने वाले व्यक्ति उतना ही ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकें। हम चाहते हैं और हमारी ऐसी आशा है कि इस विद्यालय और ऐसे अन्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपना अधिक समय विज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने में व्यतीत करेंगे। यही आशा इतने बड़े कालेज से की जा सकती है।

ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना से अब मेडिकल कालेज के डाक्टरों को और मौका मिल गया है कि वह अपने अनुसन्धान में अधिक तरक्की कर सकें। हम आशा करते हैं कि वे इस कार्य की ओर भी ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो शिकायतें हुआ करती हैं कि मेडिकल कालेज के डाक्टर या हमारे विभाग के और डाक्टर केवल अपने बैंक बैलेन्स को ही बढ़ाने में अपना अधिक समय व्यय करते हैं हम आशा करते हैं कि वे ऐसी शिकायतों के होने का मौका नहीं देंगे।

जहाँ तक यूनानी और आयुर्वेदिक संस्थाओं का हमारे प्रदेश में संबंध है हमने उत्तरोत्तर उन्हें सुधारने की चेष्टा की है। हमने उनके अनुदानों में वृद्धि करके उनके यहाँ इक्वीपमेंट वग़ैरह के प्रबन्ध करने की चेष्टा की है। बजट में आपने देखा होगा कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक कालेज के लिये ५० हजार रुपये की रकम अनावर्तक और १५ हजार रुपये की रकम आवर्तक बढ़ाई गई है यानी रैकरिंग और नान रैकरिंग ग्रान्ट्स। इसी तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के यूनानी कालेज में, तकमीलुलतिब कालेज, लखनऊ और गुरुकुल काँगड़ी आयुर्वेदिक कालेज की आवर्तक रकमों में २० हजार की वृद्धि की गई है। जिससे कि उनमें आवश्यकीय यन्त्र रख दिये जायं और फिर उनके द्वारा वहाँ शिक्षा पाने वालों को आधुनिक शिक्षा दी जाय। वहाँ इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करके वे लोग जनता का अधिक फायदा कर सकें।

हमने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि लखनऊ के अन्दर जो आयुर्वेदिक कालेज बनने वाला है वह शीघ्र से शीघ्र स्थापित किया जाय। इसलिये इस बजट में ५० हजार की रकम टोकेन रूप में रक्खी गई है क्योंकि अभी उस कालेज के बारे में डिटेल्ड स्कीम तैयार नहीं हुई है। हम आशा करते हैं कि डेढ़ दो महीने के अन्दर उस कालेज की डिटेल्ड स्कीम कालेज के संचालन की तैयार हो जायगी और जुलाई से वह कालेज यहाँ अपना कार्य आरम्भ कर देगा। सदस्यों को यह भी भलीभांति मालूम होगा कि हमने ४ वर्ष पूर्व इस बात का प्रयत्न किया था कि लखनऊ विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की संरक्षता में एक आयुर्वेदिक कालेज चलाया जाय और विद्यार्थियों को दाखिल करके हमने कार्य भी आरम्भ किया था परन्तु कुछ कारणों से हम उसमें सफल न हो सके। हम उन कारणों का यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि गत वर्ष हम उनका जिक्र कर चुके हैं। मेडिकल कालेज के डाक्टरों से हमें उतना सहयोग न प्राप्त हो सका जितने सहयोग की हम आशा करते थे। यह दुःख की बात है परन्तु अब हमने निर्णय किया है कि इस कालेज को गवर्नमेंट के अन्तर्गत किसी दूसरे स्थान पर चलायें और उसकी इमारत बनवाने का पूरा–पूरा प्रबन्ध करें।

बजट के विभिन्न पन्नों को देखने से यह पता चलेगा कि इस प्रकार के कालेज के बनाने के लिये पब्लिक वर्क्स के बजट में हमने रुपया रखा है। कुछ इमारतें उस कालेज की बन भी गयी हैं, कुछ वार्ड बन गये हैं और कुछ शीघ्रता के साथ बनाये जा रहे हैं। जैसी कि अभी मैंने कहा हम कदाचित उस कालेज को जुलाई से प्रारम्भ कर देने और विद्यार्थियों का दाखिला करने के लिये जुलाई से पूरा प्रबन्ध कर सकेंगे।

हमने इस बजट में होमियोपैथी के प्रसार के निमित्त होमियोपैथिक बोर्ड के लिये कुछ रकम रखी है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही होमियोपैथिक के रेजिस्ट्रेशन के लिये जो नियम बनाये जा रहे हैं वे लागू हो जायेंगे और उन नियमों के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में होमियोपैथिक डाक्टरों के रेजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारम्भ हो जायगा और इस तरह से होमियोपैथी के विकास में भी हम कुछ मदद दे सकेंगे।

इन तीन चार वर्षों में हमारे प्रदेश में टी०बी० के बेड्स की संख्या भी बढ़ी है। अगले वर्ष में हमारे यहां टी० बी० के तीन स्थानों पर वार्ड बनने जा रहे है, एक तो मेरठ में, एक फीरोजा-

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बाद में और एक इटावा में। फीरोजाबाद में तो अप्रैल से ही वार्ड्स का कार्य प्रारम्भ हो जायगा। इटावा का अस्पताल करीब-करीब तैयार है, उसके खुलने की ही देरी है। फीरोजाबाद में करीब करीब दो तीन महीने में नये वार्ड तैयार हो जायेंगे और वहां टी० बी० के सौ बेड्स को रखने का इन्तजाम किया जा रहा है। इसी तरह से प्यारेलाल हास्पिटल, मेरठ, में २५ शैयों का एक वार्ड तैयार किया जायगा। वृन्दावन में भी विद्यार्थियों के टी० बी० फंड से २५ टी० बी० के बेड्स का वार्ड बनने वाला है। हमारी यह भी योजना है यद्यपि हमें दुख है कि हम उसके लिये अपने इस मौजूदा बजट में रूपया नहीं रख सके कि इलाहाबाद, बनारस, सारनाथ में भी टी० बी० के अस्पताल कायम हो जावें। इसकी स्कीम भी सरकार तैयार करा रही है और हम आशा करते है कि इन अस्पतालों का निर्माण कार्य भी अप्रैल या मई के महीने से प्रारम्भ हो जायगा। इस तरह से हम अगले वितीय वर्ष में इन अस्पतालों को इन स्थानों पर स्थापित कर सकेंगे।

हमने इतने वर्षों में नेत्र चिकित्सा का भी बराबर प्रबन्ध किया है और अपने प्रदेश के उन दो बड़े अस्पतालों को बराबर सहायता प्रदान की है जो प्रदेश की जनता की काफी सेवा करते रहे हैं। मेरा अभिप्राय अलीगढ़ और सीतापुर के अस्पतालों से है। यह दो अस्पताल हमारे प्रदेश के बल्कि हमारे प्रदेश के ही नहीं, हमारे देश के प्रमुख नेत्र चिकित्सा के अस्पताल हैं। मैंने पिछले वर्ष इन अस्पतालों की प्रशंसा में कुछ बातें कही थीं, जो विदेश के रहने वालों ने इन अस्पतालों के सम्बन्ध में कहीं थी। वह अस्पताल आज भी उसी तरह से लगन के साथ कार्य कर रहे हैं जैसा कार्य वे पिछले वर्षों में बराबर करते आ रहे हैं। हमने १५, १५ हजार की रकम उनके आवर्तक अनुदानों में इस वर्ष बढ़ाई है। हम चाहते हैं कि यह अस्पताल अधिक से अधिक सेवा हमारे प्रदेश की करते रहें।

जहां तक नेत्रों के रोगों का सम्बन्ध है हमने अपने प्रदेश में एक आप्थलमिक ऐडवाइजरी कौंसिल की स्थपना है। उस कौंसिल ने नेत्रों के इलाज के लिये पूरे प्रदेश को पांच क्षेत्रों में बांट रखा है और पांच जोन्स बड़े-बड़े आई स्पेशलिस्ट के अन्तर्गत काम करते हैं। इन जोन्स में विभिन्न लोगों की सहायता से आखों की बीमारियों को दूर करने के लिये कैम्पस इत्यादि की रचना होती है, मोबाइल कैम्पस की रचना होती है। इनके अन्तर्गत विभिन्न जगहों पर नये आंखों के अस्पताल खोले जाते है और लोगों की आंखों के रोगों से मुक्त करने के लिये तरह-तरह की सहायता इस कौंसिल के अन्तर्गत प्राप्त की जा रही है। हमारे प्रदेश में ऐसा बताया जाता है कि करीब नौ दस फीसदी लोग आंख के रोगों से ग्रसित रहते हैं। यह अस्पताल और यह कौंसिल अपने कार्य को इधर उधर बढ़ाती जायगी और अपने इन कार्यों के द्वारा लोगों की आंखों के रोगों का निवारण कर सकेगी। आंखों के रोग और आंखो की बीमारी मनुष्य के जीवन में क्या स्थान रखती है, इसकी तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं।

यदि इन संस्थाओं के द्वारा लोगों को अपनी आंखें मिल जाती हैं, लोगों को प्रकाश देखने को मिल जाता है तो यह उनके लिये कितनी अनमोल चीज है, मुझे इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से और इस प्रदेश की जनता की ओर से इन संस्थाओं के संचालकों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनकी मिसाल का अनुकरण और भी प्रदेशों के डाक्टर जो योग्यता रखते हैं, जो क्षमता रखते हैं करेंगे। यदि इन संस्थाओं के संचालकों की तरह से कार्य करने वाले हमारे प्रदेश में अधिक संख्या में पैदा हों तो हमारी बीमारियों की संख्या बहुत हल्की हो सकती है और हम उस कार्य को बहुत तेजी के साथ पूरा कर सकते हैं जिसके लिये और अधिक धन और परिश्रम की आवश्यकता है।

हमने प्योर फूड ऐक्ट के अन्तर्गत यह भी कदम उठाया है कि आज जो विभिन्न प्रकार की वस्तुयें हमारे खाने की बाजार में मिलती है उन में मिलावट होती है उसको रोकने के लिये हमने अधिक संख्या में चीजों के सैम्पिल लेने का प्रबन्ध किया है। १९४६ से अब सैम्पिलों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। जो व्यक्ति दोषी पाये

जाते हैं उन्हें सजा भी दी जाती है। पिछले वर्ष मिलावट के मामलों में ३ लाख रूपये जुरमाने की सजा दी गई। और ३४, ३५ आदमियों को जेल की भी सजा हुई है। पहले हमारे यहां जो ऐक्ट लागू था उसमें जेल की सजा नहीं थी परन्तु अब जो फूड ऐक्ट बना कर प्रदेश में लागू किया गया है उसके अन्तर्गत लोगों को जेल की सजा भी मिलती है। हम आशा करते हैं कि इस ऐक्ट को प्रदेश में तेजी के साथ और कड़ाई के साथ लागू करने से एडल्ट्रेशन की बीमारी जो रोजमर्रा बढ़ती जाती है वह घट जायगी।

दवायें जो बाजार में मिलती हैं उनमें भी बहुत सी मिलावट की दवायें मिलती हैं। उनसे रोग भी बढ़ता है और बीमार भी अच्छे नहीं होते हैं। उनकी मिलावट को रोकने के लिये हमने अपने प्रदेश में कुछ इन्स्पेक्टर्स रख छोड़े हैं और अगले वर्ष कुछ क्षेत्रों में काम करने के लिये ५ और इन्स्पेक्टर्स रखने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इन इंस्पेक्टरों के कार्य करने से और इनके सचेत रहने से वे संस्थायें, वे दुकानें, और वे मैन्यूफैक्चर्स जो दवाओं में मिलावट करते हैं और दोषपूर्ण दवायें हमारे प्रदेश में प्रसारित करते हैं उनके इस कार्य में रुकावट होगी। उनके पकड़े जाने पर जो बुरा कार्य आज हमारे देश और प्रदेश में चल रहा है, वह रोका जा सकेगा। उत्तरोत्तर हमारा यह प्रयत्न है कि हम इस दोष को रोकें।

मैंने आपके सामने थोड़े शब्दों में उन चीजों को तो रख दिया जिनके संबंध में हम कार्य करेंगे या कर रहे हैं, परन्तु हम सारा कार्य करते रहते हुये भी अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पायेंगे, यदि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के सिलसिले में हम कुछ कदम न उठायेंगे। आज चाहे जितना पैसा व्यय करने की हम चेष्टा करें, चाहे जितनी सामग्री इकट्ठा करने की हम चेष्टा करें यदि प्रदेश में जितनी जन संख्या बढ़ती जा रही है उसको रोकने की हम चेष्टा न करें तो एक दिन वह आ जायेगा कि जब न तो हमारे पास खाने के लिये सामग्री होगी और न पहनने के लिये वस्त्र होंगे। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसा वातावरण अपने प्रदेश में पैदा करें जिससे हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या में कुछ रुकावट डाल सकें और उसके लिये हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति अपने ऊपर कुछ ऐसा प्रतिबन्ध लगायें जिससे कि वे इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकें। उसके लिये भी हमारी प्रदेशीय सरकार की ओर से अगले साल के बजट में भी और इस साल के बजट में भी रेड क्रास सोसायटी के अन्तर्गत जो कार्य फैमिली प्लानिंग का चल रहा है उसको सहायता प्रदान की है। और जे० के० इंस्टीट्यूट जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसको भी मदद पहुंचाई है। हम आशा करते हैं कि इन संस्थाओं को इस प्रदेश की जनता का सहयोग प्राप्त होगा और उस सहयोग से इस बढ़ती में रुकावट डालने का प्रयत्न किया जायगा जोकि एक भयंकर स्वरूप हमारे बीच में उपस्थित कर सकती है।

मैंने थोड़े शब्दों में आपके सामने जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसका संकेत किया है, परन्तु मैं यहां यह कह देना चाहता हूं कि जो योजनायें हमारे विशेषज्ञों ने समय-समय पर हमें दी हैं, यदि हम उन योजनाओं को केवल सरकारी व्यय पर कार्यान्वित करना चाहें तो वे योजनायें तो कार्यान्वित नहीं हो सकती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भोर कमेटी और हमारे प्रदेश की सरकार ने जिस कमेटी को नियुक्त किया था उसने जिन बातों का जिक्र किया है और जिस रुपये की मांग अपनी रिपोर्ट में सुझावों के अन्तर्गत की है वह पूरी नहीं हो सकती है। भोर कमेटी ने सारे देश के लिये और हमारे प्रदेश के लिये, विभिन्न योजनाओं के लिये पहले ५ वर्षों के लिये ५१ करोड़ रुपये की मांग की थी और पहले १० वर्षों के लिये करीब ११६ करोड़ रुपये की मांग की थी। मैं नहीं समझता कि इस ५१ करोड़ रुपये की मांग और ११६ करोड़ रुपये की मांग को यह हमारा प्रदेश कैसे पूरा कर सकता है जिसको कि पहले अपनी और समस्याओं को हल करना भी आवश्यक है, जिसके हल करने से बीमारियां दूर हो सकती हैं यानी अन्न की समस्या, लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करना इत्यादि। इसके लिये हमारे देश की ओर से एक कमेटी नियुक्त की गई थी जिसके चेयरमैन हमारे सभापति जी श्री खेर थे। उस कमेटी नें २६.१६ करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की थी।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

यह योजनायें विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर हमारे बीच में आईं लेकिन वह हमें आगे नहीं ले जा पाई और हमें रास्ता नहीं दिखा पाई। ऐसे समय में जब कि हमें वास्तविकता से मुकाबला करना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि पहले हमें अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हुये बीमारियों को रोकने का प्रबन्ध करें। इसलिये जहां-जहां मैं जाता रहा हूं जनता से हमेशा कहता रहा हूं कि यदि हमें अपनी समस्याओं को हल्का करना है तो इस प्रदेश की जनता को उन कार्यों को पूरा करने में अपने पैसे से और श्रम से पूरा-पूरा सहयोग सरकार को देना है और जब जनता अपना सहयोग देगी तभी हम अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। अन्यथा यदि हम सरकारी कोष की तरफ ही नजर लगाए रहे और समस्याओं को पूरा करने का प्रबन्ध करते रहे, तो इसमें वर्षों लग जायेंगे और समस्या फिर भी वैसी की वैसी ही दिखाई देगी, जैसी कि आज हमें दिखाई दे रही है।

आज इसीलिये इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हम अपने प्रदेश के कोने-कोने में हास्पिटल सेंटर चालू करें और धन संग्रह करें और उस संग्रह किये हुये धन को अस्पतालों की जरूरतों पर व्यय करें, मरीजों के भोजन पर व्यय करें और अस्पताल की सज्जा के लिये व्यय करें जिसकी कि अस्पतालों को नितान्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारी एक योजना और थी और वह यह कि हम इस प्रदेश में यह चाहते थे कि अस्पतालों के लिए लौंड्री चलायें, जैसा कि बाहर के देशों में किया जाता है परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके लिये केन्द्रीय सरकार से इजाजत नहीं मिली। इसलिये इस योजना को हम आगे न बढ़ा सके।

मैं आशा करता हूं कि जिन बातों की तरफ मैंने संकेत किया है और जिन आशाओं को प्रगट किया है, हमारे इस माननीय सदन के सदस्यगण उनको पूरा करने के लिये हमको अपना पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे अपने-अपने स्थानों पर अस्पताल के निर्माण के लिये एक कोष स्थापित करने की कोशिश करेंगे जिससे अपने-अपने यहां के अस्पतालों के निर्माण में सहायता कर सकें और देश की आवश्यकता पूरी करने में सहायक बन सकें। आप आलोचना कर सकते हैं और मैं भी इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि आज हमारे विभाग में बहुत सी त्रुटियां हैं और बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं, जो उतनी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं और उस त्याग के साथ कार्य नहीं कर रहें हैं जिस क्षमता और त्याग के साथ उनको काम करना चाहिये। हम इन बातों को देखते हुये भी यह ऐसा कह सकता हूं कि बहुत से हमारे ऐसे कर्मचारी भी हैं जो काफी अच्छे हैं और जिन्होंने बड़ी योग्यता के साथ कार्य किया है, बड़ी मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ कार्य किया है। अभी हाल ही में कुम्भ मेला हुआ था। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई थी वहां पर जितना कार्य स्वास्थ्य विभाग ने किया है वह कर्मचारियों के परिश्रम और लग्न का परिचायक है। ऐसा इंतजाम था जिसके अंतर्गत एक मक्खी तक दिखाई नहीं देती थी और बीमारी नहीं फैली। यह बात इसको द्योतक है कि हमारे कर्मचारियों ने बड़ी लग्न, मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य किया। मैं अपनी ओर से तथा अपनी सरकार की ओर से उन कर्मचारियों को जिन्होंने कुम्भ के अवसर पर बड़ी ईमानदारी, लग्न तथा मेहनत के साथ कार्य किया है, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस राज्य के कर्मचारी हमारे बीच में और उभरेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिससे जनता का हित सिद्ध हो। मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस बजट को आपके सामने सदन की स्वीकृति के लिये उपस्थित कर रहा हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दोनों प्रस्तुत अनुदानों में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने अपनी एक घंटे की लम्बी तकरीर में करीब करीब जितने विषय इस पुस्तिका में लिखे हुए हैं उनसे भी आगे बहुत सी बातों का जिक्र

किया है । यह तो सम्भव नहीं होगा कि दोनों अनुदानों के सम्बन्ध १०-१५ मिनट मे बहुत सी बातें कह सकूं, लेकिन यथासम्भव हम यह देखते है कि जब हम इस पुस्तिका को उठाते है और इसमें दिये हुये तीन वर्षों के आंकड़ों को देखते हैं तो हमें यह दुख होता हैकि जिस गौरवपूर्ण भाषा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने बातें कहीं सरकार की नीति उस दृष्टिकोण से नहीं चलती है ।

हम देखते हैं कि सन् १९५२-५३ में चिकित्सा के लिए २,३६,४६,५०७ रु० है, लेकिन १९५४ में है २,६५,२३,१०० रुपया । जब हम जन-स्वास्थ्य की ओर देखते हैं तो सन् १९५२-५३ में १,११,४६,७८२ रु० है और सन् १९५४ में १,३०,२०,२०० रुपया है । इसी प्रकार से अगर हम गत वर्ष से इस आने वाले वर्ष का मुकाबला करते हैं तो सन् १९५४-५५ मे करीब ४८ लाख रुपये की कमी जन-स्वास्थ्य में कर दी गयी है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कुम्भ मेला अगले साल नहीं होगा । यह उसी का खर्च है जो इसमें शामिल है ।

श्री गंगाधर मैठाणी---और यदि हम पिछले आंकड़ों को भी देखते हैं तो मालूम होता है कि सरकार का ध्यान इस चिकित्सा और जनस्वास्थ्य की ओर, जिसे मैं समझता हूं कि खाद्य के बाद सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिये, कोई अधिक महत्व नहीं दिया गया है सन् १९५०-५१ में चिकित्सा में ३.८४ प्रतिशत बजट का खर्च हुआ और सन् १९५१-५२ में ३.८४ प्रतिशत खर्च हुआ । सन् १९५२-५३ में ३.६२ प्रतिशत खर्च हुआ । उसी प्रकार जन स्वास्थ्य में देखते हैं कि सन् १९५०-५१ में १.६४ और सन् १९५१-५२ में १.७५ हुआ और सन् १९५२-५३ में १.६५ खर्च हुआ । इस प्रकार से जैसा कि माननीय वित्तमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह कल्याणकारी राज्य का आईना है और जिस कल्याणकारी राज्य के आईने में हम देखते है कि माननीय गृहमंत्री के पुलिस विभाग के लिए ११ करोड़ रुपया दिया जाता है, जब जन-स्वास्थ्य का नम्बर आता है तो एक करोड़, कुछ लाख रुपया इसमें आता है । हम जैसी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आशा करते थे यह उस प्रकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने भोर कमेटी का जिक्र किया और यह कहा कि ११६ करोड़ रुपया खर्च करने की ताकत इस देश के अन्दर नहीं थी, इसलिये वह लागू नहीं की गयी, लेकिन उसके बाद ही जो खेर कमेटी बैठी थी उसके अन्दर भी हम देखते है कि जितनी रिकमेंडेशन की गयी थी उनका भी कोई पालन नहीं हुआ । खासकर एक रिकमेंडेशन ऐसी थी कि हेल्थ और चिकित्सा इन दोनों का जिला स्तर पर एकीकरण कर दिया जाय यद्यपि प्रान्तीय स्तर पर एकीकरण किया गया, लेकिन जिला स्तर पर भी नहीं किया गया । उससे आगे कि देश का खर्चा घटाया जाय, सब से बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अन्दर बड़े अफसरों के और छोटे अफसरों के वेतन का जब इतना फर्क है तो उसके द्वारा हम काफी रुपया बचा सकते थे । जैसा कि कहा जाता है कि हम इसके द्वारा बहुत नहीं बचा पाते, लेकिन जितनी थोड़ी भी बचत होती तो हम यह जो छोटा सा अनुदान जन स्वास्थ्य का है, शायद इसको कुछ और आगे बढ़ा सकते थे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे स्वास्थ्य मंत्री महोदय से एक निवेदन करना है इस सम्बन्ध में कि हमारे देश के अन्दर जो हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है, जो हमारे यहां की जन-स्वास्थ्य की योजना है उसे विस्तृत कर दिया जाय जिससे कि हमारे प्रदेश के ६ करोड़ और कुछ लाख आदमियों को, सबको चिकित्सा का लाभ हो सके । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर यह देखते हैं कि आयुर्वेद जो कि इस देश का बहुत प्राचीन शास्त्र है और जिसके अन्दर वैज्ञानिक ढग से भी बहुत सी चीजें है, मनुष्य के शरीर का, उसके मन और भावों का भी उसमें विश्लेषण

[श्री गंगाधर बैठाणी]

किया गया है, उसके ऊपर भी जितनी दृष्टि होनी चाहिये, उतनी दृष्टि सरकार की नहीं है जितनी सस्ती दवाइयां और जितने सस्ते सामान आयुर्वेद के द्वारा बन सकते हैं और जितनी अच्छी तरह से हम आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा की समस्या को हल कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह से एलोपैथिक ढंग से नहीं कर सकते। एलोपैथिक ढंग इसके मुकाबिले में बहुत महंगा पड़ता है और इसके अलावा एलोपैथिक ढंग से जो पेटेंट दवाइयां आती हैं वह हमारे जलवायु के हिसाब से ठीक नहीं होतीं। जब हम गढ़वाल में रहते हैं तो वहां की जलवायु दूसरी होती है और जब लखनऊ में आते हैं तो यहां की काफी गरम जलवायु है। तो हम देखते हैं कि जो दवा वहां के लिये उपयुक्त होती है वह यहां की जलवायु के अनुसार उपयुक्त नहीं होती। हम देखते हैं जैसे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि १० अंग्रेजी दवाखानों के खोलने का आगामी वर्ष में प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से १० आयुर्वेदिक दवाखानों का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर आप इन दोनों के खर्च को देखें तो मालूम होगा कि अंग्रेजी दवाखानों के लिये ६५,३०० रुपये का रेकरिंग और ५३ हजार रुपये का नान रेकरिंग खर्चा रखा गया है लेकिन आयुर्वेदिक दवाखानों के लिये रेकरिंग २४ हजार रुपया और नान रेकरिंग १० हजार रुपया है। इस तरह से लगभग एक और पांच का अनुपात है। तो इससे हम यह देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथिक दवाखाने खोलने के बजाय अगर हम आयुर्वेदिक औषधालय खोलें तो इससे ५ गुने अधिक लोगों को हम राहत पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी शिक्षा पद्धति के संबंध में भी कहनी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम इनकी शिक्षा के संबंध में भी सोच रहे हैं और वह काम भी कर रहे हैं, जैसा आपने इसका जिक्र किया हम इसको मानते हैं और बधाई भी देते हैं कि आपने स्वीकार किया कि जो आयुर्वेदिक फैकल्टी लखनऊ यूनिवर्सिटी में खोली गई थी वहां के डाक्टरों ने सहयोग नहीं किया और वह नहीं चली। उसी प्रकार से इसी तरीके को अगर हम डिपार्टमेंट के अन्दर भी रखेंगे तो जब तक आयुर्वेदिक विभाग डाक्टरों के अधीन होगा तब तक वहां भी वही नीति करती रहेगी। यह बहुत पुरानी मांग है और देश की मांग है कि आज आयुर्वेद विभाग को एक स्वतंत्र विभाग मान लिया जाय जैसे कि पिछले अनुदान के समय माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि वह इसको मानते हैं। अब उसके कालेज जो हैं उसके संबंध में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहां पर उत्तर प्रदेश के अन्दर १३ आयुर्वेदिक कालेज थे जिनको बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ने रिकगनीशन दिया था और आपने उनके पुनर्संगठन के लिये एक समिति बनायी जिसने उनमें से कुछ कालेज कम कर दिये। अब जब मैं फिगर्स की तरफ देखता हूं तो जो ५ कालेज रह गये हैं पीलीभीत के अन्दर, झांसी के अन्दर और और जगहों में उसमें प्रति वर्ष २०० विद्यार्थी आते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितनी चिकित्सा की आवश्यकता है उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो आयुर्वेदिक कालेज खत्म करने की बात है उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। लखनऊ में जैसे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज खोलने की योजना है। लेकिन जो मेडिकल कालेज लखनऊ की आज हालत है और जैसा कि माननीय भगवान सहाय जी ने बताया था कि जब तक डाक्टरों के घर पर न जाइये तब तक किसी का भी अच्छी तरह से इलाज नहीं हो सकता। शायद वही संक्रामक बीमारी हमारे आयुर्वेदिक कालेज में भी फैल जायगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगर इसके बजाय वह किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाय तो बहुत अच्छा है।

एक बात मुझे इस संबंध में और कहनी है कि अगर पहाड़ी इलाके में नहीं तो जो बनारस और अलीगढ़ में कालेज हैं अगर बनारस कालेज को ही काफी अनुदान दिया जाय और एक अच्छा आयुर्वेदिक कालेज बना दिया जाय तो शायद इससे रुपया भी कम खर्च होगा और वहां पर अच्छे ढंग से कार्य भी हो सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टी० बी० सैनिटोरियम का भी बहुत सा जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया है। टी० बी० सैनिटोरियम प्राइवेट संस्था है। भुवाली में ९८ बेड्स हैं।

फिरोजाबाद में करीब १०० बेडों की और आवश्यकता है। वृन्दाबन में २५ बेड्स के लिये अनुदान रखा गया है। इसी प्रकार मेरठ में कुछ बेड्स हैं। लेकिन उनमें जो तीन लाख रुपया रखा गया है वह बहुत कम है। प्रायः अधिकतर यह रुपया टी० बी० ऐसोसिएशन दान द्वारा इकट्ठा करती है। सरकार की ओर से उतना खर्चा नहीं होता जितना होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सीतापुर और अलीगढ़ में जो आई हास्पिटल्स हैं, अलीगढ़ हास्पिटल का मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन जहां तक सीतापुर आई हास्पटल है वहां से डा० मेहरा हमारे पहाड़ी जिलों में जाते हैं और वहां जो कटरैक्ट आदि बीमारियां हैं उनको बहुत लाभ हुआ है। इसलिये उनको जितना अनुदान इसमें दिया गया है वह बहुत कम है।

हमारे प्रदेश में संक्रामक रोग भी काफी तादाद में होते हैं। उनके निवारण से जितना काम ग्राम सभाओं के सहयोग और अन्य लोगों के सहयोग से होना चाहिये उतना नहीं हुआ है। और न सरकार उतना खर्च करने के लिये तैयार होती है।

फैमिली प्लानिंग का भी जिक्र इस पुस्तिका के अन्दर है। हमारे प्रदेश में ६ करोड़ के अलावा जितनी आबादी बढ़ेगी उनके खाने-पीने और भोजन का क्या प्रबन्ध होगा इस ओर भी हमें ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त जच्चा-बच्चा की जो बीमारियां होती हैं उससे हमारी समस्याएं और बढ़ती हैं। इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस पर अधिक ध्यान दें। जहां तक मैंने इसकी रिपोर्ट को देखा है उसमें लिखा तो बहुत कुछ गया है और वह मुनासिब मालूम होता, है लेकिन कोई खास प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा फूड एडलट्रेशन के बारे में कहना है। मुझे जिला गढ़वाल के बारे में कहना है। सरसों के तेल में मिलावट ह ती है। इसके लिये फूड एडलट्रेशन ऐक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो मिल वाले तेल बनाते हैं उन पर फूड एडलट्रेशन ऐक्ट के अन्दर कोई जुर्म नहीं होता लेकिन जो आदमी बेचता है उस पर जुर्म होता है हालाँकि उसका कोई दोष नहीं होता लेकिन उसको पकड़ा जाता है। इसलिये फूड एडलट्रेशन ऐक्ट को संशोधन करने की जरूरत है।

गढ़वाल जिले में टॅचर कार्ड के नाम से दवा बिकती है। जिले के अधिकारी उसके लिये परमिट देते हैं। उसमें शराब से भी ज्यादा एलकोहल होता है और लोगों को नुकसान होता है। एक तरफ तो प्राहिबिशन किया जाता है लेकिन दूसरी तरफ मेडिकल एड के नाम पर ऐसी चीजों के परमिट्स दिये जाते हैं जो बड़ी नुकसानदेह हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक बात मुझे माननीय मंत्री महोदय से मुझे और कहनी है कि केदार नाथ-बद्रीनाथ रोड पर जिस तरह से काम किया गया है उसके लिये मैं बधाई देता हूं लेकिन फिर भी वहां बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री वहां जायेंगे और उसे देखेंगे।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी (जिला कानपुर)––श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा श्रीमान् स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जिस योग्यता और कुशलता से उन्होंने साल भर से इस विभाग का कार्य किया है और साथ ही उनके कर्मचारियों ने भी इस विभाग में काम करते हैं उन्होंने भी मेहनत और कुशलता से कार्य किया है उन्हें भी बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी अपने विभाग के ऐसे कर्मचारियों को साथ रखा है जो बहुत ईमानदारी से और वफादारी से काम करते हैं। किसी भी देश के स्वास्थ्य की जांच वहां की इस बात पर मुनहसर

[डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी]

रहता है कि वहां पर मृत्यु की संख्या बढ़ती है या घटती है। एक्सपैक्टेंसी आफ लाइफ गिर गया है। आया लोगों को आयु को बढ़ाने का ख्याल रहता है या घटाने का। वहां पर वबाई बीमारी घटती है या बढ़ती है। अगर इस पैमाना पर देखा जाय तो आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश में वबाई बीमारी बराबर घटी है और एक्सपैक्टेंसी आफ एज बराबर बढ़ा है। हमारे यहां मृत्यु का हिसाब १० साल पहले १८ फी हजार का हिसाब था लेकिन अब १० का हिसाब रह गया है जिससे यह मालूम होता है कि यहां पर मौतें बहुत कम हुई हैं। आपको यह मालूम होगा कि वबाई बीमारी किस कदर कम हुई है। एक जमाना था कि यहां पर जब कोई मेला होता था तो इस सूबे के करीब-करीब सारे जिले में डिपार्टमेंट काम करते थे कि कहीं पर मेले के बाद हैजा न फैले। हर शख्स उसकी तैयारी करता था कि कहीं पर बीमारी न फैले। लेकिन आपने देखा कि बड़े-बड़े मेलों में अब हैजा नहीं फैलता है। हरद्वार का कुम्भ हुआ वहां पर भी ऐसा इन्तजाम किया गया कि बीमारी नहीं फैली। अभी इलाहाबाद में इतना बड़ा कुम्भ हुआ लेकिन इस तरह का वहां पर सफाई का इन्तजाम था जिसकी वजह से कोई वबाई बीमारी नहीं फैल सकी। मुझे कानपुर के लोगों से बात करने का मौका मिला और एक साहब जो गवर्नमेंट के बहुत क्रिटिक थे और हादसे के तो बहुत ही क्रिटिक थे लेकिन वह भी इस बात को मानते थे कि यह बात ठीक है कि वहां पर सफाई का इन्तजाम बहुत अच्छा था। उन्होंने बताया कि वहां पर सफाई का इन्तजाम इस कदर अच्छा था कि जिसकी वजह से कोई मक्खी तक नहीं थी। वह बहुत बुर्जुग आदमी थे जो यह बात कह रहे थे। इस वजह से मैं उनके कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने होशियारी और कुशलता के साथ और वफादारी के साथ इस काम को किया और इसके अलावा और जो कुछ सरकार ने किया वह काबिले तारीफ है। किसी गांव की तरफ आप चले जाइये तो पहले ऐसा मालूम होता था कि लोग बीमार हैं और तिल्ली हो गई है लेकिन आज यह चीजें देखने में बहुत कम आती हैं। टयूबरकोलोसिस के केसेज में काफी इजाफा हुआ है। करीब २०,१५ गुना। खास तारीफ की बात यह है कि जितना रुपया इस डिपार्टमेंट को मिलता है वह इस कदर कम मालूम होता है कि इसके लिये काफी नहीं है। खुद मंत्री साहेब ने इसे माना है। जब हमारी केन्द्रीय सरकार ने रुपया हर जगह हर काम के लिये दिया है करीब ११२ करोड़ के तो हमारे प्रान्त को केवल ११,१२ करोड़ ही दिया जबकि हमारा प्रान्त सबसे बड़ा है। कहा जाता है कि हैल्थ एक सेकिंड लाइन आफ डिफेंस है। आपने देखा कि केन्द्रीय सरकार के डिफेंस में ४ अरब रुपये में से २ अरब सिर्फ डिफेंस के लिये रखा गया है तो जब यह सेकिंड लाइन आफ डिफेंस है तो इसके लिये अधिक रुपया मिलना चाहिये था लेकिन हमारे यहां नहीं मालूम क्यों फाइव ईयर प्लान में भी डिपार्टमेंट सबसे पीछे रखा गया है और इसमें रुपया बहुत कम रखा गया है।

दूसरे मुल्कों में बजट के टोटल एक्सपेंडीचर का २५,३० परसेंट स्वास्थ्य के लिये रखा जाता है लेकिन यहां सिर्फ पांच परसेंट हमको मिलता है। पहले ४·९ परसेंट खर्च था जब कि हमारी आय कम थी और बजट में रुपया कम था। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये ज्यादा रुपया रखना चाहिये। मैं दो एक बातें और अर्ज करना चाहता हूं। कानपुर में हमारी १३ डिस्पेंसरीज हैं उनमें जितने मजदूर जाते हैं और उनमें काफी बीमार टी० बी० के निकलते हैं। ऐसे मरीज बेचारे न तो फैक्टरी में ही जा सकते हैं क्योंकि उनको सार्टीफिकेट नहीं मिल सकता और न उनके इलाज और रहने का ही कोई ठीक ठिकाना होता है। अभी ८ तारीख का वाकया है कि एक जवान आदमी मिट्टी का तेल डालकर यहां मर गया क्योंकि कहीं रहने की जगह उसको नहीं थी, घर वाले भी उसको नहीं रखते थे, मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े अस्पताल चाहे न बनायें जायं लेकिन थोड़े खर्चे से उनका रहने का इन्तजाम कर दिया जाय।

कानपुर में मेडिकल कालेज के लिये भी बहुत दिनों से मांग है। कानपुर में यह सबसे कम खर्चे में हो सकता है। वहां पर अस्पताल मौजूद हैं, सब इंतजाम है इसलिये थोड़े से रुपये

में ही वहां पर मैडिकल कालेज स्थापित किया जा सकता है । फीमेल अस्पतालों की भी जरूरत है । इसके अलावा रिफ्रेशर्स कोर्स भी होने चाहिये । वैद्य और डाक्टरों के लिये ये कोर्सेज रखे जांय तो बहुत लाभ हो सकता है ।

प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में हर साल ही मैं कहता हूं । प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाय तो लोगों को बहुत सुभीता हो सकता है और उसके बजाय डाक्टरों को, जिस प्रकार सर्जरी में कुछ परसेंटेज दिया जाता है, उस प्रकार से दे दिया जाया करे । जब तक प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द नहीं होगी तब तक गरीब लोग 'सफर' ही करते रहेंगे क्योंकि डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस का समय ही नहीं मिलता है । मेरा ख्याल है कि यह किया जा सकता है । अच्छे वार्डस अस्पतालों में बढ़ाये जांय ।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---श्री मान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूं कि आज आपने इस अनुदान पर एक महिला को बोलने का सबसे प्रथम अवसर दिया । श्रीमन्, आज इस भवन में जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है वह इस प्रदेश के लिये बहुत महत्व पूर्ण हैं । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूं और साथ ही उनके साथ अपनी सहानुभूति भी प्रगट करती हूं कि यह अनुदान वास्तव में प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत ही कम है । जिस प्रकार जीवन में खाने पीने तथा बेअर नैसेसिटीज का स्थान है उसी प्रकार से मनुष्य के लिये स्वास्थ्य का प्रश्न उसके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसके लिये यदि और अधिक अनुदान रखा जाय तो अधिक अच्छा होता । इतने बड़े प्रदेश के लिये केवल इतनी ही अनुदान संख्या वाकई में बड़े खेद का विषय है और यह खेद तब और भी अधिक बढ़ जाता है जब कि उसमें एक बहुत ही थोड़ी मात्रा में रुपया स्त्रियों के स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है और यह माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं अपने मुखारबिन्द से स्वीकार किया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही कम खर्च किया जाता है । उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि इस प्रदेश में ६७ शिशुपालन-गृह खोले गये हैं । जहां पर और अस्पताल का विषय आता है वह मैं सोचता हूं कि कई अंशों में वह इस संख्या से बढ़कर हो जाती है ।

अब मैं एक सवाल आपके सामने और रखना चाहती हूं । यहां की जो चिकित्सा-प्रणाली है वह बड़ी दोषपूर्ण है । हम आज विदेशों से दवायें मंगाने में बहुत से रुपये खर्च करते हैं किन्तु यदि हम आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनावें तो हमारा बहुत सा रुपया अच्छे कामों में उपयोग हो सकता है । मैं अपने अनुभव से बता सकती हूं कि न केवल हमारे देश और प्रदेश का रुपया बेकार जाता है बल्कि हम अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को भी इस चिकित्सा से खराब करते जा रहें हैं । इंजेक्शंस से हमारे स्वास्थ्य पर बाद में जो असर पड़ता है उससे सारी उम्र ठीक होना मुश्किल होता है । यदि हमारे यहां प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया जाय और जगह-जगह उसके सेन्टर्स खोले जांय तो बहुत सी समस्या स्वास्थ्य की हल हो सकती है । दूसरा प्रश्न आयुर्वेदिक चिकित्सा का आता है। आज भी हमारे पर्वतीय प्रदेशों में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके प्रयोग से हजारों रुपया जो बाहर से दवायें मंगाने में खर्च होता है और देर भी लगती है वह बचाया जा सकता है । यदि इस विषय को योजनानुसार कार्यान्वित किया जाय तो बहुत सा रुपया हमारे प्रदेश का दूसरे कामों में आ सकता है। मैं यहां पर अधिक न कह कर केवल एक बीमारी का जिक्र करती हूं। हमारे यहां आज कल एक बीमारी पथरी की चलती है। हमारे बहुत से लोग आपरेशन के वक्त अपनी जान से हाथ धोते हैं । इसके लिये आयुर्वेदिक में एक पत्थरतोड़ पत्ता पाया जाता है जो हमारे यहां पहाड़ों पर मिलता है । उस पत्ते से पत्थर पर लाइन खींचना चाहें तो खींच सकते हैं इसी तरह से अगर उस पत्ते का पथरी की चिकित्सा में प्रयोग किया जाय तो ऐसा प्रसिद्ध है कि पथरी उसके प्रयोग से टुकड़े-टुकड़े होकर गिर जाती है । और इसी तरह से एक बड़े भयंकर रोग से मुक्त किया जा सकता है । इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं और बड़े-बड़े कष्टों से

[श्रीमती चन्द्रवती]

निवृत्ति पा सकते हैं। इसके बाद होमियोपैथिक की समस्या है। एक साल के लगभग हो चुका लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर अगर ध्यान दिया जाता तो मैं समझती हूं कि चिकित्सा सम्बन्धी जितनी आवश्यकताएं हैं उनको देहाती क्षेत्रों में भी पहुंचा सकते थे और इलाज का मूल्य भी कम हो सकता था। हमारे जो अस्पताल आज हैं उनमें थोड़ी सी व्यवस्था इसकी भी एक होमियोपैथिक डाक्टर रख-कर कर दें तो बहुत हद तक इस सम्बन्ध में काम हो सकता है।

अब तीसरा सवाल देहाती क्षेत्रों में दाइयों की ट्रेनिंग के लिये सेंटर्स खोलने का आता है। उसमें मेरा सुझाव है कि जितनी दाइयां आज गांवों में अनाधिकार चेष्टा किया करती हैं जच्चा-बच्चा के सम्बन्ध में अगर उनको ट्रेनिंग देने के बाद लाइसेंस दिया जाय तो सरकार को भी उससे आमदनी होगी और एक बड़ी समस्या देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा की हल हो सकती है। अब इसके सम्बन्ध में मेरा एक दूसरा विचार सुझाव के रूप में सदन के सामने आता है। मंत्री महोदय ने इस भवन में यह भी बतलाया कि प्रदेश में नर्सिंग और मिडवाइफ की बहुत कमी है क्योंकि बहुत सी बहनें इस क्षेत्र में आना नहीं चाहती। उसके बहुत से कारण हैं सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन या प्रचार भी तो नहीं कर रही है। अगर आप इसके प्रचार के लिये साहित्य बांटे और स्कूलों में यह कम्पलसरी एजूकेशन रख दी जाय जैसे कि मिलेटरी एजूकेशन कमपल्सरी कर दी गयी है तो मैं समझती हूं कि इससे काफी प्रचार हो सकता है और इस तरह से यह प्रश्न जो कि अत्यन्त गम्भीर है हल हो सकता है। हमारी बहुत सी बहनें इस लाइन में आना चाहती हैं परन्तु यह जरूर है कि महिलाओं द्वारा इसका कार्य हो। मैं मन्त्री महोदय को इसके लिये बहुत हद तक मदद कर सकती हूं। यदि उन्हें और भी सुविधा दी जाय तो उनमें बहुत सी बहनें प्रोत्साहित हो कर आ सकती हैं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे।

देहातों में एक समस्या और आती है। हमारे यहां बच्चों के जो रोगी होने की शिकायत होती है उसमें मैं सोचती हूं कि जितना होमियोपैथिक इलाज उपयोगी हो सकता है उतना और कोई इलाज उपयोगी नहीं हो सकता है। अगर ऐसे बच्चों के रोगों के लिये और निवृत्ति के लिये अगर होमियोपैथिक का प्रोत्साहन दिया जाय तो इस समस्या का भी बहुत हद तक हल हो सकता है।

इस के अतिरिक्त हमारे यहां अन्धों की समस्या भी बहुत गम्भीर है। हमारे देश में जो अन्धे हैं उनमें अगर देखा जाय तो अधिक मात्रा में स्त्रियां ही पाई जायेंगी। इसका भी एक कारण है। सबसे पहले तो मैं यह चाहूंगी कि हमारे देश से डालडा का पूर्ण बहिष्कार किया जाय। इसकी वजह से देश में अन्धों की संख्या अधिक बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां खाना बनाने की व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है। खाना बनाने की व्यवस्था में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देहातों में जंगलों के कट जाने की वजह से लकड़ी की एक बहुत बड़ी समस्या हो गयी है।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में माननीय मंत्री महोदय का जो भाषण हुआ उसमें इस देश में चिकित्सा पद्धति के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक इन तमाम व्यवस्थाओं की चर्चा की गई। मैं इस संबंध में एक विचार माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं कि यदि देश के स्वास्थ्य का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि हमारा देश स्वतंत्र है तो मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि हजारों पद्धतियों को निर्मूल कर केवल एक पद्धति चाहे वह एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होमियोपैथिक हो या यूनानी हो, इस देश में लागू होनी चाहिये। यह बड़ी अजीब सी बात है कि एलोपैथिक, यूनानी या होमियोपैथिक इन सब पद्धतियों का केवल मन रखने के लिये एक पुरानी ट्रेडिशन जो चली आ रही है, उनकी सहायता करना मेरे ख्याल में हमारे देश के लिये अनुकूल नहीं है। मैं इसलिये चाहता हूं कि अनुसंधान से देश के वातावरण के अनुकूल, स्वास्थ्य के

अनुकूल, अर्थ के अनुकूल, इकोनामी के अनुकूल जो भी पद्धति आप उचित समझते हों साहस के साथ, दृढ़ता के साथ चाहे वह एलोपैथिक पद्धति हो, चाहे आयुर्वेदिक पद्धति हो, चाहे यूनानी पद्धति हो, चाहे होमियोपैथिक पद्धति हो, या सब का सम्मिश्रण करके एक पद्धति निकालिये ताकि एक ही कारखाने में दवाइयां बन सकें, एक ही फारमेसी में उनका उपयोग हो सके और एक ही तरह के डाक्टर इलाज कर सकें। एक ऐसी पद्धति का आप इन्तजाम करें, उसका इस देश में इंट्रोडक्शन करें और उसको इस देश में कार्यरूप में लायें और चलायें। इन चारों पद्धतियों के रहने से न केवल रुपया बरबाद होता है बल्कि जनता का विश्वास भी जाता रहता है। हम नहीं जानते और कभी कभी परेशानी हो जाती है कि इस डाक्टर के यहां जायं या उस सिस्टम वाले डाक्टर के यहां जायं। स्टेट का पैट्रनेज पहले अंग्रेजी हुकूमत में एलोपैथिक को मिलता था। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारा विश्वास कई दिशाओं में डिवाइडेड है। जब तक हम एक मन से एक निष्ठा से एक पद्धति को प्रश्रय नहीं देंगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पद्धति हमारे देश में उन्नति नहीं कर सकेगी। जब माननीय मंत्री जी भाषण कर रहे थे तब हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने जर्राहों का नाम क्यों छोड़ दिया। वास्तव में बहुत से सदस्यों का इस सदन के भीतर और इस सदन के बाहर ऐसा विचार हो रहा है कि हमारी सरकार इस दिशा में एक भूल सी कर रही है और वह यह है कि सब का मन रखने के लिये कि एलोपैथिक वाले लोग कहीं नाराज न हो जायं, यूनानी वाले लोग कहीं नाराज न हो जायं जो यह किया जाता है कि इसको भी देख लें और उसको भी देख लें, इससे किसी एक दिशा में हम पूर्ण शक्ति के साथ और निष्ठा के साथ उन्नति नहीं कर रहे हैं और न कर पा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि साहस के साथ, दृढ़ता के साथ और निष्ठा के साथ इस संबंध में अनुसंधान करके जो भी सिस्टम हो या चारों सिस्टम को मिला करके एक सिस्टम को स्थापित किया जाय और उसी को इस देश में कार्यान्वित किया जाय। मैं समझता हूं कि इससे न केवल रुपया बचेगा बल्कि हमारी उन्नति भी एक दिशा में तेजी के साथ हो सकेगी। मैं इसी सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का बजट मेरे ख्याल में बहुत रुपयों का तकाजा नहीं करता, इसमें बहुत ज्यादा रुपये की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज्यादा अस्पतालों की भी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें टेंडेंसी की, हैबिट्स की और सिस्टम्स की आवश्यकता हुआ करती है। ऐसी हालत में हमारा स्वास्थ्य बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। हमारा वातावरण स्वच्छ है या नहीं, हमारी टेंडेंसीज और हैबिट्स ठीक हैं या नहीं, यदि हैं तो मेरा ख्याल है अस्पताल और दवाखानों की बातें सिकेंड्री बातें हो जाती हैं, बहुत सी बातें आप से आप फालो करती हैं। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा अभी माननीय सदस्या श्रीमती चन्द्रवती जी ने कहा है कि हमारे फूड सिस्टम में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे घरों में हमारी जो हैबिट्स सदियों से बन गयी है कि घरों में इस तरह से भोजन बनता है और इस तरह से खाया जाता है कि वह बरबाद हो जाता है। अच्छे-अच्छे लोग जिन को अच्छा भोजन मिलता है उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उसका एक ही कारण हो सकता है और वह यह है कि हमारी हेबिट्स फूड के बारे में, खाने के बारे में, खाना पकाने के बारे में, और स्वाद के बारे में ठीक नहीं है। मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि सरकार जो शक्ति का एक केन्द्र हुआ करती है वह इस बारे में एक सिस्टेमेटिक आन्दोलन चलाये और जिस प्रकार वह अन्य दिशाओं में स्रोत बहाया करती है, उसी प्रकार इस दिशा में भी एक स्रोत बहाये। फूड के संबंध में एक बड़े भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। अडल्ट्रेशन के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पारसाल और परियार साल बजट के सिलसिले में अडल्ट्रेशन की चर्चा हो चुकी है। लेकिन इस संबंध में हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखायी पड़ रहा है। आजकल हमारा जीवन ऐसा घुमक्कड़ हो गया है कि कभी हम इलाहाबाद में होते हैं, कभी आजमगढ़ में होते हैं कभी देवरिया में होते हैं, और हर जगह हम भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमें होटलों पर निर्भर होना पड़ता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि अडल्ट्रेशन के संबंध में आप एक सख्त नीति अपनायें। अभी इस सिलसिले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इससे हमारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और जो खाने का व्यापार करते हैं वे बड़ी निर्दयता के साथ हमारे स्वास्थ्य के साथ व्यापार करते

[श्री पद्मनाथ सिंह]

हैं और हम चौपट होते जाते हैं। इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि एक निश्चित कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं पापुलेशन के संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं। जितनी इस संबंध में योजनायें बनी हैं वे अपर क्लास को टच करती हैं। जो स्वयं जागरूक हैं वहां तो पापुलेशन कम हो रहा है लेकिन नीचे के वर्ग में हम न तो इसका प्रचार पहुंचा सकते हैं और न ये सुविधायें उनके यहां पहुंचा सकते हैं और पापुलेशन की बहुत ज्यादा वृद्धि वहीं हो रही है। छोटे से छोटे तबके में चले जाइये तो उनके पास इसकी कोई सूचना नहीं है, कांशेसनेस ही नहीं है मैं प्रार्थना करूंगा कि उस वर्ग में प्रचार की जो भी व्यवस्था आप कर सकें उसको करें।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान पूर्वक सुनता रहा और कुछ हंसी भी आती थी इस बात को सुन कर कि हमारे माननीय मंत्री अपने आंकड़ों पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे हैं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि दो या तीन वर्ष पूर्व थानों में बर्थ और डेथ रजिस्टर्स रहा करते थे और जब से गांव सभायें स्थापित हुई हैं उनके सुपुर्द यह कार्य कर दिया गया है। गांव सभाओं में क्या जन्म और क्या मत्यु जिस तरह से लिखी जाती हैं यह मुझे ही नहीं बल्कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को भली भांति मालूम है। कहीं तीसरे या चौथे महीने जब सेक्रेट्री महोदय आये तो उन्होंने पूछा और पूछ कर अगर कहीं पता चला और उनको तकलीफ और जहमत नहीं हुई तो एक नाम लिख दिया और नहीं तो बहुत सी ऐसी भी गांव सभायें हैं जहां उस रजिस्टर पर कोई भी इन्दराज नहीं है। और उसी के आधार पर माननीय मंत्री जी इन्फेक्शस डिजीजेज के बारे में बहुत कुछ अपने को प्रसन्न कर सकते होंगे। लेकिन, श्रीमन्, मैं आपके जरिये उनको निहायत अदब के साथ यह बतलाना चाहता हूं कि यह उनके लिये भ्रम हो सकता है और एक ऐसा आधार हो सकता है कि जिस पर यदि वह भरोसा करना चाहेंगे तो उनको कोई रोक तो नहीं सकता लेकिन वह कार्यकारी नहीं हो सकता है। बहुत सी बातें जो सही हैं उनको मैं तसलीम भी करता हूं, जैसे मलेरिया और टी० बी० के बारे में माननीय मंत्री ने बहुत कुछ उन्नति की है। लेकिन जब मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर की तरफ हम देखते हैं तो मैं एक देहाती क्षेत्र का रहने वाला हूं और यह समझ सकता हूं कि जहां पर उनके सेंटर्स हैं वहां मिडवाइफ तो कभी होती ही नहीं हैं और अगर मौजूद भी हों तो गांवों में जाना उनके लिये कभी मुनासिब होता ही नहीं है। मेरे ख्याल में मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर जो कुछ किया जा रहा है वह महज उनको सुनाया जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि आपके लिये सरकार का धन व्यय हो रहा है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि सरकार उस धन का दुरुपयोग कर रही है। या तो ये सेंटर्स न रखे जायं और अगर रखे जाते हैं तो भली-भांति देखभाल होनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि जो रुपया हमारे माननीय मंत्री जी सर्फ कर रहे हैं उससे किस प्रकार उन गरीब किसानों को फायदा पहुंचता है। मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पतालों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फैजाबाद जिले में एक बीकापुर डिसपेंसरी है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन है। श्रीमन्, मैं आपसे सच कहता हूं कि इस सदन के सामने की तीन महीने तक वहां के डाक्टर ने पानी पिला-पिला कर लोगों को जीवित रखा और उनको विश्वास दिलाता रहा कि मैं दवा देता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---बहुत अच्छा है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---एक सदस्य कह रहे हैं बहुत ठीक है।

श्री नेकराम शर्मा---विश्वास की बात है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---यह ठीक है, लेकिन रुपया तो नहीं जाना चाहिये। आप पानी पिलाइये तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर खर्चा तो न हो।

---

*यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

इसके बाद होमियोपैथिक या यूनानी या आयुर्वेदिक के संबंध में इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इसके लिये जो भी उन्नति सरकार कर सके उसे करनी चाहिये यह मैं मानता हूं कि हर जगह एलोपैथिक के साधन उपलब्ध होना कठिन हो सकता है। पन्तु अगर होम्योपैथिक यूनानी और वैद्यक को प्रोत्साहन दिया जाता है तो बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। फैजाबाद जिले की मैं एक सही बात बताना चाहता हूं जिससे उस पक्ष के लोगों को गौरव होना चाहिये। निमोनिया के मरीजों को दिसम्बर और जनवरी के महीने में बाहर लिटाया हुआ था। इस तरफ तो स्ट्रेपटोमाइसिन चल रही थी और दूसरी तरफ यह हालत थी कि उनको बाहर लिटाया हुआ था। उनके लिये परदों का भी कोई इंतजाम नहीं था चाहे वह टाट के होते या कपड़ों के। किसी भी तरह से उनकी हिफाजत हो सके।

श्रीमन्, मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं यह नहीं समझता कि हर मेले में इनाकुलेशन आवश्यक समझा जाता था लेकिन यह कुम्भ मेले में हटा दिया गया। जब सब जगह यह उचित साबित हुआ तो माघ मेले में क्यों हटा दिया गया, वह असंगत बात या विरोधाभास को वही समझ सकते हैं या फिर उनके पक्ष के लोग समझ सकते हैं जो खुशामद में रहते हैं और चाहते हैं कि मंत्री महोदय खुश रहें।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)––अध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान आज उपस्थित हुआ है और हमारे मंत्री महोदय ने बड़ी लग्न और परिश्रम के साथ इस विभाग को संचालित किया है जिस पर हमारे प्रांत के सारे बुड्ढे और बच्चों का जीवन निर्भर करता है। माननीय मंत्री जी की केवल इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है उनकी जिम्मेदारी खाद्य से भी है और जो हमारे शरीर की बनावट है वह इन दोनों के ऊपर चलती है। जिस तरह से कि हमारे जीवन के लिये अन्न और वस्त्र की जरूरत होती है उसी तरीके से भी दवा की भी जरूरत होती है। मंत्री महोदय ने जिस समय हमारे प्रांत के इस विभाग का भार अपने ऊपर लिया उस समय सबको विदित है कि हमारा देश किधर का किधर जारहा था और कितनी बुरी तरह से हमारा राज्य गड्ढे में फंसा हुआ था और जिस क्षेत्र से मैं आया हूं यानी हमारे पूर्वी जिलों में नाना प्रकार के उपद्रव मचे हुये थे यानी अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि नाना प्रकार के उत्पात हमारे जिलों को दबाये हुये थे। फिर भी हमारे मंत्री जी ने बड़ी खूबी के साथ, उस समय जब कि बाढ़ आई हुई थी, क्षण-क्षण में जहां जरूरत हुई, तो दवा का उसी समय प्रबन्ध किया।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरे जिले की एक तहसील खलीलाबाद के एक मौजे में जिसकी आबादी ४००० है उसमें से करीब दो हजार बीमार हो गये। मैंने माननीय मंत्री जी को जब इसकी सूचना दी तो उन्होंने वायरलैस से जिलाधीश को सूचना दी और दूसरे रोज ही डाक्टर वगैरा दवा वगैरा लेकर वहां पहुंच गये। वहां का वह एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ है और मैं उसके संबंध में इतना ही कह देना चाहता हूं कि यह एरिया आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश सल्तनत के जमाने से पिछड़ा हुआ है। मैंने मंत्री महोदय की इधर निगाह डलवाई कि उस पर ध्यान दें। उन्होंने वायदा भी किया लेकिन पता नहीं कि मंत्री महोदय किस रास्ते से भूल गये कि आज तक उन्होंने इधर जरा भी ध्यान नहीं दिया और यह एरिया एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे और साथी जो माननीय सदस्य हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया करते हैं कि अब क्या हो सकता है और क्या होकर रहेगा। इन क्षेत्रों के लिये जो सदियों से पिछड़े हुये हैं जिनमें भुखमरी से तबाही है, कपड़े और अन्न के बिना तबाही है और नाना प्रकार के उपद्रवों से तबाही है, यह कहना ठीक था उस जमाने में लेकिन आज जब कि हम एक ऐसे शासन के अंग हैं जो जनतांत्रिक शासन है। आप हर क्षेत्र की बात देखते हैं इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां जाकर देखें और वहां देखें तो ठंडे हृदय से देखें तो मैं कहूंगा कि उनके हृदय पर एक आघात होगा, एक हूक उठेगी और इतना दर्द

[श्री धनुषधारी पांडेय]

होगा उनके दिल के अन्दर यह भावना पैदा होगी कि या तो मैं रहूं या अपने जीवन को दूसरे जीवन में बदल दूं। मैं तो देखता हूं कि जिस वक्त बाढ़ आई थी, वहां पर एक एक गांव में एक-एक हजार आदमी बीमार थे। अगर ऐसी अवस्था है तो लोग क्या करें? आप अपनी परिस्थिति बता सकते हैं। लेकिन मेरी डबल कांस्टिट्युएंसी है, ३ लाख की आबादी है और सरजू और कुंवानो नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें डेढ़ लाख की आबादी है, लेकिन कोई दवा का प्रबन्ध नहीं था। लेकिन मैं दावे के साथ कहूंगा कि जिस वक्त मैंने मंत्री जी को सूचना दी तो उन्होंने फौरन उसके लिये प्रबन्ध किया। लेकिन स्थायी प्रबन्ध कोई नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

एक अपील यह है कि माननीय मंत्री जी जिस तरह से शहरों की ओर ध्यान देते हैं वैसे ही देहातों के लिये भी करें। शहरों के लिये कदम-कदम पर, मुहल्ले-मुहल्ले में अस्पताल खुले हैं और शहरों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बातों को सुनकर और खोल दिये जाते हैं। मैं सुनता हूं जब कहा जाता है कि कानपुर मे एक मेडिकल कालिज खोल दिया जाय, तो क्या गोरख पुर डिवीजन उनके प्रान्त का नहीं है? वहां न खोला जाय? और बनारस डिवीजन में क्यों न खोला जाय और बस्ती के अन्दर? कानपुर और लखनऊ में जहां पर अच्छे-अच्छे अस्पताल हैं और जहां अच्छे-अच्छे प्रैक्टीशनर मौजूद हैं, वहां मेडिकल कालिज खोलने की मांग की जाती है और उन जिलों में जहां के देहातों में एक भी डाक्टर नहीं है वहां कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर न्याय की प्रथा को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो न्याय पर आवें और अगर सचमुच जाना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि चार पांच सदस्य जाकर निरीक्षण करें। मैं यह नहीं कहता कि उन पिछड़े हुये इलाकों के सदस्य ही रहें, बल्कि उन सारे जिलों के सदस्य रहें जो आगे हैं। वह जायं, निरीक्षण करें और तौल कर देखें और जो वास्तविकता है उसको मानें और वह भी मानें जिनके हाथ में बागडोर शासन की है। जिस तरह से हमारे पूर्वी जिले तिरस्कृत हैं उनको देखते हुये यह अनुचित न होगा यदि मैं इस मांग को करूं कि जो पूर्वी और पिछड़े हुये जिले हैं उनका एक दूसरा ही प्रोविंस बना दिया जाय। क्योंकि और जगह से भी हमारे देश के अन्दर यह आवाज आई और उनकी मांग पूरी करायी गयी और वह चमकती हुई निकली, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के रहते हुये कदापि आशा नहीं करता कि यह मुझे यह मांग करनी पड़ेगी। वह अवश्य हमारी दशा की ओर ध्यान देंगे कि किस तरह से वहां मलेरिया छाया हुआ है।

श्री धर्मदत्त **वैद्य** (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा इस सदन के सामने उपस्थित किया गया है मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। हमारा यह प्रदेश इस देश के अन्दर इस कार्य में अग्रणी है। अगर हम पिछले वर्षों को उन रिपोर्टों को देखें जो चिकित्सा सम्बन्धी कार्य हमारे इस प्रदेश के अन्दर किया गया है और जितनी प्रगति की है, तो मैं यह कह सकता हूं कि हमारा प्रदेश इस कार्य में बहुत आगे बढ़ा है।

हमारे इस प्रदेश में सब से पहले देशी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन दिया गया। बोर्ड आफ़ इंडियन मेडिसिन का सब से प्रथम इसी प्रदेश में जन्म हुआ और उसके द्वारा देशी चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिए बहुत से प्रयत्न किये गये और आज ५३० देशी चिकित्सालय इस प्रदेश के अन्दर चल रहे हैं। इस प्रदेश में आयुर्वेदिक कालिजों की संख्या भी बहुत अधिक है और उसका पाठ्यक्रम और प्रदेशों से अधिक अच्छा है। आज हमारे प्रदेश को बहुत से अन्य प्रदेश नकल कर रहे हैं। अब केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ है। आज देशी चिकित्सा पद्धति की स्थापना में हमारे प्रदेश ने जो कार्य किया है उसकी और प्रदेश के लोगों ने प्रशंसा की है। हम एक स्टेट फ़ारमेसी भी चला रहे हैं। यह सब कुछ होते हुए भी मैं इस माननीय सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के सम्बन्ध में यह धारणा बन गयी है कि यह प्रदेश आयुर्वेदिक या देशी चिकित्सा पद्धति की उन्नति करना चाहता है उसके उत्थान के सम्बन्ध में उसका विशेष ध्यान है हम इस धारणा

को कम करना नहीं चाहते किन्तु प्रत्येक वर्ष जो बजट में अनुदान रखा जाता है उससे हमारी यह धारणा शिथिल पड़ जाती है। आज इस कार्य के लिए इस सदन में प्रस्तुत बजट ३ करोड़ ६५ लाख रुपये का है किन्तु देशी चिकित्सा पद्धति के लिये सिर्फ ३०, ३५ लाख रुपया रखा गया है। हम ५३० आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय राज्य की ओर से चला रहे हैं और मेरा यह विश्वास है कि इन चिकित्सालयों के द्वारा हम इस प्रदेश की अधिक से अधिक जनता को लाभ पहुंचाते हैं और कम से कम व्यय इस पर होता है। आज एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा एक रोगी पर जब दो आना, ढाई आना व्यय होता है तब देशी चिकित्सा पद्धति का व्यय दो पैसे या तीन पैसे पड़ता है। इस प्रकार से हम कम से कम पैसे खर्च करके अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। जो चिकित्सालय स्टेट की तरफ से हमारे प्रदेश में खुले हुए हैं उन जगहों पर डाक्टर लोग किसी भी तरह से नहीं रह सकते। ऐसे-ऐसे बीहड़ इलाके जहाँ तीन-तीन नदियां बहती हैं वहाँ एम०बी०बी० एस० पास डाक्टर लोग नहीं टिक सकते जब कि वहाँ वैद्य और हकीम लोग रहकर वहाँ के लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। किन्तु हमें देखना यह है कि जिस प्रकार से आज हमारे प्रदेश में डाक्टरों की संख्या कम है और सरकार की ओर से बार-बार यह बात कही जाती है कहीं भी डाक्टरों की मांग होती है या शिकायत होती है तो सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि डाक्टरों की कमी है, हमें तो सन्देह है कि इसी प्रकार से कहीं वैद्यों और हकीमों की भी कमी न होने लग जाय क्योंकि आज हम आयुर्वेद की शिक्षा पाने वालों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। आज हाई स्कूल पास करने के बाद जब आयुर्वेद पढ़ने के लिए आता है तो उसको ५ वर्ष का कोर्स करना पड़ता है। जो सरकार की तरफ से बोर्ड आफ मेडिसिन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है वह ५ वर्ष में पूरा करने के बाद वह स्नातक की डिग्री प्राप्त करता है किन्तु उसे जो वेतन मिलता है वह ग्रेजुयेट के अनुपात का नहीं होता। जब कि एक सैनिटरी इंस्पेक्टर जो कि हाई स्कूल के बाद एक साल की ट्रेनिंग का कोर्स पूरा करके उससे अधिक वेतन पा सकता है तो उन्हें इतना अल्प वेतन क्यों दिया जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है और इस सदन का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में हमारी सरकार की नीति यह है कि वह इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देना चाहती है, इसे आगे बढ़ाना चाहती है तो वह इसके साथ खिलवाड़ न करे। इस प्रकार ३०,३५ लाख रुपया बजट में रखकर के और ५० हजार रुपये में एक कालेज की बात को सामने रखकर के हम इस पद्धति को बहुत अधिक लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। आज हमारे जो ५३० चिकित्सालय हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी इमारत हो जिसमें कि रोगी के रहने के लिए कोई व्यवस्था हो। एक ओर तो हम समानता करते हैं एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से, उन अस्पतालों से जिनमें कि २०,२०, २५, २५ या ५०,५० रोगियों के रहने की व्यवस्था है, जिनमें आधुनिक यन्त्र हैं और जो आधुनिक सज्जा से सम्पन्न है और एक ओर खाली एक वैद्य और एक कम्पाउंडर को रख करके उनकी बराबरी करना चाहते हैं। हमें सबसे प्रथम यह करना चाहिये कि वे स्थान जहाँ से जिला चिकित्सालय २०, २५ मील की दूरी पर हों, उन चिकित्सालयों में अन्तरिम रोगियों के रहने की व्यवस्था की जावे। हम वहाँ पर चिकित्सालयों को रखकर उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज हमारा यह विभाग एक दूसरे विभाग के अधीन है। यह सारा विभाग डाइरेक्टर के अधीन है जो उस विज्ञान से कुछ भिन्न विज्ञान के ज्ञाता हैं। तो इस बात की आवश्यकता है कि हम उसका एक अलग विभाग बनाएं और उनका एक डाइरेक्टर नियुक्त करें और सारा कार्य सुचारु रूप से चले। अगर जो उस विज्ञान का जाननेवाला नहीं है जो उसकी विशेषता को समझ सकता हो उसके अधीन यह विभाग चलाना है तो वह उन्नति नहीं कर सकता।

श्री कमाल अहमद रिजवी (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्टेट के रिसोर्सेज को देखते हुए हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बजट हमारे सामने रखा है वह काफी अच्छा है। परन्तु फिर भी दो एक बातों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। हालांकि मंत्री जी ने

[श्री कमाल अहमद रिजवी]

भी उधर हल्का सा इशारा किया है लेकिन वह हल्का सा इशारा काफी नहीं है। बल्कि उधर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। मेरा मतलब है फैमिली प्लानिंग से। मैं समझता हूं कि एशिया के सभी देशों और खास कर हिन्दुस्तान के लिये जहां पर रोज आबादी बढ़ रही है मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में फैमिली प्लानिंग की सख्त जरूरत है। आपसे यह बात छिपी नहीं है कि हमारे देश में गल्ले की कमी है। लाखों रुपया ग्रो मोर फूड स्कीमों पर खर्च करना पड़ता है, लेकिन हम कितना ही खर्च करें, कितनी ही पैदावार बढ़ जाय लेकिन यह समस्या तभी हल होगी जब कि हम आदमियों की तादाद पर रोक करें। कितना भी गल्ले की पैदावार बढ़े हम उस पर काबू नहीं पा सकते हैं। यह आसान काम नहीं है क्योंकि अगर प्रचार भी करें तो जनता के दिल में यह बात जमती नहीं है क्योंकि यह देश ऐसा है जहां संतान के लिए न मालूम कितने साधुओं और फकीरों की रोज चलती है जहां पर मंत्र फूंक कर बच्चा लेना चाहते हैं। इसलिये हमें पूरा जोर इसके लिए लगाना होगा। सिर्फ चौराहों पर फैमिली प्लानिंग के पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा बल्कि काफी लिटरेचर छापना होगा और न्यूजरील्स और दूसरे तरीके से जितने भी साधन हैं सब को काम में लाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि शुरू में चाय चलाने के लिए चाय कम्पनियां मुफ्त में चाय पिलाया करती थी। मेरा मतलब यह नहीं है कि फैमिली प्लानिंग के भी प्रेक्टिकल डिमांस्ट्रेशंस किये जाय। लेकिन उसी विस्तार से और उसी साइट में इसको भी होना चाहिये। जैसा कि मैंने अर्ज किया उसका प्रोपगैन्डा इस तरह से होना चाहिए कि हर आदमी उसको समझ सके। आसान भाषा में हो। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे अपने लखीमपुर अस्पताल का तजुर्बा है। वहां पर एक बक्सा रखा है जिसपर लिखा हुआ है "मूलम् मंजुशा"। मैं समझता हूं कि इसका मतलब इस हाउस में भी कोई न समझ पाया होगा। उसका मतलब है शिकायत का बक्सा। बाद में मालूम यह हुआ कि इसलिये यह लिखा गया है कि पहले शिकायतें बहुत आया करती थी। तो इसलिये शिकायतें न आया करें, शायद लोग समझें कि चैरिटी बाक्स है। इसलिए यह लिख दिया गया। अगर हमने इस तरह से प्रचार किया और जनता समझ न पायी तो कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात मैटरनिटी सेंटर्स और चाइल्ड वेलफेयर के बारे में है। अगर हमें फैमिली प्लानिंग की स्कीम नहीं चलानी है तो उसका लाजिमी नतीजा है कि हमें अधिक मैटरनिटी सेंटर्स और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। और फैमिली प्लानिंग स्कीम चलती है तो उनकी तादाद में भी कमी होगी।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आप रोजाना देखेंगे कि मस्जिद और मंदिरों की दीवारों से लेकर गिरजों के चौराहों पर, और हर जगह विनरल डिजीजेज के मुतालिक इश्तहार लगे हुए है। अगर कोई बाहर का आदमी आये तो वह यही समझेगा कि इस देश में सभी लोग विनरल डिजीजेज से पीड़ित हैं और कोई भला आदमी बसता ही नहीं है।

(इस समय ३ बज कर १० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

तो हमें इस तरफ ध्यान देना है और इन चीजों को खत्म करना है। एक किस्सा मुझे याद आता है। पता नहीं कहां तक सच है। लेडी माउंटबेटन बनारस के मन्दिरों को देखने गई थीं। बाहर निकलीं तो यही इश्तिहार लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह क्या है। पोजीशन बड़ी खराब हो रही थी तो उनको कहा गया कि ये श्लोक लिखे हुए हैं। यह बड़े शर्म की बात है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि सड़कों और दीवारों पर इश्तिहार लगाने की कोई रोक नहीं है, उसे बन्द किया जाय।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय चेयरमैन साब, आज हमारे प्रदेश में सब से बड़ी जटिल समस्या इस बात की है कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि वह इस बात के लिये ---

श्री नेकराम शर्मा---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन महोदय, को इंफुलुएंस किया जा रहा है और कुछ लिस्टें दी जा रही हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

अधिष्ठाता---इट इज नाट ए प्वाइंट आफ आर्डर। सदस्य लोग तो इस तरह से भेजा ही करते हैं।

श्री मलखान सिंह---आज हमारे प्रदेश की जो सब से बड़ी जटिल समस्या है वह जनसंख्या की वृद्धि है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय स्वशासन मंत्री को इस बात के लिये बधाई दूंगा कि वह अपना कदम अमली रूप में जनसंख्या को कम करने की ओर बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर इसीलिये कि देहातों में दवाइयों का दुर्भिक्ष फैला हुआ है जिसके कारण मृत्यु संख्या बढ़ रही है। यह भी एक कदम है जिसके कारण जनसंख्या कम हो मैं यह कह देना चाहता हूं कि शहरों में तो आज थोड़ी बहुत दवाइयां मिल भी सकती हैं लेकिन देहातों में बिना दवाइयों के लाखों आदमी हर साल मरते हैं। मुझे तो इस बात का भी ताज्जुब है कि जिस सूबे की आबादी साढ़े ६ करोड़ हो वहां डाक्टरों की तनख्वाह और औषधि वगैरह सब के लिये अनुदान हो ३ करोड़ ९५ लाख यानी १० आने फी आदमी इससे मेरी समझ में आता है कि इस काम में कि जनसंख्या कम हो वह जरूर कामयाब हो जायंगे। तो मैं यह साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि मेरे जिले में देहातों में तीन चार अस्पताल हैं जैसे जलाली, विजयगढ़, सासनी में लेकिन पानी के सिवा वहां कुछ नहीं मिलता और जो कुछ भी अनुदानें बजट में देखी हैं वे इसी बात के लिये हैं कि कुछ तो डाक्टरों को दी जा रही हैं और कुछ वैद्यों को दी जा रही हैं और अगर कहीं कुछ दिया भी जाता है तो वह सब व्यर्थ जाता है। हां, एक ही कार्य जिसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई दे सकता हूं वह है गांधी नेत्र चिकित्सालय अलीगढ़ जो बड़ी प्रशंसा का कार्य कर रहा है इस सूबे के अन्दर और इस देश के अन्दर, उसको उन्होंने यथाशक्ति जो कुछ वह दे सकते थे उसको उन्होंने इस बजट में सहायता दी।

मैं उनसे यह भी प्रार्थना करूंगा कि वह देहात से निकल कर शहर में आकर शहरी अवश्य हो गये हैं। लेकिन उनकी तवज्जह अधिक से अधिक गांव की ओर भी रहनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां खर्च किया जाय। यह कह देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि अलीगढ़ जिले में उनकी उत्पत्ति हुई और वहां से आकर वह शहर लखनऊ के शहरी हो गये। तो उनका ध्यान उधर भी जाना चाहिये। अलीगढ़ में जो छोटे-छोटे हमारे २,५०० देहात हैं वहां पर पिछले दिनों चेचक की बीमारी ने बहुत जोर पकड़ा था। एक-एक गांव में जहां एक हजार की आबादी है वहां पर २५० के करीब बच्चे मर गये और बहुत से घर तो ऐसे हो गये कि बच्चा भी वहां नहीं रहा। बहुत से उधर के भाइयों ने बतलाया कि मंत्री महोदय से उन्होंने कह दिया और वायरलैस से दवाई का इन्तजाम हो गया लेकिन हम तो ऐसे दुर्भागी हैं कि कहते रहते हैं और अर्जी देते रहते हैं और वहां हैल्थ आफिसर को भी अर्जी देते रहते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। हैल्थ आफिसर साहब तो झगड़ों में ही फंसे रहते हैं इधर कुछ ध्यान भी नहीं देते और इसी वजह से वक्त पर दवाई भी नहीं पहुंच पाती। हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड में भी एक हैल्थ आफिसर हैं वह तो ऐसा व्यवहार करते रहते हैं कि जिससे लोगों को काफी शिकायत है। एक चिट्ठी लिख देते हैं अदालत को कि मैं कुम्भ में जा रहा हूं और गवाही की तारीख इसी बीच में हो जाये तो अच्छा हो। वहां को बुला लेना ताकि उनको कुछ आने-जाने का पैसा मिल जाय और वह अपने

[श्री भलखान सिंह]

घर भी मिल सकें। इस तरह के आदमी इस हैल्थ विभाग में वर्तमान हैं जो केवल हमारे ऊपर एक भार हो रहे हैं। और हैल्थ के सम्बन्ध में लोगों के स्वास्थ्य का सुधार हो या उन्नति हो इस ओर उनका जरा भी प्रयत्न नहीं है। तो मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि वह जरा कड़ाई से काम लें। ऐसी बात नहीं है कि वह कड़ाई से काम न ले सकें। मैं उनको जानता हूं लेकिन जरा उनकी दृष्टि फैलनी चाहिये और देहात की ओर ध्यान जाना चाहिये। यह छोटा सा अनुदान इस विभाग को दिया गया है। इसमें कुछ रुपया वैद्यों को दिया गया है पता नहीं है कि कौन सा वैद्य है और कितना मिलता है और कौन डाक्टर हैं और वह प्रैक्टिस करते हैं या नहीं और उनको क्या सहायता मिलती है। जो मिलता है वह तो उनकी जेब में जाता है लोगों को तो सिर्फ पानी मिलता है। इस कारण जो फिजूल खर्ची हो रही है उसको रोकना चाहिये और कड़ाई के साथ रोकना चाहिये ऐसी मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है।

†श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान को प्रस्तुत करते समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने काफी विस्तार पूर्वक अपने विभाग की वस्तुस्थिति को इस भवन के सामने रखा। मैं उनको उनकी स्पष्टवादिता के लिये हार्दिक बधाई देता हूं। कोई भी ऐसा प्वाइन्ट नहीं था जो माननीय मंत्री ने स्वयं नहीं कह दिया और शायद कोई भी कमजोरी विभाग की नहीं थी जिसको उन्होंने खुद तसलीम नहीं किया हो। इसके बाद जैसा कि सभी भाषणों से ज्ञात होता है यह स्पष्ट राय है कि जनस्वास्थ्य की महत्ता को देखते हुये जो अनुदान है और उस अनुदान के अन्तर्गत जो रुपया रखा गया है इस विभाग के लिये वह बहुत कम है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि जनस्वास्थ्य हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र की आधार शिला है यानी सेकिंड लाइन आफ डिफेन्स समझी जाती है लेकिन फिर भी इतने कम अनुदान के होते हुये इस विभाग का जो संचालन किया गया और कर्मचारियों ने जितने परिश्रम से हैजा, टी० बी० प्लेग और कालरा आदि जो भीषण बीमारी हमारे प्रदेश में थीं उनसे संघर्ष किया और उन पर काफी मात्रा में विजय पायी उसके लिये वह सभी हमारे बधाई के पात्र हैं।

श्रीमन्, इसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के विभाग में आज इतना सुधार हो जाने के बाद भी डाक्टर साहबान का जो आउटलुक है वह हमारी जनतन्त्र प्रणाली के अनुकूल नहीं है। मैं अस्पतालों में देखता हूं कि देहात के लोग जब वहां जाते हैं उनके साथ वह व्यवहार किया जाता है जो आज किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा एक शिकायत में यह भी देखता हूं डाक्टर साहब और थानेदार साहबान में फौजदारी के मुकदमों में कुछ साजिश सी रहती है और आम तौर पर यह शिकायत है कि डाक्टर साहबान की तरफ से मुकदमों में रुकावट पैदा की जाती है। एक बार हमारे सदन के एक माननीय सदस्य ने चेष्टा की कि गांव से एक मरीज को ले जाने के लिये एम्बुलेंस कार मिल जाय और मुझे तो यह भी मालूम हुआ कि माननीय मंत्री जी ने आदेश भी दे दिया था कि कार दे दी जाय मगर शायद वह बाद में बाहर चले गये और कार नहीं मिली। मरीज की मृत्यु भी हो गई। बात छोटी सी है परन्तु इससे यह मालूम होता है कि जिस भावना को लेकर हमारे मन्त्री जी काम का संचालन करना चाहते हैं नीचे वह मनोवृत्ति अभी नहीं बन पाई है। मैं यह महसूस करता हूं कि पिछले दिनों आयुर्वेद के लिये काफी मदद दी गई है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं, कि जल्द आपको यह निर्णय करना होगा कि कौन सी पद्धति आपको अपनानी है। इसमें शक नहीं कि एलोपैथी बड़ी एडवांस्ड

†यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

हैं लेकिन चूंकि हमारे देश में अधिकांश लोग देहात के हैं, जो एलोपैथी जैसी कास्टली दवाई नहीं ले सकते इसलिये एलोपैथिक अधिक नहीं चल सकती। होमियोपैथी के लिये प्रोत्साहन की बात कही गई। आपने एक बिल पास कराया था और बोर्ड भी बना लेकिन डेढ़ साल का समय हो गया और यह बोर्ड कोई विशेष कार्य नहीं कर पाया है। अगर मेरी मालूमात ठीक हैं तो मुझे पता चला है कि बोर्ड ने कुछ रूल्स बनाकर सेक्रेटेरियट को भेजे, जो, यहीं पड़े हैं। उन पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

फूड एडल्ट्रेशन की ओर काफी काम हुआ है लेकिन जिस भावना को लेकर हमने यह ऐक्ट पास किया था वह पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिये। एक्सटेंशन और रिएम्पलायमेंट दूसरे लोगों में मायूसी होती है।

अन्त में मैं अपने जिले की बात कहता हूं। हमारे जिले में एक जगह आंवला है जहां का अस्पताल ६०-६५ वर्ष से पी० एम० एस० बन का था और उसके पीछे एक एन्डाउमेंट भी है। मैं यह आग्रह नहीं करूंगा कि मंत्री जी नया हास्पिटल खोल दें लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि हम जहां हैं वहीं तो हमें रहने दिया जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--माननीय चेयरमैन साहेब, मैं अपने आपको इस विवाद में डालना नहीं चाहता हूं। अगर मैं ऐसा करूं तो जिस ओर मैं इस सदन का और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं शायद उससे मैं वंचित रह जाऊं और जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां का प्रतिनिधित्व न कर सकूं। अस्तु जो कुछ प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में मंत्री जी ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने यह कहा कि जिस देश में अथवा जिस प्रान्त में लोगों को खाने पीने की दिक्कत रहती है उसका स्वाभाविक प्रभाव स्वास्थ्य पर हो जाता है। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहता हूं कि जिस पूर्वी प्रदेश का मैं निवासी हूं और जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां आये दिन तरह तरह की दिक्कतें पेश आती रहती हैं। नतीजा यह होता है कि वहां के निवासी आधे पेट रह कर न मालूम कितनी रैन गुजारते हैं। यदि सारे शेष प्रान्त को और पूर्वी जिलों को देखा जाय तो जितनी व्याधियां पूर्वी भाग में हैं उसके हिसाब से जो इस बजट की रकम रखी गयी है वह बिल्कुल ही नाकाफी है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि शोहरतगढ़ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक एलोपैथिक अस्पताल की दशा को सुधारा है। वहां की हालत बहुत ही खराब थी। जब माननीय मंत्री ने नयी इमारत का उद्घाटन किया था तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस अस्पताल का प्रान्तीयकरण शीघ्र ही किया जायगा। मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने उसका प्रान्तीयकरण कर दिया है। इतना ही नहीं बस्ती जिसकी आबादी प्रान्त भर में सबसे अधिक है, सदर और जनाना अस्पतालों में बिजली के साधन उपलब्ध कर दिये हैं और आधुनिक विधि से जो चिकित्सा संभव है वह वहां होने लगी है। लेकिन माननीय चेयरमैन साहब, शोहरतगढ़ से लौटते समय जब कि माननीय मंत्री बांसी स्थान पर चन्द मिनट के लिये ठहरे तो सौभाग्य से मैं भी उनके साथ था। वहां के नागरिक और अन्य लोगों ने एक अस्पताल खोलने के लिये उनसे प्रार्थना की जिसकी स्वीकृति सरकार कर चुकी थी। वहां के निवासियों में से एक ने २०-२५ हजार रुपया भी अपनी स्त्री के नाम पर दानस्वरूप दिया था। यह सौभाग्य से तय भी हो गया था कि वहां पर जनाना अस्पताल खोला अवश्य जायगा। माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा है कि अस्पताल वहीं खोले जायेंगे जहां स्थान का अभाव न होगा। लेकिन यह दिक्कत बांसी में नहीं है क्योंकि वहां पर अफीम की एक कोठी खाली पड़ी हुई है जिसे माननीय मंत्री महोदय को दिखला भी दी

[श्री रामकुमार शास्त्री]

गयी है। लेकिन फिर भी दुःख है कि वहां पर अब तक जनाना अस्पताल नहीं खोला गया उन्होंने यह भी अपने भाषण में कहा है कि मिडवाइफ, नर्सेज के लिये स्त्रियां आगे नहीं बढ़ती हैं। लेकिन जब इस क्षेत्र में अस्पताल नहीं है और दवा वगैरह का कोई प्रबन्ध नहीं है तो वे नाम लिखा कर भी क्या कर सकती हैं। स्थिति यह है कि लोग रुपया देने को भी तैयार हैं लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी और बांसी का जनाना अस्पताल नहीं बना अथवा खोला गया। विभाग के कर्मचारियों की बड़ी तारीफ की गयी कि उन्होंने कितनी तपस्या और त्याग से काम किया। अब तो इस तरह की प्रशंसा की धाराप्रवाह चर्चा होने लगी है। ऐसी हालत में माननीय, यह तो आप ही विचार सकते हैं कि वहां रहने का स्थान है, रुपया भी है फिर भी इतने दिनों से बांसी में अस्पताल नहीं खुला तो वे सरकारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं अथवा नहीं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बांसी में जनाना अस्पताल को अब शीघ्र खोलने का प्रबन्ध करें जिससे वहां की महिलाओं को दवादारू से लाभ उठाने की सुविधा हो।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय सभापति जी, आज जो अनुदान हमारे सामने हैं उसके सम्बन्ध में जो जनोपयोगी योजनायें हैं और जिनका वर्णन माननीय मंत्री जी ने किया है मैं उसके लिये मंत्री जी को और विभाग को बधाई देता हूं।

आज के जमाने में जो मौजूदा चिकित्सा पद्धति है उसका ढांचा इतना महंगा है कि वह हमारे देश की जनता के अनुकूल नहीं है। हमारे देश में चिकित्सा इतनी महंगी है कि बड़े से बड़े आदमी के लिये अगर वह बीमार हो जाता है तो उसके एक महीने भर की आमदनी साफ हो जाती है। तो हमें आज जरूरत इस बात की है कि सस्ती चिकित्सा पद्धति का विकास यहां पर हो। उसके लिये ध्यान इस विभाग का नहीं है और यही हालत जनस्वास्थ्य विभाग की भी है। जो ढांचा आज स्वास्थ्य विभाग का है उसके लिये यह आवश्यक है कि हैजे का टीका लगवाओ, चेचक का टीका लगवाओ, प्लेग का टीका लगवाओ, सन्तति निरोधक औषधियों का उपयोग करो, और डी० डी० टी० का छिड़काव कराओ तब जाकर यहां स्वस्थ रह सकते हो। आज का स्वास्थ्य विभाग का यह ढांचा इस देश के अनुकूल नहीं है। आज स्वास्थ्य विभाग ब्रह्मचर्य, प्राणायाम और खाने की प्राचीन परिपाटी जो स्वास्थ्य रक्षक है और शरीर की वाइटेलिटी (रोग निरोधक शक्ति) को बढ़ाती है उसका स्वास्थ्य विभाग जिक्र भी नहीं करता। इसलिये मैं कहता हूं कि आज सम्पूर्ण स्वास्थ्य विभाग को पुनर्संगठित करने की आवश्यकता है। हर आदमी जानता है कि ब्रह्मचर्य, और प्राणायाम आदि और दूसरी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे स्वास्थ्य बनता है लेकिन पाश्चात्य रंग में रंगे हुये डाक्टरों और स्वास्थ्य विभाग में इनके लिये स्थान नहीं है। यह बिल्कुल मानी हुई बात है कि एलोपैथिक डाक्टर्स से यह विभाग आच्छादित है और उसकी वजह से इस विभाग में उसके लिये कोई स्थान नहीं है।

इसके अलावा डिपार्टमेंट में और भी बहुत सी खराबियां हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इतने सामान में मिलावट के कारण प्राजीक्यूशन हुये। मैं विभाग का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो मिलावट नहीं करते हैं लेकिन विभाग के लोगों को कुछ देना नहीं चाहते हैं उनका ही प्राजीक्यूशन होता है लेकिन जो मिलाते हैं जो मिली हुई चीजें बेचते हैं उनके सामान का कोई कंफिस्केशन नहीं होता है। लीगल ऐक्शन तो लिया जाता है लेकिन यह नीयत नहीं है कि सामान में मिलावट बन्द हो। अगर यह नीयत होती तो जहां कहीं भी गड़बड़ सामान मिलता है वह बिकना नहीं चाहिये लेकिन यह नहीं है। आज खुले तौर पर घी और कड़ुवे तेल का एसेंस

मिलता है। लेकिन मिली हुई चीजों का कोई कन्फिस्केशन नहीं होता है सिर्फ चालान किया जाता है और मुकदमा चलने पर थोड़ा सा रुपया जुर्माना हो जाता है लेकिन मिलावट बन्द करें यह काम नहीं होता सिर्फ कागजी कार्यवाही की जाती है। अपने कारनामों को दिखलाने की कोशिश की जाती है कि इतने चलान किये गये।

आज अस्पतालों में घूसखोरी बड़ी जोरों से चल रही है, जनाना अस्पतालों में भी घूसखोरी चल रही है। वहां पर दवायें चोरी से बेची जाती हैं, उनकी बिक्री होती है मैं इस तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके साथ ही जो आम बात हर बजट की है कि कितने ही आइटम्स यहां से स्वीकृत हो जाते हैं लेकिन उनका साल भर एस्टीमेंट्स ही बना करता है और वह अमल में नहीं आती। अभी फैजाबाद जिला के अयोध्या के श्रीराम अस्पताल के डाक्टर साहब मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि जो रुपया गवर्नमेंट से मिला था अस्पताल के लिये उसके लिये आज तक एस्टीमेट ही बन रहा है। ऐसी कितनी ही मिसालें दी जा सकती हैं। माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने एक सुझाव दिया था कि एक ही पद्धति को चलाया जाना चाहिये। मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि बावन चिकित्सा पद्धतियां नहीं चल सकती हैं लेकिन कौन सी चिकित्सा पद्धति हो इसका निर्णय कैसे हो। ईक्वल स्टैटस बराबर की सुविधा मिलती नहीं है तो फिर इसका निर्णय कैसे हो सकता है। आज एलोपैथिक मेडिकल एड उस मिकदार में नहीं मिल रही है जिस मिकदार में उसकी आवश्यकता है। मैं इस नाम पर तो आयुर्वेद की उन्नति नहीं चाहता, अगर आयुर्वेद में कोई वैज्ञानिकता है तभी वह उन्नति कर सकता है लेकिन उसको बराबरी का स्टैटस तो मिलना चाहिये। उन्नति तो वही कर सकता है जिसमें कोई सच्चाई होगी, कोई वैज्ञानिकता होगी यह तो प्रत्यक्ष बात है। कोई भी हो चिकित्सा में यदि वह निपुण नहीं है तो रोगी उसके पास नहीं आवेगा। इसमें झूठ चल नहीं सकता है, इसमें धोखाधड़ी नहीं चल सकती है। इसलिये हम चाहते हैं कि आदर्श आयुर्वेदिक कालेज खोले जावें। लेकिन दुःख है कि सरकार के विभाग में आयुर्वेद के लिये जो व्यवस्था है उसके लिये कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। एलोपैथिक डाक्टर लोग इसको प्रोत्साहित नहीं होने देना चाहते। कहा यह जाता है कि आयुर्वेद विभाग स्वतंत्र है लेकिन वास्तविकता यह है कि आयुर्वेद विभाग जो योजनायें बनाता है उसको करटेल कर दिया जाता है और उनकी वह योजनायें लौटा दी जाती हैं और वह सूबे भर में नहीं चल पाती, किसी तरह से इसकी प्रतिष्ठा कम हो यह प्रत्यत्न किया जाता है, इसके ज्वलन्त प्रमाण हमारे सामने हैं।

हमें माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वह लखनऊ यूनीवर्सिटी में डाक्टरों के असहयोग के कारण आयुर्वेदिक कालेज चलाने में असफल रहे। इसी तरह से ५२ जिलों के अन्दर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसरों के मातहत आयुर्वेदक डिस्पेन्सरियों की व्यवस्था की गई है वह पनप नहीं पा रही है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में एक डीन के अन्डर में फैकल्टी होती है उसी तरह से जिलों में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसरों के अन्डर में डिस्पेन्सरियां हैं और डिस्पेन्सरियां वहां सफल नहीं हो सकी हैं। अगर आप कम्पिटीशन करना चाहते हैं तो उसके लिये जरूरत है कि आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये भी सरजिकल सामग्री दी जाय। चूंकि उनके यहां सरजिकल सामान की व्यवस्था नहीं होती है इसलिये वह एलोपैथिक से कम्पिटीशन नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप जो भी सुविधायें दें वह सब को बराबर दें। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और निमन्त्रण देना चाहता हूं कि अगर सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये व्यवस्था नहीं कर सकती है तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिये एक कमिश्नरी या दो कमिश्नरी एलाट करके हमें खर्चा एलाट कर दें और उसके लिये अलग से आदमी नियुक्त किये

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

जाय और फिर आप देखें कि कितने सरल तरीके से और योग्यता के साथ हम काम करते हैं। इसी तरह से आयुर्वेदिक मुहकमे के जो कर्मचारी हैं उनको बिलकुल स्वतंत्र होना चाहिये। वह किसी डाइरेक्टर के अधीन न रक्खे जायं। आपके मुहकमे की तरफ से विज्ञान के उपदेश दिये जाते हैं लेकिन मुहकमे की तरफ से अजीब कारनामे किये जाते हैं। सरकार ने इंडियन बोर्ड आफ मेडिसिन और आयुर्वेद यूनानी एकेडेमी खोल रखी है लेकिन उन बोर्डों के अन्दर एक भी टेक्निकल आदमी नहीं है। यह तो वैसे ही है जैसे कि एक बोतल पर लेबिल लगी हो मगर उसमें दवा नदारद हो।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन दोनों अनुदानों पर जो विवाद चल रहा है वह कल सवा बजे तक जारी रहे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि इन दोनों अनुदानों पर जो विवाद चल रहा है वह कल सवा बजे तक चलता रहे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्य गंगाधर मैठाणी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस प्रांत के अभावग्रस्त क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमान् जी संक्रामक रोग ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में अपना एक केन्द्र बना रखा है। उन बीमारियों में खासकर हैजा, प्लेग, महामारी चेचक इत्यादि है। यह बीमारियां खासकर वहां गरीबी के कारण होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में खासकर बाढ़ों के कारण सारी फसल नष्ट हो जाती है। कभी-कभी सूखा, पत्थर या ओले पड़ जाते हैं। इस प्रकार की आफतें इन क्षेत्रों में आया करती हैं इन कारणों से और खूराक की कमी के कारण उन क्षेत्रों में बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। वहां लोगों को भर पेट खाना नहीं मिलता है, इसलिये वे लोग बहुत सी अभक्ष्य चीजों का भोजन करते हैं और वे हैजा और दूसरी अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं वह देवरिया जिला ओले से, सूखे और हर तरह से तबाह रहता है। वहां किसी प्रकार की खाने की व्यवस्था नहीं है। वहां लोग पीपल के गोदे, अकोलाह के फल खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसी दशा में भी मैं बतलाना चाहता हूं कि वह जिला अपेक्षित रहा। उस जिले में तो पहले कोई सरकारी अस्पताल ही नहीं था। कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल थे। अब माननीय मंत्री जी की तरफ से एक अस्पताल फाजिलनगर में बनाना शुरू हुआ है। उन्होंने यह बतलाया है कि सन् ५३ के मार्च के महीने तक वह तैयार हो जायगा। कितने वर्षों के बाद इमारत तो तैयार हो गयी है लेकिन अभी तक न उसमें कोई डाक्टर गया है और न कोई दवा ही पहुंची है। उसी तरह से तरिया का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र से तीन हजार आदमियों की दरख्वास्तें अभी-अभी आयी हैं जो कि माननीय गेंदा सिंह जी के पास हैं। जब वहां टेस्ट वर्क चल रहा था, तब उसमें हजारों आदमी काम कर रहे थे। अब वह टेस्ट वर्क भी बन्द कर दिया गया है। वहां लोग अब भूखों मर रहे हैं। इसके साथ-साथ वह क्षेत्र नदी के किनारे पड़ता है इसलिये वहां के लोग तमाम बीमारियोंके शिकार होते हैं। वहां इसलिये कोई इन्तजाम नहीं होता कि माननीय गेंदा सिंह का क्षेत्र है उनके कारण इन्तजाम नहीं होता है। लेकिन मैं आपके सामने बतलाऊं कि पडरौना की उत्तर तरफ जो खड्डा का क्षेत्र है, जहां से महावीर सिंह जी चुन करके आये हैं जब हम वहां चुनाव के सिलसिले में गये तो हमने वहां देखा कि पांच-पांच कोस तक कहीं दवा का ठिकाना नहीं है। इन बीमारियों के बारे में कोई इन्तजाम नहीं है। लोग परेशान रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री जी का ध्यान क्यों नहीं उस तरफ जाता। हम तो यह कहने में भी नहीं हिचकते कि माननीय मंत्री जी बाल बच्चे वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो बाल बच्चे

वाले हैं और हम यह महसूस करते हैं कि जितनी बीमारियां वहां पहुंचती हैं वे गरीबी की वजह से पहुंचती हैं। यहीं एक डफरिन अस्पताल है उसमें दवा को छोड़िये पानी नहीं मिलता है हां, वहां एक चीज की अधिकता है और वह बन्दरों की अधिकता है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय चेयरमैन साहब, मैं बड़ा मशकूर हूं कि आप की इनायत से मुझे भी मौका मिल रहा है कि मैं अपने कुछ ख्यालात इस भवन के सामने रखूं। सब से पहले मैं उन बधाई देने वालों में अपने आपको भी शरीक पाता हूं जिन्होंने माननीय मंत्री जी की उस तकरीर के लिये उनको बधाई दी कि जो उन्होंने इस बजट को पेश करते हमारे सामने की। इसमें शक नहीं कि उस तकरीर में उन्होंने बड़ी बजाहत के साथ यह बात बयान की कि किस तरीके पर पब्लिक हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट को तरक्की देने की वह कोशिश कर रहे हैं जबकि रुपया और हमारे रिसोर्सेज इतने काफी नहीं हैं कि जिनसे इसको उतनी तरक्की दी जा सकती जितनी कि हम चाहते थे। इसमें शक नहीं कि हमारी फाइव ईयर प्लान ने हमारे लिये बहुत कुछ पाबन्दियां मुकर्रर कर दी हैं जिसके मुताबिक हमें आगे बढना है और मैं यह देखता हूं कि जो न्यू आइटेम्स आफ एक्सपेंडीचर हैं उसमें भी अलहदा अलहदा अखराजात बतला दिये गये हैं कि फाइव इयर प्लान के मुताबिक ये अखराजात किये जायेंगे और आर्डिनरी तरीके पर ये ये अखराजात किये जायेंगे। अगर उस तमाम लिस्ट को पढें तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और उससे हमें कम से कम इस बात का यकीन हो जाता है कि हमारे मिनिस्टर साहब इस बड़ी प्राबलम की तरफ पूरी दिलचस्पी और हमदर्दी रखते हैं और इस मामले में कोई इमकानी बात जो उनके इमकान के अन्दर हो वह उठा के रखी नहीं गई है। लेकिन यह भी एक वाकया है कि जहां तक माली हालत और हमारे रिसोर्सेज का ताल्लुक है वह महदूद हैं और फाइव इयर प्लान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी डाल दी हैं जिनकी वजह से हम इस सिलसिले में उतना सब कुछ जल्दी तो नहीं कर सकते हैं जितना कि हम करते लेकिन इसमें शक नहीं कि जहां तक तालीम का ताल्लुक है और पब्लिक हेल्थ का ताल्लुक है ये दो नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं और जब तक ये किसी वेलफेयर स्टेट के अन्दर तरक्की न करें उस वक्त तक उस स्टेट की तरक्की नहीं हो सकती। जनाबवाला, यह अभी मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बतलाया और हम यह पहले से भी जानते हैं कि इस सूबे की हुकूमत और गवर्नमेंट आफ इंडिया के जमाने में इस बात की बड़ी कोशिश की गई कि मार्टेलिटी का रेट कम हो और हमें आज खुशी है कि हमारे सूबे के अन्दर और मुल्क के अन्दर भी हम नुमायां हैसियत से इस बात का दावा कर सकते हैं कि मार्टेलिटी हमारे सूबे के अन्दर कम हो गई है। लेकिन यह चीज जहां एक तरफ खुशखबरी देती है वहां दूसरी तरफ यह चीज हमारे लिये बहुत एलार्मिंग भी है। इसलिये जैसा कि मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि खुद फाइव इयर प्लान में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमने एक तरफ यह बन्दोबस्त भी कर दिया है कि हमारे यहां मौतें कम होने लगें और अगर दूसरी तरफ पैदावार हम बढायेंगे तो फिर मुश्किल ही है। इसलिये इसकी तरफ हमें पूरा ध्यान देने की जरूरत है और गवर्नमेंट तो इस सिलसिले में जो कुछ कर सकती है कर रही है लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि इसके लिये संस्थायें और पब्लिक सामने आये और इस मामले में कोआपरेट करें। बगैर पब्लिक और संस्थाओं के पूरे कोआपरेशन के किसी गवर्नमेंट के लिये यह नामुमकिन है कि वह एक कानून बना कर इतने बड़े मसले को, जो एक सोशल मसला है, हल कर सके।

जनाबवाला, वक्त कम है और इस सिलसिले में कहा बहुत कुछ जा सकता है। मैं दो एक तजवीजें मिनिस्टर साहब की खिदमत में पेश करूंगा और मुझे यकीन है कि वह उन पर गौर फ़रमायेंगे। इसमें शक नहीं कि जहां तक हेल्थ का ताल्लुक है, अगर हम यह चाहते हैं कि क़ौम की हेल्थ बेहतर हो तो हमें बजाय क्यूरेटिव के प्रिवेंटिव की तरफ जाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और उसके लिये मैं समझता हूं कि यह सब से बेहतर होगा कि जिस वक्त से हमारे बच्चे जूनियर स्कूल में तालीम के लिये जाते हैं उस वक्त से हम कुछ ऐसा प्रबन्ध करें कि वे हेल्थ

[श्री सुल्तान आलम खाँ]

की एजुकेशन लेना सीखें। हमें खुशी है कि हमारे सूबे के अन्दर हमारे मुल्क की जो सब से बड़ी जरूरत है--ऐग्रीकल्चर उसकी पाबन्दी हमारे जूनियर स्कूल्स में कर दी गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज के मुताल्लिक भी गौर करेगी कि क्या यह मुमकिन हो सकता है कि हम अपने जूनियर स्कूल्स में हेल्थ की निस्बत भी बन्दोबस्त कर सकें। मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया कि जहां तक आयुर्वेदिक फैकल्टी का मामला है बड़ा अफसोस है कि मेडिकल कालेज से पूरा कोआपरेशन नहीं हो सका और इसलिये वह स्कीम खत्म करनी पड़ी। हम सब को भी इस बात का बहुत दुख है। मगर इस सिलसिले में मैं बहुत अदब से उनके सामने एक तजवीज यह भी रखूंगा कि हमारे यहां सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हमारे देहातों में रकबे में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो और इसके लिये वह इस तरफ भी अगर गौर फरमायें तो मुनासिब होगा जो कि तुलबा मेडिकल कालेज आगरा में या लखनऊ में हम लेते हैं उनसे कुछ इस किस्म की पाबन्दी हम लें कि वे यहां से निकलने के बाद एक अरसे तक देहातों में हैल्थ का काम करेंगे तो यह ज्यादा मुनासिब होगा।

इसके अलावा एक और चीज, मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे सूबे के अन्दर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक, ये चार सिस्टम काम कर रहे हैं और लोगों को इस बात का मौका है कि वे चारों की कम्पेरेटिव स्टडी करें। तो मैं उनसे यह अर्ज करूंगा कि मुनासिब यह मालूम होता है कि हम सूबे के अन्दर एक किस्म का सर्वे करें जिससे यह पता हो कि किस इलाके के लोग किस किस्म का इलाज पसन्द करते हैं और आइन्दा के लिये एक प्लान अपने पास रखें और जब कहीं कोई हास्पिटल खोलें तो उस प्लान के मुताबिक खोलें। जिस इलाके के लोग जिस किस्म की डिसपेंसरी चाहते हैं वही उनको दी जाय।

*श्री आर्थर गाइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--डिप्टी स्पीकर साहब मैं वही पुरानी चाल चलूंगा। मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि नर्सेज की बाबत हमारे मिनिस्ट साहब हर साल कहते हैं कि नर्सेज की बड़ी डर्थ है और नर्सेज मिलती नहीं हैं। लेकिन उसके लिये वह कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे मिला था उनको समझाया भी था और उनको मैंने चिट्ठी भी लिखी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि कौन गर्ल्स हैं जो नर्सेज के प्रोफेशन में जा रही हैं। क्रिश्चियन गर्ल्स या ऐंग्लो इंडियन गर्ल्स ही जा रही हैं। आपकी ब्राह्मण लड़की नहीं जा रही है, मुसलमान लड़की भी नहीं जा रही है। ज्यादा तर क्रिश्चियन गर्ल्स ही जा रही हैं जा रही है क्रिश्चियन गर्ल्स ही। लेट अस कमट्रू दी ब्रास टैक्स।

मैं फिर कहता हूं कि हमारे स्कूलों के ऐजूकेशन का स्टैंडर्ड आपके यहां के स्कूलों से बहुत ज्यादा ऊंचा है। हमारे यहां का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आप अपने यहां की किसी लड़की को ले आइये उसको हमारे यहां की लड़की मात कर देगी। लेकिन फिर भी आप नर्सेज के लिये सीनियर कैम्ब्रिज और हाई स्कूल स्टैंडर्ड को गिराते नहीं हैं। आपने इंटर और हाई स्कूल स्टैंडर्ड कर रखा है। पहले जो फोर्थ स्टैंडर्ड और सिक्स्थ स्टैंडर्ड की ऐंग्लो इंडियन गर्ल्स नर्सेज में आती थीं उनका स्टैंडर्ड आप लोगों को मालूम होगा कितना हाई था। अब आपने हाई स्कूल और इन्टर कर दिया है तो कितना स्टैंडर्ड नीचा हो गया है, इतनी गंदगी और इतना मैला हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज हमारे इस ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन के मारे हमारा यू० पी० बरबाद हो रहा है। मैं कहता हूं कि इसको आग में झोंक देना चाहिये और स्टैंडर्ड भी हो तो एकोर्डिंग टू प्रोफेशन होना चाहिये। क्या आपने हाई स्कूल इंटर कर दिया है। फिर से वही सिक्स्थ और सेवेन्थ स्टैंडर्ड ले लिया जाय तो फिर नर्सेज की डर्थ नहीं रहेगी और आपके हास्पीटल्स भर जायेंगे।

---

* यह भाषण माननीय स्वयं द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

उनके खाने और रहने का भी इन्तजाम महान रद्दी है। आप हमारे साथ इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा वगैरा चलें तो आपको मालूम होगा कि उनकी बेजेज रद्दी हैं। यह बड़ा नोबिल प्रोफेशन है। लेकिन हमारी सरकार जरा भी ख्याल नहीं करती है। उनके खाने का और रहने का और कपड़ों का बड़ा खराब इंतजाम है। सब चीज खराब है और ऊपर से हिन्दी में ऐसे वर्डस हैं जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा था कि लिखने वाला लिखने के बाद पढ़ नहीं पाता। ऐसे वर्ड्स मेडिकल लिस्ट में रखे गये हैं। बाबा यह सब हो सकता है और हम जानते हैं कि हमें हिन्दी सीखना पड़ेगा क्योंकि हिन्दी यहां की लैंगुवेज है। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह जल्दी जल्दी न बढायें। लीव इट एलोन। सन् १९५४ के बाद नो इंगलिश। इस से लोग क्या समझ सकते हैं। डाक्टरों का कहना है कि वह नहीं समझ पाते हैं। इस सबका नतीजा क्या होगा। हमारे मास्टर भी ऐसे ही निकल रहे हैं। इसी माफिक हमारी नर्सेज और डाक्टर थर्ड, फोर्थ और फिफथ ग्रेड के निकलेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दो तीन साल से कानपुर में मेरा एक टी० बी० अस्पताल है। यह पर्सनल चीज है। लोग कहते हैं कि अपने कानपुर की बात मत कहो कहो तो सारे यू० पी० की बात कहो। लेकिन मुझे कहना पड़ता है। कानपुर में हाइएस्ट रेट टी० बी० का है, लेकिन वहां रुपया मौजूद है, जमीन है, टी० बी० असोसियेशन है, परन्तु जब भी हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं देती। लाला लाजतपराय हास्पिटल में बड़ी शान से कहा जाता है कि वहां टी० बी० वार्ड खोल दिया गया है। १२ आदमी और १२ वीमेन हैं। बिलकुल स्टूपिड है। आई ऐम सारी, आई विद्ड्रा दिस मेरे कहने का मतलब यह है कि उससे बिलकुल भी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। वहां क्या ठीक है? वहां जमीन है, रुपया है और सब चीज हो सकती है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे और मालूम हो कि हम कर रहे हैं। इस तरह काम नहीं चलता। आपके द्वारा मैं माननीय मिनिस्टर से कहता हूं कि वह कानपुर की टी० बी० असोसियेशन की ओर गौर से देखें और टी० बी० के मुताल्लिक क्या हो रहा है यह मालूम करने की कोशिश करें। हेल्थ की बाबत, मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ की तरफ से बड़ी मांग आ रही है और अप्रैल और मई में बड़ा शोर होता है कि "कट फ्रूट्स मस्ट नाट बी सोल्ड, ओपिन स्वीट्स मस्ट नाट बी सोल्ड" (कटे फल और खुली मिठाइयां कदापि न बेची जायं) लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं करता। म्युनिसिपैलिटी के बाउन्डरी में भले ही न बिकें लेकिन बाउन्डरी के बाहर कट फ्रूट्स खूब बिकते हैं। और कालरा कालरा मिनिस्टर चिल्लाते चिल्लाते रहे हैं और कहा जाता है कि ४ लाख इंजेक्शंस दे दिये और फलाना कर दिया है, लेकिन जबतक ये कट-फ्रूट्स बन्द न हों और इसके रोकने का हम लोग जबतक कोई इन्तजाम न करें तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस तरफ ध्यान दें। जो रूल्स निकालें कम से कम उसको अपहोल्ड करें। अगर रूल्स पर अमल होता है तो ठीक है अदरवाइज डोंट मेक रूल्स।

*श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)--माननीय चेयरमैन साहब, मैं सब से पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी देरके बाद कम से कम मुझे आपने यह भी अवसर दिया कि हम अपने जिले बारेमें भी कुछमाननीय मंत्री जीसे कहें। इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उहोंने बड़ी कुशलता के साथ इस अनुदान को सदन के सामने रखा और अपने इंट्रोडक्टरी व्याख्यान में उन्होंने जो कुछ खामियां थीं उनको सहृदयता से तस्लीम कर लिया, इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश हम लोगों को नहीं थी और जो कुछ बाकी बचा हुआ था उसको हमारे पूर्व वक्ता ने मंत्री जी के सामने रख करके और भी रास्ता बन्द कर दिया। नर्सेज के बारे में किसी माननीय सदस्य ने कुछ नहीं कहा था,

* यह भाषण माननीय सदस्य द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है।

[श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह]

उन्होंने उस बात को भी माननीय मंत्री जी के सामने पेश कर दिया और आशा है कि माननीय मंत्री जी उन कठिनाइयों को दूर करने में कामयाब होंगे। अब मैं गोरखपुर के बारे में कुछ बातें माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। गोरखपुर वह स्थान है जहां पर नाना प्रकार की बीमारियों की जन्मभूमि है। मैं जानता हूं कि गोरखपुर से माननीय मंत्री को बड़ी मुहब्बत है और वहां का खास ध्यान रखते हैं और उनको हम से कम ज्ञान गोरखपुर के बारे में नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है, मुमकिन है कुछ भूल हो गयी हो, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि गोरखपुर में एक टी० बी० का अस्पताल बढ़हलगंज में खोलने का विचार माननीय मंत्री जी का था और पिछले बजट में इसकी कुछ चर्चा भी थी लेकिन अबके बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वहां स्थान है, दरिया का किनारा है। वहां पर अगर टी० बी० का अस्पताल खोल दिया जाय और कुछ मरीजों के और डाक्टरों के रहने का प्रबन्ध कर दिया जाय तो गोरखपुर को बड़ी भलाई होगी। एक बात और कह दूं कि गोरखपुर में सीतापुर के जो डाक्टर साहब हैं उन्होंने बड़ी मेहरबानी के साथ एक आंख खोल रखी है। जो अभी प्राइवेट तरीके से चल रही है और वहां की जनता को बहुत फायदा पहुंच रहा है। दो ढाई सौ आदमियों की आंख उस अस्पताल के डाक्टर ने बनायी होगी और डाक्टर साहब जो सीतापुर के इचार्ज हैं वह खुद भी वहां पधारे थे। तो उस अस्पताल को, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कुछ ग्रांट, कुछ मदद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिये ताकि वहां की जनता का उपकार हो। वैद्य लोगों और डाक्टरों के झगड़े में तो हम जाना नहीं चाहते हैं लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि आयुर्वेद जो है वह हमारा पुराना तरीका दवा का रहा है और आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचार देहातों और शहरों में किया जाय और गवर्नमेंट इसकी मदद करे तो इससे ज्यादा भलाई होगी क्योंकि एलोपैथिक में बहुत सी बीमारियों की दवा ठीक रूप से नहीं हो पाती है और हम लोगों का एतबार भी आयुर्वेद में बहुत ज्यादा है और विश्वास जो है वही मरीज को अच्छा करता है। अगर किसी डाक्टर की दवा में मेरा विश्वास नहीं है तो मैं उससे कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिये आयुर्वेदिक तरीके पर चूंकि हम लोगों का एतबार है इसलिये उन दवाखानों की मदद करना हमारा कर्तव्य होता है। एक चीज के लिये और भी हम माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे कि अगर मूविंग मेडिकल हास्पिटल, डिस्पेंसरीज रखी जायं तो उससे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि देहात के लोगों को शहरों में पहुंचने में बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और वहां उनके रहने के लिये कोई सुविधा नहीं होती है। इसलिये बहुत से मरीज अस्पतालों में दवा कराने के लिये नहीं जाते हैं। तो अगर इस किस्म का कोई प्रबन्ध हो जाय कि मूविंग डिस्पेंसरीज हों और हर जगह गांव गांव में जाकर के वह दवा लोगों को दें तो हम समझते हैं कि लोगों का स्वास्थ्य निहायत अच्छा हो जायगा।

मैं अपने माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे गोरखपुर के जिले में म्युनिसिपल बोर्ड के जो हेल्थ आफिसर हैं उन्होंने इतनी कामयाबी से वहां काम किया कि जब से वह वहां गये तब से वहां कालरा और प्लेग की बीमारियां नहीं आयी। उनका रिटायरमेंट का वक्त हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक ऐक्सटेंशन जरूर दिया जाय। वह बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं और उनकी कोई शिकायत नहीं है तथा वह इन बीमारियों को रोकने में बहुत कामयाब हुए हैं।

यह बात जरूर है कि इस अनुदान में रुपया बहुत कम है। इसकी वजह से हमारे माननीय मंत्री जी को कठिनाइयां तो होंगी लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारे पिछड़े हुए जिले के ऊपर वह खासतौर से मेहरबानी करेंगे।

अधिष्ठाता—माननीय नारायण दत्त तिवारी,

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय चेयरमैन साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई लिस्ट आपके पास है जिसमें से आप नाम पुकार रहे हैं?

अधिष्ठाता—आप बैठ जाइये, कोई लिस्ट नहीं है। मैं किसी लिस्ट के अनुसार काम नहीं कर रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय सभाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मैठाणी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बड़े दुख का विषय है कि जब कि एक ओर पिछले तीन साल में सारे बजट के खर्चे में ६५ करोड़ से ८१ करोड़ तक की वृद्धि हुई है वहां हमारे स्वास्थ्य विभाग के अनुदान में १४ लाख रूपये की कमी हुई है। मैं इस बात की आशा नहीं करता था कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जैसे प्रभावशाली सदस्य के रहते हुए भी प्रान्त के स्वास्थ्य विभाग के बजट में बढोत्तरी होने के बजाय कमी की जायगी। मुझे तो इस बात की भी शिकायत है कि पंचवर्षीय योजना के अनुसार जितना रुपया खर्च होना चाहिये था। जितना टार्जेट था, उतना खर्च नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान स्टेट प्लान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं पेज २४, और पेज २७, २८ और २९ पर लिखा हुआ है कि ऐडीशनल करेंट रेट आफ एक्सपैंडीचर जो नया खर्चा होगा वह पंचवर्षीय योजना के अनुसार मेडिकल डिपार्टमेंट में २९ लाख रु० का होगा और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में १४ लाख रु० का होगा। लेकिन जब हम बजट देखते हैं तो मेडिकल डिपार्टमेंट में केवल ८ लाख ८१ हजार रुपये का और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में केवल ४० हजार रुपया पंचवर्षीय योजना के अनुसार खर्च हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रान्तीय सरकार की क्या नीति है। एक तरफ तो कहा जाता है कि हम पंचवर्षीय योजना के अनुसार चल रहे हैं लेकिन पंच वर्षीय योजना के जो टार्जेट हैं, जो हम एलाट किये गये हैं। उनके अनुसार खर्चा नहीं होता है। माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े मृत्यु के दिये और उन्होंने कहा कि पिछले सालों में मृत्यु की संख्या इसलिये कम हुई है क्योंकि स्वास्थ्य में तरक्की हो रही है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि यू० पी० में एवरेज एक्सपेक्टेशन आफ लाइफ क्या है। मेल और फीमेल का एज एक्सपेक्टेशन क्या है। वह बिलकुल स्टैटिक है जो कि सन् १९४१ में थी। मर्दों का औसत ३२ वर्ष और स्त्रियों का ३१ वर्ष इस देश में है। इसी प्रकार जहां मृत्यु की रफ्तार में मननीय मंत्री जी कमी बतलाते हैं वहां जनसंख्या की वृद्धि में भी कमी हो रही है। सन् १९४९ ई० में आबादी में वृद्धि ९.६६ हुई और सन् १९५२ में वह केवल ६.७२ ही रह गई।

जहां तक टी० बी० का सवाल है माननीय मंत्री जी ने एक टी० बी० सैनेटोरियम खोलने की योजना एक रखी थी लेकिन उसको बन्द करके तीन नये छोटे छोटे अस्पताल खोले जा रहे हैं और उसमें १ लाख ४५ हजार की कमी कर दी गई है। सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि आज भी इस स्टेट के अन्दर केवल १६ क्लिनिक हैं जो कि सन् ४६ से चले आ रहे हैं। आवश्-यकता इस बात की है कि हर जिले में एक टी० बी० क्लिनिक और एक वेनरल डिजीजेज का क्लिनिक हो। १६ केन्द्र लेप्रोसी आर्गेनाइजेशन के भी हैं लेकिन प्रान्तीय स्तर पर उसका कोई आर्गेनाइजेशन नहीं है और न वेनरल डिजीज का मुकाबिला करने के लिये ही प्रान्तीय स्तर पर कोई स्तर है जिसके अधीन यह कार्य पूरे प्रदेश में हो।

इसी प्रकार हमारे देश में कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है और दो लाख मृत्युएं इस देश में पिछले वर्ष हुईं तो इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रांत में कैंसर का भी एक अच्छा अस्पताल हो।

डाक्टरों की कमी खुद माननीय मंत्री जी ने स्वीकार की। यहां पर ६,३०० की आबादी पर एक डाक्टर पड़ता है और ४३,००० आबादी पर एक नर्स उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि हम नये मेडिकल कालेज खोलें और पंचवर्षीय योजना में उनका स्थान होना चाहिये। जैसा कि माननीय जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल कोर्स को छोटा कर सकें और एम० बी० बी० एस० कोर्स छोटा करके

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जल्दी देहातों में डाक्टरों को भेज सकें। आज जो भी डाक्टर निकलते हैं वे देहातों में जाना नहीं चाहते। उनके रहने के लिये कोई इंसेंटिव नहीं है। उनके रहने के लिये कोई ठीक साधन नहीं है। एक ओर देहातों में एलोपैथिक डिसपेंसरीज खुल रही हैं लेकिन माननीय मंत्री जी यह बतलायें कि कितनी जगहों पर वहां डाक्टर हैं और कितनी जगहों पर नहीं। कितनों के पास बिल्डिंग्स हैं और कितनों के पास कंपाउन्डर्स हैं। मैं समझता हूं कि आज प्रांत में सैकड़ों ऐसे अस्पताल होंगे जहां पर एक न एक चीज की भारी कमी है। जिससे लोगों को अस्पताल के प्रबन्ध में विश्वास घटता चला जा रहा है। माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं अस्पताल के कर्मचारियों की दशा की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। वार्ड ब्वाय और मेल नर्सेज की अगर आप हालत देखें आज भुवाली जैसे सैनेटोरियम में जो कि अपनी सीट से खेला करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। न उनको इंक्रीमेंट मिलता है और न उनके नियमों में परिवर्तन ही हुआ है। कई साल से उनके डेप्यूटेशंस आ रहे हैं लेकिन उनकी दशा की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। पंचवर्षीय योजना में लखनऊ में एक होम्योपैथिक लेबोरेटरी खोलने की बात स्वीकृत की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि होम्योपैथिक दवाइयों के स्टैंडर्डाईजेशन के लिये वह क्या कर रहे हैं। शिकायत इस बात की है कि ९० फीसदी होम्योपैथ को इलाज नहीं आता लेकिन दवाइयों का स्टैंडर्ड भी तो नहीं है। प्रांतीय सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुदान मांग कर लखनऊ में एक होम्योपैथिक लेबोरेटरी खोलती जो प्रदेश की ही नहीं वरन सारे देश की जरूरतों को पूरा करती। मुझे भरोसा है कि अगले साल माननीय मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और होम्योपैथी, एलोपैथी आयुर्वेदिक के बीच जो संघर्ष है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। सारे देश में विवाद खड़ा हो उठा है कि कौन सी पद्धति अच्छी है। माननीय मंत्री जी जो कि कम्प्रोमाइज फारमूले पर कि एलोपैथी को भी ग्रांट दे दो, होम्योपैथी को भी ग्रांट दे दो और आयुर्वेद और यूनानी को भी ग्रांट दे दो काम कर रहे हैं ऐसा न करके एक निश्चित योजना प्रदेश के सामने रक्खें कि हम भारत की पुरानी मर्यादाओं के अनुसार आयुर्वेद और पुरानी यूनानी की भी उन्नति करेंगे और पाश्चात्य देशों से जो पद्धति मिली है उसकी भी उन्नति करेंगे। लेकिन कोई ऐसी स्कीम इस बारे में नहीं है। यह कह दिया जाता है कि फलां कालेज में लेक्चरर्स बढ़ा दिये गये लेकिन इतने से काम होने वाला नहीं है। इस मसले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये और अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पंचवर्षीय योजना की सफलता बड़ी बड़ी किताबों में यह लिख देने से नहीं होगी कि हम इतना खर्च करने वाले हैं या खर्च कर रहे हैं बल्कि इस बात में है कि आप में हिम्मत होनी चाहिये कि उस रुपये को इकट्ठा करके आप खर्च करें।

श्री अनवार सिंह (जिला मेरठ)---माननीय चेयरमैन महोदय, ये दो अनुदान जो सदन के सामने हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पूरे प्रदेश की आबादी से सम्बन्ध रखते हैं और मैं यह कहूंगा कि जो रुपया इन अनुदानों में रक्खा गया है वह बहुत थोड़ा है। यह अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी जिस सुचारू रूप से इस विभाग को चला रहे हैं वह प्रशंसनीय है। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा मुझे मेडिकल कालेज में जाने का अवसर हुआ और मैंने वहां खुद जा कर देखा। लखनऊ मेडिकल कालेज की जो प्रगति है वह बहुत प्रशंसनीय है। वहां मैंने कई पेशेंट्स से बातचीत की। उनसे मालूम हुआ कि वहां का इन्तजाम और ट्रीटमेंट, दवा और खाने का इन्तजाम एक ऊंचे पैमाने का है। यह बात देख कर मुझे खुशी हुई। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां भी अस्पतालों में ऊंचे दर्जे के औजार और आधुनिक इलाज करने के तरीके मुहइया हैं। उन पर बड़ा परिश्रम किया जा रहा है और व्यय किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि जहां तक जन स्वास्थ्य का सम्बन्ध है देहातों के लिये हमारी सरकार ने क्या किया। आज इस सदन के अन्दर पद्धति की बात कही जाती है कि एक पद्धति हो या दो पद्धतियां हों। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख होता है। देहातों में जहां कृषक रहते हैं पद्धति का तो वहां सवाल ही नहीं वहां डाक्टर्स कम्पाउन्डर्स और

मिडवाइव्स का भी प्रबंध नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी इस बात का भी प्रबंध कर रहे हैं कि हर जिले में एक्सरे का प्रबन्ध हो। इसके लिये मैं मानता हूं कि बड़े रुपये की जरूरत है लेकिन साथ ही इस बात को भी मानना होगा कि देहात का जो जनस्वास्थ्य है वह हमारी गिरफ्त के बाहर है। हमें इस ओर अपनी दृष्टि डालनी होगी क्योंकि काफी रुपया कृषकों से इस प्रदेश के रेवेन्यू में आता है और उनको यह भी सुभीता न हो कि वह अच्छी तरह से अपना इलाज करा सकें तो यह बड़े दुख कीबात है। हम देखते हैं कि बाज बाज जिलों के अन्दर ४०,४० मील तक कोई मेटर्निटी सेंटर्स, कोई मेडिकल हास्पिटल्स, औषधालय या दवाखाने नहीं हैं और उनको हर तरह की दिक्कत पड़ती है। क्या शहरों के अन्दर बीमारी होती है और देहात के अन्दर नहीं होती है। यह जरूर है कि वे लोग परिश्रम करते हैं और कम बीमार पड़ते हैं लेकिन वहां पर भी टी० बी०. के बीमार होते हैं। मैं गाजियाबाद तहसील का जिक्र करता हूं कि वहां पर गाजियाबाद तहसील के डासना परगना में एक भी दवाखाना, एक भी शफाखाना और अस्पताल नहीं है। वहां पर कोई मिडवाइफ नहीं है और दवाई भी वहां पर नहीं मिलती है। वहां का एरिया इतना low land है कि जिसकी वजह से वहां पर बीमारी होती है। कैनाल वाले वहां की कैनाल की ड्रेस की सफाई नहीं करते हैं। इस वजह से वहां पर बीमारी आती है। जनस्वास्थ्य के लिये सरकार की तरफ से कोई भी दृष्टि वहां पर नहीं डाली जाती है। बावजूद इसके कि बहुत लिखा पढ़ी की गयी लेकिन वहां पर कोई भी अस्पताल खोलने की योजना नहीं रखी गयी है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन शेष तीन साल के अन्दर हर ५ मील के अन्दर आप किस प्रकार से यह सेंटर खोल लेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि उनको मेरठ डिवीजन की तरफ ध्यान देना चाहिये। इस बात की जरूरत है कि वहां पर व्यवस्था इस बात की की जाय कि लोग अच्छा से अच्छा इलाज करा सकें।

जहां तक जिले का सम्बन्ध है वहां पर प्यारेलाल अस्पताल ही एक बड़ा अस्पताल है। वहां पर मैंने देखा है कि टी बी० वार्ड में पेशेंट्स के लिये ढंग से खाने का प्रबंध नहीं है। वहां पर देखा है कि अस्पताल में जो डाइट मनी उनको मिलता है वह बहुत थोड़ा है। इनडोर पेशेन्ट के लिये खाने का अच्छा इन्तजाम होना चाहिये। यह भी वहां पर देखा है कि मरीज बरामदे में पड़े रहते हैं। ५२-५३ में जो वहां पर रुपया खर्च किया गया था वह ९,५५३ खर्च किया गया था। अगर यह मरीजों की तादाद के हिसाब से देखा जाय तो वह पूरा नहीं है। अब आपकी यह लाल रोशनी हो गयी है। मुझे कई बात कहनी थीं लेकिन अब सिर्फ हवाला ही देता हूं। इसके अलावा जो वह वहां पर इनडोर पेशेन्ट रहते हैं उनके लिये जो वहां पर देखभाल करने के लिये लोग रहते हैं वह बरामदे में ही पड़े रहते हैं सर्दी के मौसम में उनको बड़ा कष्ट होता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बात का वह ध्यान करें और कोई व्यवस्था अस्पताल के अन्दर की जाय।

इसके अलावा एक लेडी अस्पताल मेरठ में है जहां पर केवल ४० बेड हैं। वहां पर कम से कम २०० बेड होने चाहिये। वहां पर भी यह देखा जाता है। कि जो मैटरनिटी केसेज होते हैं वह बरामदे में ही पड़े रहते हैं। वर्षा में भी वह वहीं पर पड़े रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरठ डिवीजन का दौरा करें और आकर स्वयं इस बात को देख सकते हैं। हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब भी उसी डिवीजन के रहने वाले हैं। वह इस बात का अच्छी तरह से परिचय करा सकते हैं।

श्री राम भजन शर्मा (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के सभी लोग इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश के अन्दर था उस समय मलेरिया, हैजा और चेचक इत्यादि बीमारियों का यह देश क्रीड़ास्थल बना हुआ था। जो लोग देहात के रहने वाले

[श्री रामभजन शर्मा]

हैं वह इस बात को जानते हैं कि वहां पर मलेरिया का कितना जोर था और हैजा का तो बढ़ समझा जाता था, लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश प्रगति करता जा रहा है उसी तरह से हमारे देश से यह बीमारियां बड़ी तेजी के साथ दूर होती जा रही हैं। हमारे देश में यों तो अभी इस प्रकार की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इसके लिये ज्यादा काम किया जाय लेकिन हमारे लिये और भी आवश्यकतायें हैं उन आवश्यकताओं के बीच में हमारे मंत्री महोदय ने जो सफलता अपने विभाग में प्राप्त की है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम यह देख रहे हैं कि जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेजी शासन था उस वक्त हमारे देश में अंग्रेजी दवाखानों और देशी दवाखानों की जो संख्या थी उससे आज ५ गुनी और ६ गुनी संख्या ज्यादा हो गयी है। हर तरीके से हमारे देश में इस ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। देहात में काफी कार्य हो रहा है लेकिन फिर भी और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उधर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं यह समझूंगा कि देश की ठीक तरह से सेवा नहीं हो पायी। लेकिन मुझे आशा है कि देहात की ओर और ज्यादा ध्यान दिया जायगा। शहरों के अस्पतालों में जो कमी हो वह पूरी की जाय लेकिन अधिक नये अस्पताल देहात में ही खोलने चाहिये। वहां प्रसूतिगृह कम हैं जिनके कारण हमारी माताओं और बहनों को बहुत कष्ट होता है। इससे सदस्यगण अच्छी तरह परिचित हैं। मैं चाहता हूं कि देहात में अधिक प्रसूतिगृह होने चाहिये। कई पद्धतियों की बात कही गयी लेकिन सरकार चाहे किसी को भी ज्यादा प्रोत्साहन दे यह तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस पद्धति को ज्यादा पसन्द करती है और जिसे जनता ज्यादा पसन्द करे उसी पद्धति को बढ़ावा देना चाहिये।

हमारे देश में इस समय स्वास्थ्य रक्षा का कार्य एक पेशे के तौर पर किया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी तक हमारे देश में जो कुछ प्रयत्न इस ओर किया जाता था वह निःस्वार्थ भाव से होता था। लेकिन जब से पेशे के तौर पर दवादारू होने लगी है तभी से मुसीबतें बढ़ गयी हैं। यह सरकार के करने की चीज नहीं है लेकिन मैं आपके द्वारा वैद्यों, हकीमों और डाक्टरों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि चाहे वह इस कार्य को पेशे के तौर पर करें लेकिन इसके साथ ही साथ सेवाभाव से भी दवादारू करें।

हमारे विरोधी दल के लोग हर प्रकार की नुक्ताचीनी सरकार की करते हैं लेकिन फिर भी कभी-कभी उनकी आलोचना में इस प्रकार की बातें हुआ करती हैं जिनमें कुछ तत्व होता है। लेकिन बाज मर्तबा इस तरह की बातें होती हैं कि वे हर अच्छाई को भी बुराई करने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य में काफी प्रगति हुयी है और हमें आशा है कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इस ओर और भी उन्नति होगी। लेकिन ज्यादा ध्यान देहात की ओर देने की आवश्यकता है। इसी से देश बलिष्ठ हो सकता है। हमारे देश में इस समय टी० बी० और कुष्ट जैसे भयानक रोगों का बढ़ाव है।

श्री गणेश प्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान के लिये अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जब यह विभाग गुप्ता जी जैसे कर्मठ व्यक्ति के हाथ में है तो यह काम आगे ही बढ़ेगा। लेकिन कई बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान दिलाना जरूरी होता है। बड़ी देर से इस बात पर बहस हो रही थी कि हमारे पास रुपया बहुत कम है और काम बहुत है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर इस काम में हमें और रुपया मिलता तो हम इस गाड़ी को और आगे बढ़ा सकते। लेकिन आप इस इतने बड़े देश के अन्दर हमें ऐसी इलाज की प्रथा सोचनी चाहिये जो बहुत खर्चीली न हो। जब हमारे पास पैसा कम है तो अवश्य ही हमें ऐसी प्रणाली को सोचना होगा जो सस्ती हो। जहां तक अंग्रेजी दवाखानों का सवाल है वे हमारे सूबे में ३४७ हैं। हो सकता है कि और भी बढ़ा दिये जांय लेकिन जितने गांव हमारे देश में हैं और जितनी आबादी हमारे देश की है उसके हिसाब से,

अंग्रेजी दवाखाने के हिसाब से, बजट बनाया जाय तो यह मुमकिन ही न हो सकेगा। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी अवस्था में हमें सस्ते किस्म का इलाज सोचना चाहिये। जहां तक मैंने देखा है होमियोपैथी सरीखा सस्ता इलाज हमारे सामने नहीं है। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि हमारे देश में एक ही तरह का इलाज कर दिया जाय लेकिन यह बात कोई समझ की नहीं मालूम होती। संसार के अन्दर अलग-अलग इलाज के तरीकों का ईजाद हुआ है और अनुसन्धान भी। हर तरीके के इलाज से लोगों को फायदा हो सकता है और होता है। इसलिये मैं यह नहीं कहता कि ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी इलाज के तरीकों को बंद कर दिया जाय लेकिन मेरा तो कहना यह है कि होमियोपैथी बहुत कम पैसे में ही चल सकती है और उतने कम पैसे में और कोई इलाज नहीं चल सकता।

दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों का आदि काल से संबंध चला आता है। हमारे यहां बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो खाने में बहुत ज्यादा लाभकारी हैं लेकिन लोग उनको नहीं खाते। इस खाने के मामले में बहुत भ्रम लोगों में फैला हुआ है। हमने देखा है देहातों में केरेमुआ का एक साग होता है जो बहुत ही फायदेमन्द है लेकिन लोग उसको फेंक देते हैं। इसी प्रकार से कहीं-कहीं सेम की फली का ऊपरी भाग खाते ही नहीं और केवल बीज ही खाते हैं। यह भी अजीब भ्रम है कि पूड़ी कचौड़ी और मिठाई खाने से आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है। मुझे जैसे अस्वस्थ आदमी को आप देखकर कह सकते हैं कि तुम स्वास्थ्य के बारे में कैसे बातें कर सकते हो? लेकिन यह सत्य है कि एक अस्वस्थ्य व्यक्ति ही भोजन के प्रयोगों से जान सकता है कि कौन चीज लाभकर है और कौन हानिकर। खाद्य पदार्थों के बारे में सरकारी ओर से प्रचार की आवश्यकता है।

अभी विरोधी दल के एक भाई ने कहा कि हमारे यहां मौतों की संख्या बढ़ी है। उन्होंनें खास तौर से चेचक से होने वाली मौतों के बारे में कहा। मैंने उसी समय अपने सामने जो किताब रक्खी थी उसको देखा और यह पाया कि सन् ५० और ५२ में जो आंकड़े बताये गये हैं उनमें बहुत फर्क है। सन् ५० में प्रतिहजार औसत जब कि १३.४९ था सन् ५२ में वह घट कर १०.७ रह गया है। इसके अलावा पैदाइश की संख्या सन् ५० में २१.०४ प्रति हजार थी और सन् ५२ का औसत १७.४२ है। चेचक से सन् ५१ में प्रति हजार .७७ मृत्यु हुई जो घटकर सन् ५२ में ·२९ रह गई। इन दोनों मामलों में हमारा प्रान्त बहुत आगे बढ़ रहा है। जहां तक आबादी का सवाल है मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब तक हमारे माननीय मंत्री जी है आबादी बहुत नहीं बढ़ सकती। क्योंकि स्वयं मत्री जी ने आबादी नहीं बढ़ाई। वह तो इस चक्कर में ही रहते हैं कि देश की आबादी बहुत न बढ़े और जो आंकड़े आपके सामने हैं उससे भी यह स्पष्ट दिया होता है।

अब मैं इलाहाबाद की दो एक बात कहना चाहता हूं। इलाहाबाद के अन्दर एक मेडिकल कालेज खोलने की बात थी और उसके लिये कई लाख रुपया रखा गया था लेकिन वह इस कारण टल गया था कि वहां कोई उचित जगह नहीं मिल रही थी। मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि अब वहां जगह मिल जायगी जहां कालेज खोला जा सके। अतः उसे खोलने की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त वहां एक टी० बी० का अस्पताल गैर-सरकारी तरीके से बन रहा था उसको उन्होंने देखा है और मेरा ख्याल है कि उसका जिक्र कार्य विवरण में है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये टी० बी० सेनिटोरियम का इंतजाम किया जायगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां टी० बी० सेनिटोरियम ऐसा बनाया जाय जो जनसाधारण के भी काम आ सके।

श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)--माननीय, मैं इन दोनों अनुदानों का समर्थन करता हुआ मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। यह अनुदान मनुष्य को जिन्दगी देता

[श्री शिव प्रसाद]

हैं। आज की इस बदलती हुई दुनिया में जब कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को झुकने की कोशिश कर रहा है, यह आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश को समृद्धिशाली, शक्तिशाली, बलशाली एवं हृष्टपुष्ट बनावें और मैं समझता हूं कि यह तभी सफल हो सकता है जब कि हम जनता के स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दें। मैं इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं करता कि हमारे मंत्री जी ने इस प्रदेश के स्वास्थ्य की ओर जो ध्यान दिया है वह यहां की जनता के लिये सौभाग्य की बात है। आये दिन कालाजार, तपेदिक, लकवा और मलेरिया के हजारों आदमी शिकार हुआ करते थे आज इन बीमारियों में शान्ति है। मैं देवरिया जिले में रहता हूं। देवरिया एक ऐसा जिला है जिसमें कुछ दिन पहले कालाजार तथा मलेरिया का भयंकर प्रकोप था लेकिन आज उसका प्रकोप शान्त है। मैं नहीं कहता कि पूर्ण रूप से शान्त है, क्योंकि हम लोग जब इस सदन में बोलते हैं तो जरा भी कोई बात हो तो हमारे विरोधी पक्ष के भाई उसका आसमान बना कर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं लेकिन मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि जहां तक प्लेग का ताल्लुक है, जहां तक मलेरिया और जहां तक हैजे का सम्बन्ध है, जब कि सलेमपुर तहसील और देवरिया तहसील में बैशाख के महीने में हर एक भाई घरों को छोड़ कर छोटी-छोटी मड़ैयों में शरण लेते थे लेकिन यह आज मंत्री महोदय की देन है कि वे किसी तरह से इनसे कुछ छुटकारा पा सके हैं लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाये हैं।

अब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह ऐसा क्षेत्र है जहां मजदूर लोग काफी मात्रा में रहते हैं, और जो आदमी मशीनों के सामने काम करता है यह स्वाभाविक है कि वह अस्वस्थ हो जाया करता है। कप्तानगंज, रामकोला तथा लक्ष्मीगंज की जो फैक्टरियां हैं उनमें मजदूर काफी काम करते हैं और वह प्रायः बीमार हो जाया करते हैं। थोड़ी सी दवाओं की व्यवस्था इन फैक्टरियों में अवश्य होती है लेकिन वह इतनी संतोषजनक नहीं है कि जिस पर हम सब्र कर लें। मैंने पारसाल भी माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि रामकोला ऐसी जगह है जहां दो-दो फैक्टरियों के बीच में लोगों को रहना पड़ता है और वहां की दूषित जलवायु की वजह से लोगों का स्वास्थ्य नष्ट होता रहता है। इसके साथ ही साथ बाढ़ की वजह से, ओला की वजह से और सूखा की वजह से जो प्राकृतिक विपत्तियां वहां मुंह बाये दौड़ती हैं उससे उनका स्वास्थ्य इतना कमजोर हो जाया करता है कि वे प्रायः बीमार बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में रामकोला में अगर एक अस्पताल का जन्म हो जाय तो देवरिया वालों के लिये यह एक बड़ा पुनीत कार्य होगा। अब मैं आपका ध्यान, हाटा तहसील में मथौली एक स्थान है जहां पर कि बेतिया स्टेट (बिहार) का एक अस्पताल था उसकी तरफ, दिलाना चाहता हूं। वहां पर डाक्टर, कम्पाउन्डरों तथा दवाइयों की व्यवस्था की जाय जिससे कि उस बिल्डिंग के इर्दगिर्द रहने वाली जनता का लाभ हो सके। वहां पर लोग काफी बीमारियों से परेशान हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान पूर्वी जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां प्रायः ऐसी बीमारियां हो जाया करती हैं जिनकी रोक-थाम के लिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान और कदम अभी आगे और बढ़ना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनके लिये अनुसंधान होने की बहुत आवश्यकता है। मेरा ख्याल है कि लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़ या ऐसे दूसरे बड़े शहरों में आज बीमारियों को अनुसन्धान की आवश्यकता नहीं है बल्कि देहाती क्षेत्रों के लिये अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है जहां कि गरीबों और मजदूरों के चेहरे और शक्ल से अन्दाज लगाया जा सकता है कि यहां के लोग इस रोग से पीड़ित हैं और उस रोग की व्यवस्था क्या हो सकती है। इसीलिये देहाती क्षेत्रों और खासकर देवरिया के लिये सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह विशेष रूप से ध्यान दे। हमारा

देवरिया जिला एक नया जिला है और जब कोई नयी चीज बनती है तो उसके लिये नये प्रकार की व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। देवरिया जिले में बहुत सी चीनी की फैक्टरीज हैं। इनसे लाखों रुपया सरकार को इक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होता है।

श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम अक्सर सरकार की तरफ से सुना करते हैं कि उसका मोटो 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख मनुभवेत्' हो। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग की जो पुस्तिका निकाली है उसमें आगे वर्ष के लिये जो योजना बनी है उस पर हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी की दृष्टि बड़े-बड़े शहरों के विद्युत प्रकाश और बड़े-बड़े जिलों के कोलाहल से आगे न बढ़ कर वहीं रह गई है और उन्होंने उन गन्दी झोपड़ियों और उन पिछड़े क्षेत्रों की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उन जिलों की तरफ नहीं दिलाना चाहता जहां कि उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी योजनायें जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद इन शहरों में ही जो कि सेन्टर हैं, खोल रक्खी हैं, वहां पर तो मेडिकल एड की व्यवस्था है ही, लेकिन मैं उन जिलों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि बहुत ही बैकवर्ड हैं और जिनकी ओर कदापि पहले ध्यान नहीं गया है और यहां पर बोलने वालों ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिलाया है। जैसे पश्चिम में मैनपुरी जिला है उसमें जसराना तहसील है वह बहुत पिछड़ी हुई है। उसकी आबादी लगभग २ लाख है लेकिन उस क्षेत्र में सिर्फ एक ही सरकारी अस्पताल है जो कि तहसील के हेडक्वार्टर से करीब २० मील की दूरी पर है। तहसील हेडक्वार्टर पर माननीय अधिष्ठाता महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक डिस्पेन्सरी है। उस डिस्पेन्सरी की हालत मैं क्या बयान करूं? वहां पर जो दवा दी जाती है वह उसी तरह की है जैसा कि माननीय सदस्य आपके सामने पहले बयान कर चुके हैं कि वहां पर लोगों को जो कि अधिकांश देहाती क्षेत्र से आते हैं दुआ का पानी दिया जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से दवाइयां मिला करती हैं उसे डाक्टर महोदय अपनी प्राइवेट अलमारी में बन्द कर लेते हैं और उससे अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस चलाते हैं। हमने अक्सर उन्हें इस तरह से करते हुये देखा है। दूसरी बात उनके विषय में यह भी है कि जब उनका इस तरह का व्यवहार है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी दवा से क्या लाभ हो सकता है। इसलिये जनता में एक भावना बन गई है कि जहां भी डाक्टर साहब जाते हैं या जिस रोगी को वह पकड़ते हैं वह अवश्य ही मर जाता है। इसलिये उनसे लोग इलाज नहीं कराते हैं। श्रीमान् जी, मैं आपका ध्यान इस तहसील की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह तहसील बहुत बड़ी है। इसमें दो एक कस्बे ऐसे हैं जहां पर अस्पताल की बहुत जरूरत है। एक स्थान एका है जो तहसील हेडक्वार्टर से बीस मील की दूरी पर है। इसकी आबादी देहाती क्षेत्र और कस्बे को मिला करके छै हजार के लगभग है। यहां पुलिस स्टेशन भी है और बिल्कुल इंटीरियर में पड़ता है। कोई भी मेडिकल एड की सुविधा वहां नहीं पहुंच सकती है। इसलिये जो सरकार की योजना दस नये आयुर्वेदिक और दस नये एलोपैथिक अस्पताल खोलने की है उसमें सरकार उस क्षेत्र का भी यदि ध्यान रखे तो बड़ी कृपा होगी। इसी तरह से एक स्थान खैरगढ़ है जो कि एक बड़ा कस्बा है। वहां पर भी किसी तरह का कोई प्रबन्ध नहीं है। लोगों ने वहां पर अपनी प्राइवेट दूकानें खोल रखी हैं और वह जनता को कुछ सुविधा दे सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि वे शहरों की तरफ तो ध्यान देते ही हैं और बजट का अधिकांश भाग उन्हीं क्षेत्रों में खर्च करते हैं, लेकिन यदि वे इधर भी ध्यान दें तो बड़ी कृपा होगी। एक बात यह कही जाती है कि हम जहां पर देहात में अस्पताल खोलते हैं, वहां डाक्टर

[श्री विष्णु दयाल वर्मा]

नहीं पहुंचते हैं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अधिकांश जो हमारे डाक्टर होते हैं वह शहरों के ही रहने वाले होते हैं और उनका देहाती क्षेत्र से कुछ भी सम्बन्ध न होने के कारण देहाती क्षेत्र का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। इसलिये जब वह अपनी एजूकेशन समाप्त करके देहात में जाते हैं तो उनको स्वाभाविक हिचकिचाहट होती है क्योंकि वे उस क्षेत्र के आदी नहीं होते हैं। इसलिये इस सिलसिले में मैं श्रीमान् का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि आगे के लिये जब मेडिकल कालेज के लिये कैंडिडेट्स सेलेक्ट किये जायं, तो देहाती क्षेत्रों का अवश्य ध्यान रखा जाय। इस तरह से जो स्टाफ निकलेगा उससे हमारे माननीय मंत्री जी को जो शिकायत रहती है और देहाती क्षेत्र में डाक्टर न पहुंचने के कारण जो असुविधा होती है वह भी दूर हो जायगी और देहाती क्षेत्र का रिप्रिजेंटेशन भी हो सकेगा। अधिकांश हमारे सूबे में आबादी देहाती क्षेत्रों की ही है। देहाती क्षेत्रों में ७५ फीसदी मनुष्य रहते हैं जो अक्सर खेती करते हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। उनका जीवन ऐसा है कि वह सड़े गले मकानों में रहते हैं और उनके मकानों की हालत अच्छी नहीं है। वह ऐसी झोपड़ियों में रहते हैं जहां गन्दगी रहती है। तो इस तरफ अगर हमारे माननीय मंत्री जी ध्यान रखेंगे तो उनको बहुत सुविधा होगी और जो उनकी योजना देश कल्याण की है वह भी अधिक सफल होगी।

दूसरी शिकायत यह भी की जाती है कि हमारे माननीय मंत्री जी अंग्रेजी दवाओं की तरफ अधिक ध्यान देते हैं और आयुर्वेदिक अस्पतालों पर कम रुपया खर्च करते हैं, उनके डाक्टरों की तनख्वाह या जो और खर्चे हैं उनको भी कम रखा जाता है। इस शिकायत का दूर करना भी माननीय मंत्री जी को उचित है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठाता महोदय, हमारे राज्य का पब्लिक हेल्थ और मेडिकल का जो बजट है वह हमारी बढ़ती आबादी और हमारे राज्य के विस्तार को देखते हुये बहुत कम है। श्रीमन्, वेस्ट बंगाल मद्रास, बम्बई जिनकी जन संख्या हमारी जन संख्या से कहीं कम है, करीब-करीब आधी है और जिनके रिसोर्सेज और टोटल बजट की आमदनी हमारे बजट की आमदनी से करीब-करीब आधी है उनके मेडिकल बजट और पब्लिक हेल्थ के बजट हमारे करीब बराबर हैं। हम सन् ४६ में जो फीसदी रुपया मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के ऊपर इस्तेमाल करते थे, श्रीमन् मुझे दुःख के साथ अर्ज करना पड़ता है कि आज भी हम वही रुपया मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे राज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुये हमारा मेडिकल बजट बहुत कम है; फिर मेडिकल शिक्षा के ऊपर मुझे आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से विशेष तौर से कुछ बातें कहनी हैं फोर्ड फाउंडेशन में एक्सचेंज आफ स्टूडेंट्स के हिसाब से जो विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां आते हैं और खोज बीन करते हैं उनकी खोज बीन पर मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जरा शंका की निगाह से देखें। वह हमारे यहां किन चीजों पर खोज बीन करते हैं? वह हमारे यहां ऐसे वाइरस पर खोज करते हैं जो हिन्दुस्तान में न कभी मिले और न पाये जाते हैं, बल्कि जिनका ताल्लुक अफ्रीका कोरिया और दूसरे बहुत दूर दूर वाले मुल्कों से होता है। लामोहाला बात यह है कि इन चीजों पर खोज इसलिये की जाती है कि अगर बदकिस्मती से अमरीका से हमारी डिफरेन्स आफ ओपीनियन कभी हो जाय तो उस जमाने में हमारी पापुलेशन किस वायरस के ज्यादा ससेप्टिबिल हैं, उस चीज की ज्यादा खोज बीन करते हैं ताकि जर्म वारफेयर हमारे खिलाफ कर सकें।

इसी तरीके से मेडिकल शिक्षा के बारे में भोर कमेटी के जो रेकमेंडेशन थे उनकी तरफ भी हमने कोई अमली क़दम नहीं उठाया है। भोर कमेटी में कहा गया था कि

हर मेडिकल कालेज के स्टूडेंट के ऊपर कम से कम १० अस्पताल की बेड्स होनी चाहिये तभी हम मेडिकल कालेज के लड़कों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं। और पूरे बजट का १५ फीसदी हमें खर्च करना चाहिये। श्रीमन्, इसके मुताल्लिक मुझे यह भी अर्ज करना है कि हमारे यहां डाक्टर ग्रेगरी एलेन को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसलिये बुलाया था कि वह मेडिकल कालेजेज और मेडिकल एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट दें। और श्रीमन् आपकी इजाजत से मैं उनकी कुछ राय आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि मंत्री जी उस ओर विशेष ध्यान दें। उन्होंने लिखा है कि :—

"Your excellent teachers are underpaid, handicapped and distracted by having too many students and too few assistants."

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहूंगा कि भोर कमेटी के रेकमेंडेशंस भी इन्हीं बेसिस के ऊपर हैं और मैं माननीय मंत्री जी का विशेष तौर से इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि हमारी मेडिकल नीड्स को खयाल में रखते हुये हमारी मेडिकल काबिलियत के स्तर को मेन्टेन करने के लिये यह आवश्यक है कि इन रेकमेंडेशन्स के ऊपर वह गौर करें और इनको अमल में लायें। आगे उन्होंने यह भी कहा है :—

"You have excellent and admirable men but the students by their work fill me with concern for the future."

यह है दशा हमारे मेडिकल एजुकेशन की, जिसके बारे में मुझे माननीय मंत्री जी का विशेष तौर से ध्यान दिलाना है। इसी तरीके से उन्होंने आगे यह भी कहा है :—

In the striking scarcity of young students who will succeed the present professors.

अगर हम अपनी हालत को नहीं संभालते हैं तो आगे चलकर हमारे प्रोफेसर्स की जगहें कौन आदमी लेंगे ? इसके लिये हमारे पास काबिल आदमी नहीं रहेंगे।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं मेडिकल कालेज की गिरी हुई हालत के ऊपर और वह यह है कि मैंने एजुकेशन के बजट के सिलसिले में यह भी कहा था कि लखनऊ मेडिकल कालेज के अन्दर जब तक डाक्टर्स को प्राइवेटली न दिखाया जाय तब तक किसी ग़रीब आदमी का ऐडमिशन नहीं होता है और मैंने इसी आशय की चिट्ठी भी पढ़कर सुनाना चाहा था, परन्तु समय की कमी के कारण पढ़ नहीं सका था, जो वहां के एक डाक्टर ने मेरे एक मित्र के पास भेजी थी जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि प्राइवेटली दिखा ले तब ऐडमिशन हो सकता है वरना महीनों लग जायेंगे। जिस दिन उस आदमी ने प्राइवेटली दिखा दिया उसी दिन ऐडमिशन हो गया और उससे पहले नहीं हुआ। वहां किसी ग़रीब आदमी की गुंजायश नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेडिकल कालेज के अफेयर्स पर खास तौर से तवज्जह दें और कम से कम ऐसा प्रबन्ध करें कि ग़रीब आदमियों की वहां गुजर हो सके।

इसके अलावा तिलहर डिस्पेंसरी की तरफ भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा जिसको उन्होंने पी० एम० एस० १ से पी० एम० एस० २ कर दिया है। यह हमारे साथ गैर इंसाफी है।

श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान पर कुछ कहने से पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने राज्य के करीब करीब हर हिस्से में जो बढ़ती हुई क्षय की बीमारी थी और टी० बी० के मरीज हुआ करते थे उसके प्रथम रोक थाम के लिये ही ऐसा जबर्दस्त आक्रमण किया कि

[श्री देवमूर्ति राम]

तीन महीने के बाद ही यानी सितम्बर से लेकर अक्टूबर तक बीमार रहने के बाद जो टी० बी० के मरीज हो जाया करते थे उनमें बहुत बड़ी कमी कर दी। जिस हैजे की बीमारी के नाम पर गांवों के लोग कांपते थे उस पर इतनी तेजी के साथ आक्रमण इन्होंने किया कि गांव में वह छूत की बीमारी करीब-करीब खत्म सी हो गई। और वह डर और वह हौआ गांव वालों के दिमाग से निकल गया है। प्लेग की बीमारी का तो इस तरीके से इलाज किया गया है कि करीब करीब उसका देश से निकाला या कालापानी हो गया है, यों कहना चाहिये। इस तरीके पर वह निकली कि दुबारा दिखाई नहीं दी। इसलिये हमारे मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही हमारे गांव के अन्दर महिलाओं की बीमारी की कोई रोक थाम नहीं हो रही थी उसके लिये भी अब कदम बढ़ाया गया है और तेजी से चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मंत्री जी इधर ज्यादा तवज्जह करेंगे और इसको आगे बढ़ायेंगे।

गांवों में जहां दवाओं का प्रबन्ध नहीं रहता था वहां आज दो तीन मील के सायरे में दवाखाने खुल गये हैं और गरीब गांव वाले दवाओं के उपलब्ध करने में आगे बढ़ रहे हैं। जहां डाक्टरों के नाम पर लोग शहरों का ही स्वप्न देखा करते थे वहां आज देहातों मे ऐलोपैथी के अस्पताल खुल गये हैं। इस तरह से गांव वालों की हिफाजत और बीमारी की रोकथाम की भरपूर कोशिश की गई है। जहां मैं अपने मंत्री महोदय को बधाई देता हूं वहां जो उनकी त्रुटियां हैं, खराबियां हैं, वह बतलाये बिना भी नहीं रह सकता हूं।

उन त्रुटियों के बारे में मैं मंत्री महोदय के कानों में बनारस की बातें डालना चाहता हूं। बनारस जिला बोर्ड छः वर्षों से कायम है। उसके दो अस्पताल शहरी इलाकों में चल रहे हैं। आज तक सालाना रिमाइंडर्स के बावजूद भी इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और देहाती पैसे का उपयोग शहरों में हो रहा है और शहर में अस्पताल चल रहे हैं और बार बार कहने के बावजूद भी वह अस्पताल अभी तक शहर में ही हैं और अधिकारी आनाकानी करते जा रहे हैं और इन अस्पतालों को देहात में ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं।

मैं देख रहा हूं कि बनारस जिले की भदोही तहसील में महाराजा साहब के जमाने से डिस्पेंसरी खुली हुई है, उनकी इमारत गिरती जा रही है, कोई मरम्मत नहीं हो रही है। छप्पर के नीचे अव्यवस्था की दशा में है और उधर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। मैं क्या बतलाऊं, धानापुर और गंगापुर में दो अस्पताल खोले गये हैं। कभी डाक्टर पहुंचता है तो कम्पाउंडर नहीं पहुंचता और जब कम्पाउंडर पहुंचता है तो डाक्टर नहीं पहुंचता। यह अव्यवस्था जारी है। बराबर लिखा पढ़ी होते हुये भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि १९५३-५४ में बीरांव गांव में अस्पताल मंजूर हुआ और वहां फरवरी में आर्डर पहुंचा कि ५ हजार रुपये में इक्विपमेंट खरीदा जाय। पता नहीं मार्च के आखीर तक खरीदा जायगा या नहीं; डाक्टर का पता नहीं, पहुंचेगा या नहीं। गांव वालों ने ४२,००० रु० लगाकर इमारत बनवाई है लेकिन यह अव्यवस्था है। ऊपर के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि उच्च अधिकारी इधर ध्यान दें।

श्री गोविन्द तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, आज से कुछ साल पहले हमारे देश में जब विदेशी हुकूमत थी सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग हैजे से, चेचक से और दूसरे इसी प्रकार के रोगों से मर जाया करते थे।

जब से हमारी सरकार ने शासन की बागडोर संभाली है उसने जहां दूसरे कार्य अपने हाथ में लिये वहां देश में लोग जिन रोगों से मर जाया करते थे उनको रोकने का भी प्रयास किया और मैं कह सकता हूं कि अपने सीमित साधनों के बावजूद भी और देश के बटवारे के कारण जो समस्यायें उसके सामने आयीं उनका सामना करते हुये भी उसने अल्पकाल में रोगों की जो रोकथाम की है और रोगों के कारण जो मृत्युएं होती थीं उनकी संख्या में कमी की है । उसकी जितनी प्रशंसा की जाय उतना कम है। अगर कोई सत्य को मानने से इन्कार कर दे या वास्तविक स्थिति को स्वीकार करने से इन्कार कर दे तब तो दूसरी बात है वरना इस सदन का शायद ही कोई माननीय सदस्य ऐसा होगा जो इस बात को मानने से इन्कार करे कि हमारी सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने और मंत्री जी ने सीमित साधनों के होते हुये भी जन साधारण के स्वास्थ्य में जो तरक्की की है, जो प्रगति की है वह सराहनीय है। मैं इस सफलता के लिये विभाग को तथा मंत्री जी को बधाई देता हूं।

जहां तक इस मद में रुपयों को कम करने का प्रश्न है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय देश के सामने आवश्यकता इस बात की है कि लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाय। देश में जो अन्न की कमी है, भुखमरी है, उत्पादन के साधनों तथा उत्पादित वस्तुओं की कमी है उसे दूर किया जाय इसलिये हमारी सरकार का इस समय प्रयास इस बात का है कि वह अधिक रुपया ऐसे निर्माण के कार्यों में लगाये जिससे देश की गरीबी दूर हो और आर्थिक अवस्था सुधरे। आवश्यकता अनुभव करते हुए भी वह अधिक रुपया इसमें नहीं रख पाती है। इस सम्बन्ध में स्वयं मंत्री जी ने कहा कि जो रुपया रखा गया है वह हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुये अपर्याप्त है। वह इसको भी मानते हैं कि रुपयों की कमी के कारण जितने हमारे प्रदेश के लिये अस्पतालों की आवश्यकता है उतने अभी वे नहीं बनवा सके हैं। लेकिन मैं तो केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी साधन और जितना भी रुपया उनके हाथ में है उनका सदुपयोग करने का उन्होंने प्रयास किया है।

पेय जल का स्वास्थ्य से घनिष्ट सम्बन्ध है। माननीय मंत्री जी को भी भली भांति विदित है कि पवतीय जिलों में पेय जल का कितना कष्ट है। इसलिये शासन संभालने पर सरकार ने बजट में इस बात की गुंजाइश रक्खी थी कि पर्वतीय जिलों के देहाती क्षेत्र में पानी की सुरक्षा के साधन मुहय्या किये जायं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना यह पड़ता है कि बजट में रुपयों के रखने के बावजूद भी पेय जल की योजनाओं को कार्यक्रम रूप में परिणित नहीं किया जा सका और इस प्रकार तीन चार लाख रुपया जब्त हो गया। होना तो यह चाहिये था कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों से पूछा जाता कि क्यों नहीं सब रुपयों को जनहित के लिये, पेय जल की सुरक्षा के साधनों में खर्च किया गया ? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने अच्छी तरह से इस कार्य को पूरा करने के लिये वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को सन् १९४८–४९ में यह हिदायत दी कि वे पर्वतीय जिलों के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनायें जिसमें पेय जल के लिये ऐसी व्यवस्था हो जिससे देहात के लोगों को पानी का कष्ट न हो। लेकिन उस बात को बीते हुये पांच वर्ष हो गये और मुझे जहां तक इल्म है अभी तक ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं आयी। सरकार अपने मातहतों से अपनी नीति को कार्यान्वित न करा सके और जो रुपये उसने बजट में रक्खे हैं उनको खर्च न करा सके इससे बढ़ कर उसकी कमजोरी की बात क्या हो सकती है। कोई भी हुकूमत जो अपनी नीति को कार्य रूप में परिणत न कर सके, जिन रुपयों को वह खर्च करना चाहती है उनको वह खर्च न करा सके, इससे बढ़कर उसकी दूसरी कमजोरी नहीं हो सकती। जिस जनतंत्र की बुनियाद पर हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसके

[श्री गोवर्द्धन तिवारी]

लिये भी यह घातक सिद्ध होगी। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह पर्वतीय जिलों में पेय जल की योजना के सम्बन्ध में फिर से गौर करें और इस सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स से उन्होंने क्या है उसकी उन्हें याददिहानी कराये और शीघ्र एक योजना बना कर उसके लिये रुपया स्वीकार करने की कृपा करें। मुझे इस बात का अफसोस है कि जो बजट आज हमारे सामने है उसमें पर्वतीय जिलों की पेय जल की योजना के लिये कुछ भी रुपया नहीं रखा गया है। इस विषय पर जो सरकारी रिपोर्ट है उनको देखने से पता चलता है कि इस समस्या की गहनता को सरकार बराबर महसूस करती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मद में सरकार ने रुपयों की क्यों कमी की, यह मेरी समझ में नहीं आया। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस मद में रुपया रखकर पर्वतीय जिलों में जो पेय जल का कष्ट है उसको दूर करने का प्रयास करें।

अल्मोड़े के पूर्वी हिस्से में करीब ५०–६० मील लम्बा चौड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक भी ऐलोपैथिक अस्पताल नहीं है। पिछले साल मैंने निवेदन किया था कि दन्या नामक स्थान पर माननीय मंत्री जी एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने का प्रबन्ध करें। वहां २५, ३० मील के घेरे में एक भी एलोपैथिक अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं और आपके जरिये मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस साल वे वहां एक एलोपैथिक अस्पताल अवश्य खोलने का प्रयास करें।

पर्वतीय जिलों में कुछ प्रमुख मार्ग ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक मुसाफिरों को पीने का पानी नहीं मिलता है।

अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया। आप कृपया बैठ जायं।

श्री गोवर्द्धन तिवारी—इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१२ मार्च, १९५४

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

जिला देवरिया में १-१२-५३ से २८-२-५४ तथा १-१२-५२ से २८-२-५३ तक होने वाले अपराधों का विवरण।

क्रम-संख्या	अपराध	१-१२-५३ से २८-२-५४ तक			१-१२-५२ से २८-२-५३ तक		
		रिपोर्ट की गई	जो अदालत में चल रहे हैं	जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई	रिपोर्ट की गई	जो अदालत में चल रहे हैं	जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई
१	चोरी ..	१४०	३२	३२	११६	२४	५९
२	डकैती ..	४	२	-	३	२	-
३	कत्ल ..	५	३	१	५	१	१
४	बलवा ..	१९	५	१	१९	१३	१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७३ पर)

पिछड़ी हुई जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण

१—प्राइमरी से लेकर अधिस्नातक कक्षाओं, अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्रवृत्तियां ।

२—पुस्तक क्रय करने के लिये आर्थिक सहायता ।

३—परीक्षा शुल्क के भुगतान में आर्थिक सहायता ।

४—टेक्निकल ट्रेनिंग सेन्टर, बख्शी के तालाब, लखनऊ में प्रवेश ।

५—इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समय पिछड़े वर्ग के प्रार्थियों के हित का ध्यान रक्खा जाता है ।

विधान भवन

पी० एस० यू० पी० ए० पी०-१६० एल० एं०-१९५४-८५०